SHORT DURATION DISCUSSION - *Contd.*

Rising prices of essential items - *Contd.*

श्री राम नाथ ठाकुर (बिहार) : आदरणीय उपसभाध्यक्ष महोदय, आपने महँगाई पर अल्पकालीन चर्चा करने का समय दिया है, उसके लिए मैं अपने दल की तरफ से और अपनी तरफ से आपको कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। महँगाई पर चर्चा के लिए 16 दिनों तक हाउस नहीं चला। मैं सरकार को बधाई देता हूँ और विरोधी पक्षों को भी बधाई देता हूँ कि आपस में मिल कर आज इस पर चर्चा करने का समय दिया गया है।

उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं समाजवादी विचार का आदमी हूँ। विरोधी पक्ष के जितने वक्ता बोले, मैं उनका सम्मान करता हूँ, और मेरे दिल में उनके प्रति बहुत श्रद्धा है, लेकिन महँगाई को रोकने के लिए जो सुझाव होने चाहिए, वे किसी माननीय सदस्य ने नहीं सुझाये। डा. राममनोहर लोहिया ने लोक सभा में कहा था कि जो सरकार महँगाई नहीं रोक पाती हो, नहीं घटा पाती हो, लेकिन जो दाम हैं, जो कि निश्चित हैं, उनको तो बाँधने का काम उसे करना चाहिए।

महोदय, मेरा एक सुझाव है। 'दाम बाँधो' नीति डा. राममनोहर लोहिया ने चलायी थी, उस नीति को लागू होना चाहिए। चावल, दाल, तेल, सब्जी पर जीएसटी लगा। मेरा सुझाव है कि आप विलासिता के सामानों पर जीएसटी लगाइए, लेकिन जो गरीब के लिए सब्जी, दाल, तेल, आटा है, इन पर आप नहीं लगाइए। ...**(व्यवधान)**... मैं सरकार से अनुरोध करना चाहता हूँ कि सरकार एक सर्वेक्षण करा ले।

4.00 P.M.

आज महँगाई पर जो चर्चा हो रही है, 16 दिनों तक सदन नहीं चला, तो इस सदन का तो कुछ मैसेज बाहर जाना चाहिए। सरकार यह सर्वेक्षण कराए, जाँच कराए कि सीमेंट की बिक्री में कमी आई या नहीं आई, गिट्टी की बिक्री में कमी आई या नहीं आई, बालू की बिक्री में कमी आई या नहीं आई, मजदूरों की मजदूरी में कमी आई या नहीं आई, कपड़े की कितनी दुकानें बंद हुईं, दवा की कितनी दुकानें बंद हुईं, कितने सैलून बंद हुए, कितने होटल बंद हुए - सरकार के द्वारा इसका एक आकलन होना चाहिए और यह निर्णय होना चाहिए कि यह महँगाई का एक कारण है।...**(समय की घंटी)**... सरकार 80 करोड़ लोगों को मुफ्त, निःशुल्क, बिना काम के अनाज दे रही है। यूक्रेन की लड़ाई हुई, वहाँ से जो लोग आए, नौजवान आए, उन सबको सरकार ने बुलाया। आप उनको बुलाने का खर्च देख लीजिए। कोरोना के कारण 2 वर्ष भारत वर्ष की क्या स्थिति थी सबको मालूम है। भारत सरकार ने बहुत हिम्मत से कार्य किया । अब दशहरा, दीवाली एवं छठ पर्व आने वाला है। परिवार के बच्चे कहते हैं कि हमें दशहरा आने पर अच्छा कपड़ा मिलना चाहिए, पत्नी कहती है कि मुझे अच्छी साड़ी मिलनी चाहिए, छठ पर्व की जो सामग्रियाँ हैं, वे अच्छी मिलनी चाहिए। क्या उस गरीब परिवार के गार्जियन सब पूर्ति कर देते हैं? वे नहीं करते हैं। इसलिए गरीब की सोच रखने वाले सब लोगों को मिल कर एक उपाय ढूंढ़ना चाहिए और उनको इससे निजात दिलानी

चाहिए। गरीबों के बीच ऐसा मैसेज जाए कि हमारे लिए सोचने वाला कोई है। अगर कोई सोचने वाला नहीं है, तो बनना चाहिए।

उपसभाध्यक्ष (श्री भुबनेश्वर कालिता) : ठाकुर जी, अब आप समाप्त कीजिए। आपका समय समाप्त हो गया है।

श्री राम नाथ ठाकुर : सर, आपने क्या कहा?

उपसभाध्यक्ष (श्री भुबनेश्वर कालिता) : चूँकि आपका समय समाप्त हो गया है, इसलिए अब आप अपना भाषण समाप्त कीजिए।

श्री राम नाथ ठाकुर : सर, मैं आपके आदेश का पालन करता हूँ और इन शब्दों के साथ अपना भाषण समाप्त करता हूँ कि आइए, हम सब शोषित, पीड़ित, दलित, लांछित के बारे में सोचने वाले लोग एकजुट हों और सरकार उसमें सहयोग करे। शोषित पर अन्याय नहीं हो, गरीब पर अन्याय नहीं हो - इसके बारे में सोचें, समझें। मैं अपने दिल से यह कहना चाहता हूँ कि दाम बंधना चाहिए, महँगाई आगे नहीं बढ़नी चाहिए। जय हिन्द, जय भारत!

उपसभाध्यक्ष (श्री भुबनेश्वर कालिता) : धन्यवाद। श्रीमती महुआ माजी।

श्रीमती महुआ माजी (झारखंड) **:** माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, आपका हार्दिक धन्यवाद कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। आज मेरी मेडन स्पीच है, इसलिए मैं विनम्र अनुरोध करूँगी कि मुझे कुछ अतिरिक्त समय उपलब्ध कराया जाए।

मैं धरती आबा बिरसा मुंडा जी के उस झारखंड से आई हूँ, जिस धरती के नीचे अकूत खनिज संपदा है - कोयला, लोहा, यूरेनियम, बॉक्साइट और न जाने क्या-क्या है! इन्हें पूरे देश को सप्लाई किया जाता है, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि उस धरती के ठीक ऊपर रहने वाले लोग बहुत गरीब हैं, अत्यंत गरीब हैं। आज हम अपनी माननीया राष्ट्रपति, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को लेकर गौरवान्वित महसूस करते हैं। आज पूरा आदिवासी समाज आपकी तरफ बहुत ज्यादा आशा से देख रहा है कि निश्चित रूप से, उनकी समस्याएं दूर होंगी। महोदय, मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर इस जीएसटी और महंगाई से कोई सबसे ज्यादा प्रभावित होगा, जिन पर इसका दुष्प्रभाव पड़ेगा, वह आदिवासी समाज ही है। इसमें सिर्फ झारखंड ही नहीं, बल्कि पश्चिमी बंगाल, छत्तीसगढ़, ओडिशा, बिहार और इनके जैसे जितने भी गरीब और आदिवासी बहुल प्रदेश हैं, वहाँ की तमाम महिलाओं, बच्चों और लोगों पर इसका प्रभाव पड़ेगा।

महोदय, चूँकि मैं महिला आयोग, झारखंड की अध्यक्ष रही हूँ और मुझे वहाँ कई सालों तक काम करने का अवसर मिला, इसलिए जो समस्याएं हैं, मैंने उन्हें ग्रास रूट लेवल पर देखा है, बहुत करीब से देखा है और उन्हें समझने की कोशिश की है। झारखंड और उस जैसे प्रदेशों की जो सबसे बड़ी समस्या है, वह माइग्रेशन की समस्या है। आप सभी जानते हैं कि वहाँ पर ह्यूमन ट्रैफिकिंग की समस्या कितनी बड़ी हैं। पन्ना लाल जैसे ट्रैफिकर्स, जो अभी जेल में है, उन्होंने सिर्फ

झारखंड से ही 15,000 लड़कियों की तस्करी की थी। वे लड़कियाँ क्यों अपना घर, माँ-बाप, गाँव छोड़कर दिल्ली, असम, हरियाणा, पंजाब और न जाने कहाँ-कहाँ जाकर मेहनत करती हैं? वे अपने घर से दूर, परिवार से दूर यहाँ दो पैसे कमाने के लिए आती हैं, क्योंकि वहाँ बहुत ज्यादा गरीबी है और अगर उन पर महंगाई की मार भी पड़ेगी, तो आप समझ सकते हैं कि उनका भविष्य क्या होगा। जब उन्हें ट्रैफिकर्स लेकर जाते हैं, तब वे उन्हें जिस काम के लिए बोलकर ले जाते हैं, वहाँ वही नहीं होता, बल्कि उनका शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, हर तरह का शोषण होता है। उनकी पीड़ा आप सभी जानते हैं। इसका प्रभाव हमारे देश के तमाम आदिवासी बहुल क्षेत्रों में होता है। आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश में कितने सारे आदिवासी बहुल क्षेत्र हैं। वहाँ पर तरह-तरह के आदिवासी हैं। हमारे झारखंड में 32 जनजातियाँ हैं, जिनमें से सात प्रिमिटिव ट्राइब्स हैं। वे इतने गरीब हैं कि अभी तक उनकी स्थिति नहीं सुधरी है।

महोदय, मैं यह भी कहना चाहूँगी कि जो अनसेफ माइग्रेशन है, उससे केवल महिलाएं या पुरुष ही नहीं, बल्कि बच्चे भी बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं। हम स्कूल की बात करते हैं, स्कूल के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर देने की बात करते हैं, किताबें देने की बात करते हैं, हम उनके लिए आंगनवाड़ी केन्द्र, मिड-डे मील की बात करते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि वहाँ पर कितने बच्चे जाते हैं? वे अपने माता-पिता के साथ दूसरे राज्यों में चले जाते हैं। उनका भविष्य अंधकार में है। उनका भविष्य कौन देखेगा? महोदय, ये सारी चीज़ें गरीबी और महंगाई की वजह से हैं। इस पर ध्यान देने की जरूरत है कि एक व्यक्ति अपना घर-गाँव छोड़कर क्यों जाता है।

महोदय, मैं आपको बता दूँ कि हमारा पठारी इलाका है, जहाँ पर सिर्फ बारिश के दिनों में ही खेती होती है। वहाँ पर बाकी महीनों में आजीविका का कोई साधन नहीं है। वह दुर्गम क्षेत्र है। वे शहर नहीं जा सकते हैं और वहाँ आना-रहना भी बहुत महंगा होता है, जिसकी वजह से उन्हें दूसरे राज्यों में जाना पड़ता है। वहाँ जाकर वे मजबूरी में काम करते हैं। ...**(समय की घंटी)**... उन्हें अनऑर्गनाइज्ड सेक्टर में ले जाया जाता है, जहाँ पर उन्हें पता ही नहीं होता है कि उनके मालिक कौन हैं। महोदय, यह मेरी मेडन स्पीच है।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): I will look into it.

श्रीमती महुआ माजी : जी, सर। महोदय, उन्हें अनऑर्गनाइज्ड सेक्टर में पता ही नहीं होता है कि उनके मालिक कौन हैं। वे एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह घूमते रहते हैं। जब उनके साथ दुर्घटना होती है, तब उन्हें पता ही नहीं होता है कि उनकी देख-रेख कौन करेगा। उनके लिए कोई बीमा पॉलिसी नहीं है, कुछ नहीं है और ऐसे लोगों की संख्या लाखों में है।

आपको पता होगा कि वहाँ पर डायन प्रथा है। मैंने डायन प्रथा के पीछे की वजह भी देखी है। डायन कौन घोषित करता है? डायन प्रथा में महिलाओं को टॉर्चर किया जाता है, उनके नाखून उखाड़ दिये जाते हैं, बाल नोच दिये जाते हैं, उन्हें मैला पिलाया जाता है, उन्हें पूरे गाँव में नंगा करके घुमाया जाता है। उन्हें ओझा, गुणी, भोक्ताइन डायन करार देते हैं। आखिर क्यों लोग ओझा, गुणी की बात सुनते हैं? वे उनकी बात इसलिए सुनते हैं, क्योंकि जब वे बीमार पड़ते हैं, तब वे गरीबी की वजह से डॉक्टर के पास नहीं जा सकते, उनकी फीस नहीं दे सकते, ऐसे में वे झाड़-फूंक करवाने के लिए ओझा, गुणी के पास जाते हैं। जब झाड़-फूंक करने के बाद भी कोई बीमारी

ठीक नहीं होती, तो वे गाँव की किसी महिला को तुरंत डायन घोषित कर देते हैं और कहते हैं कि इन बीमारियों और इनकी मौत की वजह यह डायन है। यूनिसेफ की रिपोर्ट कहती है कि डायन उन लोगों को ज्यादा बोला जाता है, जो कुपोषण की वजह से कुबड़ी हो जाती हैं, जिनकी खाल काली पड़ जाती है, चमड़ी सिकुड़ जाती है। जो महिलाएं देखने में वीभत्स हो जाती हैं, ऐसी महिलाओं को डायन करार देना बहुत आसान होता है। महोदय, जहाँ ऐसे गरीब लोग हैं, वहाँ महंगाई को बढ़ाना कितना अन्याय होगा, यह ज़रा सोचने की बात है। मान्यवर, आपको पता होगा कि बच्चे आजकल अपराधी हो रहे हैं, नक्सली गतिविधियों में शामिल हो रहे हैं। **...(व्यवधान)...** सर, मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि मुझे बोलने दिया जाए, क्योंकि छः साल में एक बार मुझे यह मौका मिलेगा। **...(व्यवधान)...**

उपसभाध्यक्ष (श्री भुबनेश्वर कालिता) : आपको छः साल में एक बार नहीं, बल्कि आपको और भी मौके मिलेंगे, लेकिन ऐसा है कि **...(व्यवधान)...**

श्रीमती महुआ माजी : सर, मैं रिक्वेस्ट करूँगी। **...(व्यवधान)...**

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): Please don't*...(Interruptions)...* Please don't*...(Interruptions)...*

श्रीमती महुआ माजी : सर, मैं एक बार रिक्वेस्ट करूँगी। **...(व्यवधान)...**

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): When the Chair is speaking, don't cross talk. *...(Interruptions)...*

श्रीमती महुआ माजी : सर, यह मेरी मेडन स्पीच है। **...(व्यवधान)...**

उपसभाध्यक्ष (श्री भुबनेश्वर कालिता) : आज आपकी मेडन स्पीच है, आज की स्पीच का समय हम एक-दो मिनट तो बढ़ा देंगे, लेकिन मेडन **...(व्यवधान)...** Whatever the Chair is saying, you have to listen. *...(Interruptions)...* It is not wrong. *...(Interruptions)...* Don't evaluate. आपको एक-दो मिनट हम दे देंगे, लेकिन अगर आज हम इसको 15 मिनट करेंगे, तो फिर इसको फिनिश नहीं कर पाएँगे। **...(व्यवधान)...** जो बड़ी पार्टीज़ हैं, जैसे, रूलिंग पार्टी है, कांग्रेस है, इनके स्पीकर्स भी हैं। **...(व्यवधान)...**

श्रीमती महुआ माजी : सर, यह मेरी मेडन स्पीच है। **...(व्यवधान)...**

उपसभाध्यक्ष (श्री भुबनेश्वर कालिता) : आप दो मिनट में खत्म कीजिए। **...(व्यवधान)...**

श्रीमती महुआ माजी : सर, समय थोड़ा सा और बढ़ा दीजिए। **...(व्यवधान)...**

उपसभाध्यक्ष (श्री भुबनेश्वर कालिता) : बस, दो मिनट। **...(व्यवधान)...**

श्रीमती महुआ माजी : बच्चे अपराधी होते हैं, नक्सली गतिविधियों में शामिल होते हैं, क्योंकि वे गरीब हैं। अगर वे अपनी सब्जियों को लेकर बाजार जाएँगे, तो उसके लिए उनके पास पेट्रोल के पैसे नहीं हैं। ऊपर से यह महँगाई! आप सभी यह समझ सकते हैं कि आज़ादी के बाद पहली बार खाद्यान्नों पर इतना ज्यादा टैक्स बढ़ा है या उनकी कीमतें बढ़ी हैं। ऐसी कई आदिम जनजातियाँ हैं, जिनके लोग कभी जवान नहीं होते। वे बचपन के बाद सीधे बूढ़े हो जाते हैं। जब आप 30-40 साल के व्यक्ति को देखेंगे, तो ऐसा लगेगा कि वे कितने बूढ़े हो गए हैं।

सर, आपको पता होगा कि हमारे देश में एक क्षेत्र के विकास की कहानी दूसरे क्षेत्र के विनाश की कहानी पर आधारित होती है। हमारे यहाँ कोयला, लोहा, बॉक्साइट, यूरेनियम और तमाम खनिजों का जो खनन होता है, उसका दुष्प्रभाव वहाँ के लोगों पर पड़ता है, जिसके लिए उनको अतिरिक्त पोषक खाद्य-पदार्थों की जरूरत होती है, लेकिन महँगाई की मार के कारण वे उन्हें नहीं ले पाते। लघु वनोपज, जिन पर आदिवासियों का अधिकार है, उसको भी वन अधिनियम के अंतर्गत लाकर उनका तरह-तरह से टॉर्चर होता है, जिसके कारण वे उन्हें भी नहीं ले पाते। आपको पता होगा कि खुखड़ी, रुगड़ा, घोंघा ऐसी चीज़ें हैं, जिनमें प्रोटीन होता है, लेकिन जंगल में भी कई जगहों पर जाना उनके लिए प्रतिबंधित हो गया है। उनको पोषक आहार नहीं मिलता है, जिसकी वजह से उनकी हेल्थ दिन-पर-दिन डाउन होती चली जा रही है।

सर, मैं आपको बता दूँ कि वहाँ से कोयला तो प्राप्त होता है, लेकिन केन्द्र सरकार की कोल कंपनियों के पास रॉयल्टी का जो 1,36,000 करोड़ रुपये बकाया है, वह केन्द्र सरकार हमारे राज्य को नहीं देती है और ऊपर से डीवीसी के 8,000 करोड़ रुपये वसूलने के लिए हमारी बिजली काट दी जाती है। **...(व्यवधान)...**

उपसभाध्यक्ष (श्री भुबनेश्वर कालिता) : धन्यवाद।

श्रीमती महुआ माजी : महोदय, मैं बस थोड़ा सा और बोलना चाहूँगी।

उपसभाध्यक्ष (श्री भुबनेश्वर कालिता) : नहीं, आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। For your information, let me just repeat it. शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन और कॉलिंग अटेंशन में मेडन स्पीच नहीं होती है। आप बाद में बोलिएगा। आपको बाद में मौका दिया जाएगा। अब आप समाप्त कीजिए।

श्रीमती महुआ माजी : सर, मुझे मेडन स्पीच का मौका मिलेगा?

उपसभाध्यक्ष (श्री भुबनेश्वर कालिता) : हाँ, बाद में मिलेगा। लेकिन, शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन और कॉलिंग अटेंशन में नहीं मिलेगा।

श्रीमती महुआ माजी : सर, मैं थोड़ा सा और बोलती हूँ।

उपसभाध्यक्ष (श्री भुबनेश्वर कालिता) : अब आप समाप्त कीजिए।

श्रीमती महुआ माजी : देखिए, हम एक तरफ जंगल काटने की बात करते हैं, तो 'उज्ज्वला योजना' के तहत आदिवासियों को जो सिलेंडर और गैस चूल्हा दिया गया, वह अब कबाड़खाने में पड़ा हुआ है। गैस की कीमतें इतनी महँगी हो गईं कि वे उसको खरीद नहीं सकते हैं।

महोदय, मैं सच कह रही हूँ और सच के बारे में प्रसिद्ध मार्क्सवादी विचारक Antonio Gramsci ने कहा था - "Telling the truth is always revolutionary." मुझे लगता है कि इस महँगाई के कारण से ही सोशल रिवोल्ट हो सकता है, क्योंकि इसका दूर-दूर तक असर पड़ता है। इसके परिणाम बहुत भयानक भी हो सकते हैं। अंग्रेज़ों के खिलाफ, जमींदारों और महाजनों के खिलाफ कई क्रांतियाँ हुई हैं। उन क्रांतियों में बिरसा मुंडा, सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव के साथ-साथ बहुत सारी महिलाएँ भी शामिल थीं, जिनमें सिनगी दई, कइली दई, फूलो और झानो आदि प्रमुख हैं। **...(व्यवधान)...**

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA)**:** The next speaker*...(Interruptions)...* अब मैं दूसरे स्पीकर को बुला रहा हूँ। **...(व्यवधान)...**

श्रीमती महुआ माजी : सर, दो मिनट। सर, आपको पता होगा कि ब्रिटिश पीरियड में बंगाल में भयानक अकाल पड़ा था।

उपसभाध्यक्ष (श्री भुबनेश्वर कालिता) : आप बाद में बोल लीजिएगा, आपको समय मिलेगा।

श्रीमती महुआ माजी : अमर्त्य सेन जैसे नोबेल लॉरिएट और इकोनॉमिस्ट ने कहा था कि ब्रिटिश शासकों की गलत नीतियों की वजह से वह एक मैन-मेड अकाल था। **...(व्यवधान)...** सर, मैं यह कहना चाहती हूँ कि वही बात यहाँ दोहराई जा रही है। **...(व्यवधान)...**

उपसभाध्यक्ष (श्री भुबनेश्वर कालिता) : अब आप बैठ जाइए।

श्रीमती महुआ माजी : अगर कीमतें कम नहीं की जाएँगी, तो जो हालत आज श्रीलंका की है, वही हालत हमारे देश की होने वाली है। **...(व्यवधान)...**

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA)**:** The next speaker is, Shri Abdul Wahab. *...(Interruptions)...* Not present. *...(Interruptions)..* Shri Birendra Prasad Baishya. *...(Interruptions)...*

श्रीमती महुआ माजी : सर, मुझे लगता है **...(व्यवधान)...** हमारे राज्य में जिस तरह से **...(व्यवधान)...** के लिए पैसे हैं, लेकिन हम गरीबों के लिए पैसे नहीं हैं, इसलिए इस पर ध्यान दिया जाए। **...(व्यवधान)...**

DR. M. THAMBIDURAI (Tamil Nadu): Sir, I have a point of order.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): Are you yielding? ...*(Interruptions)*... Under which Rule?

DR. M. THAMBIDURAI: It is regarding the procedure. We have four Members in our Party but they are not at all calling our name. I have requested them so many times. My name is not at all called.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): You may come in the Chamber. It will be discussed. You may show the rule. Your name is there. Now, Shri Birendra Prasad Baishya.

SHRI BIRENDRA PRASAD BAISHYA (Assam): Mr. Vice-Chairman, Sir, I thank you for allowing me to take part in today's Short Duration Discussion on price rise of essential commodities. The subject is very important. For the last 16 days, the House could not function discussing any Bill or any issue. As assured by the Leader of the House, the Parliamentary Affairs Minister, in consultation with the Opposition, time is allotted today to discuss this topic.

Sir, today, the world economy is passing through a critical time. Due to corona and Ukraine-Russia war, the world economy today is passing through a critical phase. Today, the growth percentage of a super power country like the USA is declined. The banking industry in China today is facing a serious threat due to non-payment by builders and real estate businessmen. In this critical time, due to corona and Ukraine war, inflation is at seven per cent in our country. No doubt it is high, but in this critical time, when the world is passing through critical economic times due to Ukraine war and corona, there is seven per cent inflation. Although it is high, yet I must compliment the Government that in this critical time, they have maintained it well. Sir, we should remember one thing. Under the leadership of Narendra Modi Government, now one ration card is issued in our country. One ration card is applicable in the entire country. It is really helpful to migrant workers. During the corona time, we have seen sufferings and problems of migrant workers. They walked hundreds of kilometres without food and water. But, after the 'One Nation One Ration Card' scheme is introduced by Narendra Modi Government, the migrant workers got benefit. Any worker, maybe from Kerala and moving to Assam, will get food in the State. I must give compliments to the Government. *(Time-bell rings)* Sir, the Government has given free food to 80 crore people. This is another wonderful job

done by our Government. Sir, I would like to say one thing because my time is very short.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): Please make it your last point.

SHRI BIRENDRA PRASAD BAISHYA: The inflation is 7 per cent due to food inflation and petroleum price rise. Now, in the entire world, food inflation has declined. Everywhere food inflation has declined today. We hope that very soon, under the leadership of this Government, inflation, food inflation, in our country would come down. We do not have a common tax structure for the petroleum products. For example, for diesel and petrol, the same price is not applicable in every part of India. In Delhi, the rate is different; in Maharasthra, the rate is different and in Kerala, the rate is different. The only one reason is that we do not have a common tax structure. I would like to request hon. Finance Minister to kindly introduce a common tax structure all over India to control the petrol price and diesel price; there should be a common price in every part of the India.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): Thank you.

SHRI BIRENDRA PRASAD BAISHYA: Sir, there is one more point about G.S.T. I have one request through this House and through you to the G.S.T. Council. Small tea grower in Assam and the North Eastern Region -- it is known to you, Sir -- plays a very important role in the socio-economical development of our region. Small tea grower is unemployed but by opening some small tea garden, they survive. They get their food, they get their house because they are surviving through the tea growth. So, I would like to request the G.S.T. Council to kindly consider withdrawing the G.S.T. against the small tea grower.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): Thank you. The next speaker is Dr. Sudhanshu Trivedi.

SHRI BIRENDRA PRASAD BAISHYA: Sir, with these words, I hope the Government would seriously consider it, especially, about the small tea growers of the North Eastern Region and the Government would withdraw the G.S.T. on the small tea growers. Thank you, Sir.

डा. सुधांशु त्रिवेदी (उत्तर प्रदेश) : उपसभाध्यक्ष महोदय, आज हम सब महंगाई के गंभीर विषय पर चर्चा करने के लिए यहां एकत्र हुए हैं। विगत कई दिनों के उग्र वाक्युद्ध के बाद आज यह चर्चा हो रही है और चर्चा के दौरान भी हमने देखा कि विपक्ष के कई सदस्यों का बड़ा आक्रोश, आवेग और नयनसुख की कथा, सभी चीज़ें व्यक्त की गईं, परन्तु अभी कुछ देर पूर्व एक दृश्य सदन में दिखा था, जब ऐसा लगा था कि वह नयन को सुख देने वाला नहीं था, क्योंकि विपक्ष की लगभग सारी सीटें खाली नज़र आ रही थीं। परन्तु अच्छा हुआ कि विपक्ष ने अपनी जगह पहचान ली और समय रहते हुए आंशिक रूप से उसकी भरपाई कर दी।...**(व्यवधान)**... अब मैं यह कहना चाहता हूं...**(व्यवधान)**... मैं विषय पर ही आ रहा हूं। विषय सुनने वालों के मन में विषय के प्रति कितना आगाध स्नेह था, यह उनके उस कार्य से दिख रहा था। अब मैं विषय पर आता हूं। महंगाई का विषय बहुत व्यापक है, इसलिए इसको गंभीरता और व्यापकता से समझने की आवश्यकता है। आज यह बताया जा रहा है कि महंगाई बहुत गंभीर स्थिति में है, परन्तु मैं याद दिलाना चाहता हूं कि 2019 का लोक सभा चुनाव एकमात्र ऐसा चुनाव था, जिसमें महंगाई मुद्दा नहीं थी। 2004 का लोक सभा चुनाव छोड़ दें, अन्यथा हर चुनाव में महंगाई मुद्दा होती थी। आज की महंगाई की हम बात करें, तो भारत में अगस्त महीने का जो रेट ऑफ इन्फलेशन है, वह 7.01 प्रतिशत है। अब यदि हमें महंगाई को पूरी तरह समझना है, तो थोड़ा इसको व्यापक रूप से समझना होगा।

(**सभापति महोदय** *पीठासीन हुए*)

महोदय, मैं अपने विपक्ष के सदस्यों से कहूंगा कि वे ज़रा इस बात पर मुलाहिज़ा फ़रमाएंगे कि इस समय विश्व में महंगाई की दर इटली में 7.9 प्रतिशत है, जर्मनी 7.5 प्रतिशत है, कनाडा में 8.1 प्रतिशत है, यूरोपियन यूनियन में 8.9 परसेंट है।...**(व्यवधान)**... मैं सोर्स के साथ बोलूंगा। ...**(व्यवधान)**...

MR. CHAIRMAN: Please. ...*(Interruptions)*... No running commentary. ...*(Interruptions)*...

डा. सुधांशु त्रिवेदी : यू.एस. में 9.1 परसेंट है, ब्रिटेन में 9.4 परसेंट है।...**(व्यवधान)**...

MR. CHAIRMAN: This will not go on record. ...*(Interruptions)*... Why are you wasting your energies? ...*(Interruptions)*...

डा. सुधांशु त्रिवेदी : स्पेन में 10.8 परसेंट है।...**(व्यवधान)**...

MR. CHAIRMAN: Please sit down. ...*(Interruptions)*... Sit down. ...*(Interruptions)*... What is the source of your raising this issue? ...*(Interruptions)*... No, no. ...*(Interruptions)*... No, no; it will not go on record. ...*(Interruptions)*... You are

wasting the time. ...*(Interruptions)*... We have hardly thirty-six minutes' time. ...*(Interruptions)*...

DR. SUDHANSHU TRIVEDI: Let me complete the sentence, Sir. ...*(Interruptions)*... चीन में 2.5 परसेंट है। चीन में इसलिए कम है, क्योंकि उनके कन्ज़्यूमर प्राइस इंडेक्स का क्राइटीरिया है, उसमें उन्होंने फूड और क्लोदिंग को ज्यादा महत्व दिया है। And the source for China is South China Morning Post. उन्होंने अपनी रिपोर्ट में इस बात को दर्ज किया है। अब मैं महंगाई की दर पर कुछ कहना चाहता हूं। आज यह कोई मुश्किल बात नहीं है कि दुनिया के अन्य देशों में महंगाई की दर क्या है, आप जाकर चैक कर लीजिए। भारत में महंगाई की दर 7 प्रतिशत है। दुनिया में 63 देश ऐसे हैं, जहां महंगाई की दर 10 प्रतिशत से ऊपर है। इतना ही नहीं है, बल्कि कुछ देशों में 50 परसेंट, 100 परसेंट और कुछ देशों में 200 परसेंट भी महंगाई की दर है। इसके बावजूद हमारे देश में 7 प्रतिशत महंगाई का रेट है। महंगाई है, मैं इससे इन्कार नहीं करता हूं। अब मैं आपको और भी सोर्स के साथ बताता हूं। समस्या इतनी भी व्यापक नहीं है। आप इसकी व्यापकता पर ध्यान दीजिए। विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अमेरिका, उसने पहली बार अपना स्ट्रेटेजिक ऑयल रिज़र्व खोला in order to curtail inflation, and the source is 23 नवम्बर, 2021 व्हाइट हाउस की प्रेस रिलीज़। बताइए, आपको ज्ञात इतिहास में ध्यान हो, हमारे विपक्ष में बहुत बड़े-बड़े विद्वान ज्ञाता लोग हैं, जब उन्हें याद हो कि अमेरिका ने महंगाई को नियंत्रित करने के लिए अपना स्ट्रेटेजिक ऑयल रिज़र्व खोला हो और उसे खोलने के बाद कितना अंतर आया है। अमेरिका के एनर्जी डिपार्टमेंट की प्रेस रिलीज़ 26 जुलाई, 2022 यह कहती है कि स्ट्रेटेजिक ऑयल रिज़र्व खोलने के बाद भी 40 सेंट पर गैलन ही कम हुआ है। यानी समस्या कितनी व्यापक और गहरी है, उसे समझने के लिए यह आवश्यक है...**(व्यवधान)**...साहब, मैं टू द प्वाइंट बोल रहा हूं। जब आप बात करने का प्रयास करते हैं ...**(व्यवधान)**...

श्री सभापति : आप उनसे आर्ग्यू मत करिए।

डा. सुधांशु त्रिवेदी : समस्या कितनी व्यापक है, उसको समझने का प्रयास कीजिए। ...**(व्यवधान)**...

श्री सभापति : आप उनसे आर्ग्यू मत करिए।

डा. सुधांशु त्रिवेदी : सब्जेक्ट है - महंगाई और मैं महंगाई की बात के संबंध में यह भी कह रहा हूं कि हमारे विपक्ष के सबसे प्रमुख नेता ने जिस धरती से जाकर ज्ञान दिया था, उस धरती में, ब्रिटेन में वह 9.4 परसेंट है। यह बताइए कि वहां से जाकर महंगाई की बात हमने की थी ...**(व्यवधान)**... हम विषय पर बात कर रहे हैं और इसलिए विषय पर बात कर रहे हैं, चूंकि आपने वहीं से जाकर महंगाई के बारे में सबसे पहले बताया। ...**(व्यवधान)**...

श्री सभापति : प्लीज़ ...**(व्यवधान)**...

डा. सुधांशु त्रिवेदी : अब मैं यह भी बताता हूं कि विश्व में महंगाई की यह समस्या सिर्फ इतनी नहीं है। ...**(व्यवधान)**...

श्री सभापति : यह रिकॉर्ड में नहीं जाएगा।

डा. सुधांशु त्रिवेदी : जी, मैं बिल्कुल बता रहा हूं। देश में ही नहीं, बल्कि दुनिया में भी क्या स्थिति है, यह समझने की जरूरत है। आप हमारे मकान की मजबूती की बात कर रहे हैं, तो ज़लजले पर भी नज़र डालिए। चाइना के अंदर भी, मीडिया में यह रिपोर्ट है कि कितने बैंक हैं, जिन्होंने अपनी पेमेंट डिफॉल्ट कर दी, उसका लोक सभा में वित्त मंत्री महोदया ने विवरण दिया है। हुनान प्रोविन्स में यह भी रिपोर्ट है कि बैंकों के बाहर टैंक लगाने पड़े। यानी विश्व में चारों तरफ अर्थव्यवस्था की यह स्थिति है और समस्या सिर्फ इतनी नहीं है। आज यह कहा जा रहा है कि हम लोग मंदी की तरफ जा रहे हैं। सभापति महोदय, महंगाई से बड़ा विषय मंदी का है। मैं इस पर सोर्स के साथ बोल रहा हूं कि ब्लूमबर्ग की भारत सहित पूरी दुनिया के देशों के बारे में मंदी की रिपोर्ट भी उपलब्ध है, जिसके अनुसार इस समय अमेरिका के मंदी में जाने की संभावना 38 प्रतिशत है, यूरोपियन यूनियन की 50 प्रतिशत है, चीन की 20 प्रतिशत है, ऑस्ट्रेलिया की 20 प्रतिशत है और साउथ कोरिया और जापान की 25 प्रतिशत है। ...**(व्यवधान)**...

MR. CHAIRMAN: Please. ...*(Interruptions)*... Then I have to call you, and name you and whoever makes running commentary. ...*(Interruptions)*... प्लीज़ इससे बचिए। मेरी सभी के लिए यह सूचना है। आप दूसरे के बारे में कमेंट मत करिए।

डा. सुधांशु त्रिवेदी : ब्लूमबर्ग के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था के मंदी में जाने की संभावना है - ज़ीरो परसेंट। ...**(व्यवधान)**... मैं विषय पर आ रहा हूं। मैं विषय क्यों बता रहा था? हमारी हालत तो यह है कि समुद्र में सुनामी आई हुई है, अगल-बगल के जहाज पलटे गिरे जा रहे हैं तथा हमारा कैप्टन कितनी सावधानी के साथ जहाज को लेकर आगे जा रहा है और ये कह रहे हैं कि अगल-बगल के पलटते जहाजों को मत देखो, हमारे जहाज पर आते हुए हिचकोले को देखो। मैं कहना चाहूंगा कि हमारे प्रधान मंत्री मोदी जी इस प्रकार की परिस्थितियों के आदी रहे हैं। विपक्ष चाहे जितने भी कांटे बिछाता रहे और कितनी भी विपरीत परिस्थितियां हों, मैं उनके लिए एक पंक्ति कहना चाहूंगा:

"वह पथ क्या पथिक कुशलता क्या, जिस पथ पर बिखरे शूल न हों,
नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धाराएँ प्रतिकूल न हों।"

इतनी प्रतिकूल धारा में हम अपनी अर्थव्यवस्था को कैसे आगे ले जा रहे हैं? अब अगली बात आती है कि डॉलर के मुकाबले रुपये की वैल्यू कम हो रही है। डॉलर के मुकाबले रुपये की वैल्यू क्यों कम हो रही है और वास्तविकता में रुपये की स्थिति क्या है, यह भी मैं आपको बताना चाहता हूं। प्रकाश जी ने इस समय, इस विषय का थोड़ा सा जिक्र किया कि चाइना की करेन्सी के

मुकाबले रुपया स्थिर है येन के मुकाबले रुपया बेहतर हुआ है, स्टर्लिंग पाउंड के मुकाबले स्थिर है और यूरो के मुकाबले थोड़ा इम्प्रूव हुआ है। आप सिर्फ अमेरिका केंद्रित मानसिकता से थोड़ा बाहर आइए, उसके बाद भी आपको दिखेगा कि वास्तविकता क्या है। महोदय, अमेरिका में भी डॉलर के मुकाबले हमारे रुपये की वैल्यू क्यों कम हो रही है? वह इसलिए हो रही है क्योंकि अमेरिका अपने डॉलर का मूल्य बढ़ा रहा है। महोदय, मैं फिर क्वोट कर रहा हूं, यह 27 जुलाई, 2022 की सीएनबीसी की रिलीज़ है, वह कहता है कि, Fed - Federal Reserve hiked the interest rate by 0.75 per cent point for the second consecutive term in order to contain inflation. वे अपनी महंगाई को बचाने के लिए लगातार दूसरी बार 0.75 परसेंट प्वाइंट की बढ़ोतरी कर रहे हैं, अतः आपको इस कारण से डॉलर के मूल्य में यह अंतर नज़र आ रहा है, इसीलिए चाहे येन हो, यूरो हो या स्टर्लिंग हो - वह अंतर नज़र नहीं आता है। भारत में हमने क्या किया? मोदी जी के नेतृत्व में निर्मला जी जो काम कर रही हैं, उसमें हमारी स्थिति क्यों बेहतर है, मैं उसका भी कारण बताना चाहता हूं। महोदय, उसका कारण यह है कि हमारे यहाँ महंगाई और विकास दर, ये दोनों इसलिए संतुलित हैं, क्योंकि हम विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में एकमात्र बड़ी अर्थव्यवस्था हैं, जिसका debt-to-GDP ratio सबसे कम है, जबकि बाकी सभी अर्थव्यवस्थाओं का debt-to-GDP ratio हंड्रेड परसेंट से ऊपर है।

महोदय, इतना ही नहीं, महंगाई को नियंत्रित करने के लिए यह जरूरी था कि हमारी पूरी अर्थव्यवस्था का एक मजबूत आधार हो और उस मजबूत आधार के लिए दि इकोनॉमिस्ट, जिन्होंने क्वोट करते हुए भारत के बारे में लिखा है कि पाँच प्रमुख कारण रहे, जिनकी वजह से भारत इस परिस्थिति में भी महंगाई और रिसेशन के दौर में नहीं जा पा रहा है। उन्होंने पहला कारण यह बताया कि हमने सिंगल मार्किट यानी जीएसटी क्रिएट किया। उन्होंने दूसरा कारण यह बताया कि expansion of the industry but with a shift towards renewable energy, सोलर एनर्जी से लेकर हाइड्रोजन एनर्जी तक के लिए क्या हो रहा है, वह हम सबको पता है, फिर moving of supply chains away from China, चूंकि आज चीन के अंदर जो हो रहा है, उस कारण से तमाम प्रोडक्ट्स की सप्लाई चेन पर प्रभाव पड़ रहा है, दुनिया के अन्य देश प्रभावित हो रहे हैं, परंतु भारत ने स्वयं को उससे बचाने में सफलता हासिल की है। And the prominent use of IT, हमने आई.टी. का जो यूज़ किया है, जन-धन, मोबाइल आदि कारणों से भी काफी हद तक गतिशीलता बनी हुई है। And, the high welfare society, इन विपरीत परिस्थितियों में गरीबों के लिए किस प्रकार से जन कल्याणकारी योजनाएं चलानी चाहिए - उस कारण से भी हमारी स्थिति अच्छी है और इसीलिए इंटरनेशनल इकॉनोमिक रेज़िलियेंस की रैंक में हमारा रैंक बढ़ने के बारे में यह भविष्यवाणी की गई है कि हो सकता है के जर्मनी और कनाडा के बाद अब भारत की सबसे बेहतर इंटरनेशनल इकॉनोमिक रेज़िलियेंस की दृष्टि से सेकंड रैंक पर पहुंचने की संभावना है। इस कारण से ..**(व्यवधान)**..

श्री सभापति : सुधांशु जी, आपका टाइम समाप्त हो रहा है।

डा. सुधांशु त्रिवेदी : सभापति जी, मुझे तो पंद्रह मिनट बताए गए थे।

श्री सभापति : आपको बताया है, लेकिन इसमें दस मिनट हैं। ..**(व्यवधान)**..

डा. सुधांशु त्रिवेदी : उसके बाद मैं यह बताना चाहता हूं - महोदय, मैं दो-तीन मिनट और लूंगा।

श्री सभापति : दो-तीन मिनट नहीं हैं, सिर्फ एक मिनट है। मुझे आपको पाँच मिनट देने में कोई आपत्ति नहीं है, मगर except BJP and Congress parties almost सबका समय समाप्त हो चुका है। कुछ पार्टियाँ सुबह नाम नहीं दे पाई थीं, वे अभी नाम दे रही हैं, इसलिए अगर एक-एक मिनट का समय देंगे, तो उसमें भी समय लगेगा।

डा. सुधांशु त्रिवेदी : सभापति जी, हमारे पूर्ववर्ती वक्ता ने अपना भाषण समय से पहले समाप्त कर दिया था।

श्री सभापति : ऐसा नहीं है।

डा. सुधांशु त्रिवेदी : सभापति जी, मैं जल्दी समाप्त करने का प्रयास करता हूं।

श्री सभापति : आप सामर्थ्यवान हैं, आपको प्रयास करने की जरूरत नहीं है। आप अपनी स्पीच दीजिए।

डा. सुधांशु त्रिवेदी : उसके बाद भी हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व इस समय ऑल टाइम हाई है, all time high foreign direct investment है। इसके बावजूद, यह भी यथार्थ है कि कुछ काम ऐसे हैं, जो सिर्फ केंद्र सरकार कर रही है, राज्य सरकारें नहीं कर रही हैं, जैसे 80 करोड़ लोगों को अनाज देना, सबको मुफ्त टीका लगवाना, चीन की सीमा के ऊपर भारी इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, क्योंकि वहाँ पर सामान्य रूप से कई गुना ज्यादा कॉस्ट आती है।

महोदय, मैं यहाँ पर भी कहना चाहूंगा कि अगर आप पूरे तरीके से, घर के अंदर भी एनालिसिस करना चाहें, तो हम यह भी बताना चाहेंगे कि इस समय कुछ राज्य ऐसे हैं, जिनकी परसेंटेज ऑफ इन्फ्लेशन राष्ट्रीय औसत से ज्यादा है। मैं अपने विपक्षी सदस्यों को बता देना चाहता हूं कि इसका Edelweiss source है। इनमें तेलंगाना है, जिसका 9.4 प्रतिशत है, बंगाल का 8.27 परसेंट है और राजस्थान का 7.36 प्रतिशत है। हम विराट दृष्टि से देखें या सूक्ष्म दृष्टि से देखें, हमें दोनों दृष्टियों से यह समस्या समझ में आ रही है, परंतु सभापति महोदय, मैं यह भी बताना चाहता हूं कि जब महंगाई की बात होती है, तो सिर्फ पिछली सरकार के ज़माने की बातें नहीं बताई जातीं, बल्कि हम लोगों से यह कहा जाता है - आज तो यू-ट्यूब पर लोगों के वीडियो भी खूब अवेलेबल हैं, ऐसा बताया जाता है कि पचास साल की सबसे बड़ी महंगाई, पचास साल की सबसे बुरी अर्थव्यवस्था। सभापति महोदय, मुझे याद आता है कि हम 2022 में हैं। ठीक 50 साल पहले 1972 में क्या था, आज रेट ऑफ ग्रोथ 8.5 परसेंट है और उस समय क्या थी-माइनस 0.55 परसेंट। केवल इतना ही नहीं था, याद करिये, उस समय रेट ऑफ इन्फ्लेशन कितना था, 16 परसेंट, 28 परसेंट का रेट ऑफ इन्फ्लेशन था, सन् 1991 में सोना गिरवी रखा गया। वे कहते हैं कि उससे बुरी स्थिति थी, इसलिए मेरा मानना है कि जो बातें कही जा रही हैं, वह यथार्थ पर कहें।

मैं समराइज़ करते हुए कहना चाहूंगा, हमारे विरोधियों में महंगाई को लेकर कितनी शिद्दत है। हमें ध्यान आता है, अभी कुछ दिन पहले कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक प्रैस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें जिक्र किया गया। एक साल पहले जयपुर में महंगाई के लिए एक रैली की थी, मगर उस रैली की महत्वपूर्ण बात यह है कि कांग्रेस के चिरयुवा नेता ने 10 मिनट हिन्दू बनाम हिन्दुत्व पर भाषण दिया था। यानी यह दर्शाता है कि दिल में क्या है और वास्तविकता में क्या है, परन्तु इससे मुझे एक बात याद आई। मुझे लगा कि उनकी सोच बहुत सही थी...**(व्यवधान)**...

MR. CHAIRMAN: Sudhanshuji, I have to call the other Member. ...*(Interruptions)*.. I am sorry. Please.

डा. सुधांशु त्रिवेदी : बस मैं समाप्त करता हूं।

श्री सभापति : हां, करिये।

डा. सुधांशु त्रिवेदी : बस दो लाइनों में समाप्त कर रहा हूं। याद करिये, जिस जमाने में उनकी लगातार सरकारें थीं तो रेट ऑफ ग्रोथ दो परसेंट था, जिसमें हम लोगों का मजाक बनाया जाता था, कहा जाता था कि यह दो परसेंट हिन्दू ग्रोथ रेट है और अब जो 8.5 परसेंट है, यह हिन्दुत्व का ग्रोथ रेट है। इसलिए यह अंतर है, जो इनको समझ में नहीं आता है।

अन्त में मैं सिर्फ यह कहना चाहूंगा कि तुलनात्मक दृष्टि से बहुत सारे आंकड़े थे, उनमें न जाते हुए, हां, शक्तिसिंह जी ने कहा कि ईमानदारी से स्वीकार करिये कि महंगाई है, हम कहते हैं कि हां, बिल्कुल है जनाब, मगर इस समय चमन में बहार का नहीं, ख़िजां का माहौल है, इसके बावजूद हमारे माली ने जिस ढंग से उसे सींचने का प्रयास किया है और आपने जो किया था, उसके संबंध में ये पंक्तियां कहते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। महंगाई को लेकर जनता को जो थोड़ा कष्ट हो रहा है, उसके प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए मैं कह रहा हूं:

'चमन को सींचने में पत्तियां कुछ गिर गई होंगी,
यही इल्जाम लग रहा है, हम पर बेवफाई का।
मगर कलियों को जिसने रौंद डाला, अपने हाथों से,
वही दावा करे हैं, अब चमन की रहनुमाई का।'

धन्यवाद।

MR. CHAIRMAN: Hon. Members, please. प्लीज़ सुनिये। If you are not interested, then I will call the Finance Minister and close the discussion. If you are not interested, if you don't have the patience to hear others and you become patient to make running commentary, I feel sorry for the same. There is also another wrong impression, I was watching sitting there that some Members are saying that it is our maiden speech. बी.जे.पी में 6 लोग कह रहे हैं कि हमारी मेडन स्पीच है। इसमें मेडन स्पीच होती नहीं। Please understand. शॉर्ट नोटिस डिस्कशन में और कॉलिंग अटेंशन में मेडन स्पीच नहीं होती। बजट

डिस्कशन में और लॉर्जर डिस्कशन जो होता है, उसमें मेडन स्पीच होती है। Please understand. मेडन माने, you have entered just now. Have patience, you have another five years and odd time. So, enough opportunities you will get. Please keep that in mind. Madam Rajani Ashokrao Patil.

श्रीमती रजनी अशोकराव पाटिल (महाराष्ट्र) : धन्यवाद, सर। बहुत दुख के साथ मैं अपना यह गहना पहन रही हूं। मेरा यह स्वभाव नहीं है कि मैं यह पहनूं, लेकिन जिन मध्यमवर्गीय महिलाओं को मैं रीप्रेज़ेंट करती हूं...**(व्यवधान)**...

MR. CHAIRMAN: Please. ...*(Interruptions)*.. This is not allowed. ...*(Interruptions)*.. Then I will have to call the other Member. ...*(Interruptions)*..

श्रीमती रजनी अशोकराव पाटिल : जिन मध्यमवर्गीय महिलाओं को मैं रीप्रेज़ेंट करती हूं...**(व्यवधान)**... * ...**(व्यवधान)**...

श्री सभापति : प्लीज़, यह तरीका नहीं है, हाउस में आकर यह अधिकार है क्या?

श्रीमती रजनी अशोकराव पाटिल : हां। ...**(व्यवधान)**...

श्री सभापति : नहीं। जरा इन्हें समझाइये। ...**(व्यवधान)**...

श्रीमती रजनी अशोकराव पाटिल : देश की 50 करोड़ महिलाओं को मैं यह दर्शाना चाहती हूं।...**(व्यवधान)**...

श्री सभापति : यह रिकॉर्ड पर नहीं जाएगा।...**(व्यवधान)**...* यह रिकॉर्ड में नहीं जाएगा। नहीं दिखाएंगे। ...**(व्यवधान)**...Then I will have to call the other Member. Ranjeet Ranjanji. ...*(Interruptions)*.. No exhibition of articles is allowed inside the House. ...*(Interruptions)*.. That is very clear in the rules. ...*(Interruptions)*.. There are precedents and there are a number of rulings.

श्रीमती रजनी अशोकराव पाटिल : ठीक है। मैं इसको दिखाना चाहती हूं, यह महिलाओं की परेशानी है। ...**(व्यवधान)**...

श्री सभापति : इसको दिखाना नहीं, अगर किसी ने देखा है तो वह भी भूल जाइये। ...**(व्यवधान)**... No you have to remove that and speak and utilize your time. ...*(Interruptions)*.. You have already done it. ...*(Interruptions)*..

---

* Not recorded.

श्रीमती रजनी अशोकराव पाटिल : लेकिन मैं यह दिखाना चाहती हूं कि यह महंगाई है।

श्री सभापति: ऐसा मत करिये। Otherwise, I have to call the next speaker. ...*(Interruptions)*.. The next speaker is..

श्रीमती रजनी अशोकराव पाटिल : अभी हमारे भाई भारतीय जनता पार्टी के सुधांशु त्रिवेदी जी ने इंटरनेशनल भाषण किया और देश और प्रदेश की भाषा उन्होंने बताई। मैं इसीलिए थोड़ा सा व्यथित होकर यह गहना पहन रही थी, क्योंकि मैं इस देश की मध्यमवर्गीय महिलाओं को रीप्रेज़ेंट करती हूं। मैं आपके द्वारा इस देश को और इस सभा गृह को यह बताने की कोशिश कर रही थी कि इस देश की जो महिला है, वह आक्रोशित है, वह बहुत व्यथित है। जिस तरह से महँगाई बढ़ रही है, हमें आपके बड़े-बड़े आँकड़े नहीं पता होते हैं, हमें नहीं पता होता है कि आप किस तरह से कौन सी भाषा बोल रहे हैं, लेकिन हमें यह मालूम है कि सरकार जिस तरह से गुमराह करने की कोशिश कर रही है, हम उसके लिए चंद लाइनें बताना चाहते हैं।

" सरकार कहती है 'सब चंगा सी',
लेकिन धरातल पर है त्राहि-त्राहि।

आँकड़ों को कर अनदेखा,
जनता से छुपाते सच्चाई,
खुद को बड़ा बता तथ्य से,
झूठी उम्मीदें हैं बँधाई।

महँगाई कर चरम सीमा पर,
चला दी देश में तानाशाही,
गरीब का आँसू पलकों पर सूखा,
सरकार का व्यवहार है रूखा-रूखा,
सुविधाएँ मिलतीं बस मित्रों को,
आम जन रोज रोता है भूखा।

वे कहते हैं मंदी का सवाल नहीं" --
अभी हमारे मित्र के द्वारा मंदी के लिए बताया गया --

"वे कहते हैं मंदी का सवाल नहीं,
पर असलियत में जनता का ख्याल नहीं,
महँगाई अब बड़ी, ज़िन्दगी है छोटी,
भाजपा के राज में न मिलती गरीब को रोटी।"

सर, मैं इसके साथ ही शुरू करना चाहती थी। सर, आज आप इस कुर्सी पर बैठे हैं, मुझे मन से बहुत अच्छा लग रहा है कि आप मेरा भाषण सुनने के लिए यहां बैठे हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरे मन की बात सुनने के लिए आप यहाँ हैं। सही में यह मेरे मन की बात है। ...**(व्यवधान)**...

श्री सभापति : प्लीज़, प्लीज़।

श्रीमती रजनी अशोकराव पाटिल : सर, मानसून सत्र शुरू होने के बाद लगातार हम चाह रहे थे कि सरकार हमारे मन की बात सुने। हम कांग्रेस पार्टी और विरोधी पार्टियों की तरफ से 9-10 दिन से बार-बार कोशिश कर रहे थे कि आज की तारीख में अगर कोई जरूरी बात है, महत्वपूर्ण बात है, देश के लिए बहुत ही आवश्यक बात है, तो वह है महँगाई। महँगाई की बात, हमारे देश की बात आप लोग सुनें और भारत के जो सर्वोच्च सभा गृह हैं, राज्य सभा और लोक सभा, उनके माध्यम से, आपके माध्यम से हमारे प्रधान मंत्री जी और सभी सुनें। जब यह महँगाई डायन खा रही है, तब देश का दुख आप सुनें, लेकिन इसकी भाषा सुनी नहीं गई और उल्टा जब हमारे नेता, हमारे जयराम रमेश जी हों, हमारे वेणुगोपाल जी हों, हमारे विपक्ष के नेता, खरगे जी हों, हर रोज़ रूल 267 के नोटिस देते रहे, लेकिन एक बार भी वह नोटिस एक्सेप्ट नहीं किया गया और सर्वोच्च सभा गृह में हमें अनुमति नहीं दी गई। जब मैं संसद अटेंड करने के लिए यहाँ के लिए निकली, तो मराठवाड़ा में हमारा बहुत छोटा डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ के सभी पत्रकारों ने हमें कहा कि ताई, आप जा रही हैं न, तो हमारा जो महँगाई का मुद्दा है, आप पहले वह उठाना। मैं यह इसलिए नहीं बोल रही हूँ कि हम कुछ बड़े हैं, बल्कि मैं यह इसलिए बोल रही हूँ कि यह इतने छोटे स्तर तक पर्कोलेट हुआ है कि लोग बोल रहे हैं कि महँगाई का मुद्दा उठाओ। इसका मतलब यह है कि महँगाई लोगों के लिए कितनी पर्कोलेट हो गई है। इस कमरतोड़ महँगाई ने अगर किसी को सबसे ज्यादा उछाला है, अगर किसी को सबसे बड़ा दुख दिया है, तो महिलाओं को दिया है। इसने इस देश की आधी आबादी, जो महिलाएँ हैं, उनको सबसे ज्यादा परेशान किया है। सब्जियाँ महँगी, किताबें महँगी, स्कूल आने-जाने का यातायात महँगा, गैस महँगी, किराना सामान महँगा। इतना ही नहीं, जिस 'उज्ज्वला योजना' का अभी ज़िक्र हुआ था, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि 'उज्ज्वला योजना' का यहाँ पर जो ज़िक्र किया गया, सर, आप सीएजी की रिपोर्ट देखिए, सीएजी की रिपोर्ट के अनुसार 'उज्ज्वला योजना' के तहत जो 65 परसेंट गैस सिलिंडर्स दिए गए, महिलाएँ उन्हें यूज़ ही नहीं करतीं, क्योंकि सिलिंडर का रेट एक हजार रुपए से ऊपर चला गया है। इसलिए 'उज्ज्वला योजना' का उपयोग ही नहीं हो रहा है। सर, 1 मार्च, 2014 को जिस एलपीजी की कीमत 410 रुपए होती थी, 1 अगस्त, 2022 को उसी एलपीजी की कीमत 1 हजार 3 रुपए हो गई। अप्रैल, 2011 में कच्चे तेल की कीमत 150 डॉलर प्रति बैरल थी, उस समय उसकी रिटेल कीमत 58 रुपए 50 पैसे होती थी, जबकि जुलाई, 2022 में उसी कच्चे तेल की कीमत प्रति बैरल 96.96 डॉलर प्रति बैरल हो गई, लेकिन प्रति लीटर पेट्रोल की कीमत बढ़ गई और 96 रुपए 20 पैसे हो गई। अगर राइज़िग फूड प्राइसेज़ बताया जाए, तो एडिबल ऑयल 18 परसेंट बढ़ गया है, मस्टर्ड ऑयल 28.66 परसेंट बढ़ गया है, रिफाइंड ऑयल 19 परसेंट बढ़ गया है, पोटैटो, जिसकी माला अभी हम

पहन रहे थे, 20.42 परसेंट बढ़ गया है, टोमैटो 18.54 परसेंट बढ़ गया है, ब्रिंजल, सबसे ज्यादा 27.72 परसेंट बढ़ गया है। लेडीफिंगर 11 परसेंट, पीज़ 11.16 परसेंट और व्हीट 7.77 बढ़ गया है।

सर, सरकार अपना खजाना भरने पर तुली है, लेकिन लोगों की जेबें खाली हो गई हैं। जब महंगाई की बात निकली है, तो मुझे 1998 का अनियन इलेक्शन याद आ गया। मैं उसे अनियन इलेक्शन इसलिए बोल रही हूं, क्योंकि तब दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और श्री साहिब सिंह वर्मा यहां के मुख्य मंत्री थे, जब यहां पचास रुपये किलो प्याज हो गया था, तब उन्होंने यह बयान दिया था कि कोई गरीब वैसे भी प्याज नहीं खाता है। हमारे अर्थ मंत्री जी ने भी ऐसा ही बयान दिया था, जब प्याज का विषय आया था। यह बयान देने के बाद 15 साल के लिए दिल्ली से बीजेपी गायब हो गई थी और श्रीमती शीला दीक्षित दिल्ली की मुख्य मंत्री बनीं, अगर आपको याद हो।

सर, यूपीए के कार्यकाल में सोनिया गांधी जी ने एक प्रण लिया था कि यूपीए की सरकार आई है, तो हम किसी भी व्यक्ति को भूखा नहीं सोने देंगे और सोनिया जी ने उस प्रण के मुताबिक फूड सिक्युरिटी एक्ट लागू किया, यह बात मैं बहुत अभिमान से कहना चाहती हूं।

इसके अलावा 'मनरेगा' भी एक ऐसी स्कीम है, जिसका आप कोई भी नाम रखें, कोई इसके बारे में कुछ भी कहे, लेकिन 'मनरेगा' की स्कीम के तहत आज हम इतनी बड़ी महामारी से पार पा गये, हम कोविड-19 की महामारी से निकल गये, 'मनरेगा' ने हमें बचा लिया।

महोदय, अब मैं जीएसटी की बात करूंगी। मैडम, कल आपकी लोक सभा में दी गई स्पीच सुनने के बाद मेरे मन में कुछ प्रश्न उठे हैं और मैं उन्हें यहां उद्धृत करना चाहती हूं। जब आपने बोला कि ब्रांडेड और लेबल्ड, प्री-पैकेज्ड और लेबल्ड से अलग है। पहले बड़ी कंपनियों के प्रोडक्ट्स प्रभावित होते हैं, जिनकी कीमत अधिक होती है। इनके खरीदार मध्यम एवं उच्च मध्यम वर्ग के होते हैं। दूसरा यह छोटे व्यवसायों को प्रभावित करता है, जिनके प्रोडक्ट्स के खरीदार निम्न आय वर्ग के लोग होते हैं।

आपने बोला कि उस मीटिंग को सबने अटेंड किया था। मीटिंग अटेंड करने वाले पश्चिमी बंगाल के वित्त मंत्री जी ने यह बताया था कि वह बैठक वर्चुअल थी और इसमें मुलाकात फेस-टू-फेस नहीं हुई थी और न ही उन्होंने व्यक्तिगत रूप से सलाह-मशविरा किया था। पश्चिमी बंगाल के वित्त मंत्री जी ने दावे के विपरीत यह भी कहा था कि इस मीटिंग में मौजूद कुछ सदस्यों ने फिटमेंट कमेटी की उस रिपोर्ट का विरोध किया था, जिसमें जीएसटी के रेट में वृद्धि की सिफारिश की गई थी, उसका उन्होंने विरोध किया था। शायद इसलिए अपना रुख बदलते हुए सरकार और वित्त मंत्री ने सर्वसम्मति की जगह 'आम राय' शब्द का इस्तेमाल किया।

गरीब उपभोक्ताओं को प्री-पैकेज्ड और लेबल वाले सामान खरीदने की इच्छा क्यों नहीं रखनी चाहिए। मैडम ने जो लूज़ सामान के बारे में बोला, जो गरीब लोग हैं, क्या उन्हें प्री-पैकेज्ड और लेबल वाले सामान नहीं खरीदने चाहिए? स्वच्छता से पैक किये गये सामान को खरीदने की इच्छा रखने वाले लोगों को मोदी सरकार क्या सजा देना चाहती है? मान लेते हैं कि प्री-पैकेज्ड सामानों में कुछ इनपुट टैक्स हैं, क्या उत्पादकों और विक्रेताओं के लिए प्री-पैकेज्ड और लेबल वाले सामानों पर जीएसटी लगाने की मांग की गई थी? क्या छोटे व्यवसायी, दुकानदार उपभोक्ता सभी स्टेकहोल्डर्स रिवाइज्ड जीएसटी रेट के खिलाफ असंतोष व्यक्त करते हैं?

सर, मैं यहां एक मुद्दा और रखना चाहती हूं कि 'अमूल' दूध की फैक्टरी, जिसकी स्थापना श्री वल्लभभाई पटेल ने की थी, 'अमूल' हो या 'गोकुल' हो, इनकी सहकारी संस्था है, जिसे किसानों ने खड़ा किया है। यदि आप इनके ऊपर जीएसटी लगाओगे तो आप इस देश में किसानों को क्या संदेश देना चाहते हैं?

श्री सभापति : रजनी जी, आपके बाद रंजीत जी को बोलना है, उनका समय जा रहा है।

श्रीमती रजनी अशोकराव पाटिल : जब सीपीआई इन्फ्लेशन सात परसेंट से अधिक है, जब डब्ल्यूपीआई इंफ्लेशन 15 परसेंट से अधिक है, बेरोजगारी चरम पर है, रुपया निचले स्तर पर है, चालू खाते का घाटा बढ़ रहा है और दुनिया भर में महंगाई बढ़ने की आशंका है, ऐसे समय में टैक्स बढ़ाना क्रूरता है और दूसरा कुछ नहीं है।

हम हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि महंगाई कम करिये, लोगों को इससे बाहर निकालिये। मैं सरकार और वित्त मंत्री जी से कहना चाहती हूं कि इसमें राजनीति नहीं लाते हुए लोगों के साथ, खास तौर से महिलाओं के साथ जन्म से लेकर, दूध से लेकर श्मशान घाट तक जो महंगाई बढ़ाई है, उसे कम करने की आवश्यकता है, धन्यवाद।

श्री सभापति : आप पूरा प्रयास और पूरी तैयारी करके आईं, आपने एक मिनट टाइम वेस्ट किया और आप कह रही हैं कि बाहर महंगाई बढ़ रही है, जबकि आप वह पहनकर आईं, तो महंगाई कम है या ज्यादा है? ऐसा क्यों?

श्रीमती रजनी अशोकराव पाटिल : सर, मैं उदाहरण देना चाहती थी।

MR. CHAIRMAN: You have come prepared. Utilise the time.

श्रीमती रजनी अशोकराव पाटिल : सर, मैं दिखाना चाहती थी। ये बोलते थे। मैं सही संवेदना व्यक्त करना चाहती हूँ।

श्री सभापति : नहीं। संवेदना के लिए बहुत अवसर हैं। लोगों में जाकर उनको जागृत करना, मेहनत करते रहना। **...(व्यवधान)...**

श्रीमती रजनी अशोकराव पाटिल : सर, **...(व्यवधान)...**

श्री सभापति : प्लीज़। कमेंटरी मत करिए। Particularly when the Chairman says something, don't get ...*(Interruptions)*.. Mr. Raghav, you have one minute's time. ...*(Interruptions)*.. Make it two minutes. ...*(Interruptions)*.. What can I do? Your Leader has taken more time. ...*(Interruptions)*.. Okay. Then, Shri Jose K. Mani. ...*(Interruptions)*..

श्री संजय सिंह : सर, राघव जी का मैडन स्पीच है। **...(व्यवधान)...**

MR. CHAIRMAN: I have already told you, no Maiden speech during Short Duration Discussion or Calling Attention.

श्री संजय सिंह : सर, इनको बोलने दीजिए। **...(व्यवधान)...**

MR. CHAIRMAN: I told him, two minutes. You said, बाद में बोलेंगे। **...(व्यवधान)...** राघव जी, बोलिए।

श्री राघव चड्ढा (पंजाब) **:** सर, यह मेरा सौभाग्य है कि आप चेयर पर बैठे हैं और मुझे पहली बार बोलने का मौका मिला है। मैं सदन का सबसे युवा, सबसे नया सदस्य हूँ। आप इसे मेरी मेडन स्पीच मानें या नहीं मानें, I seek your indulgence, Sir. मुझे पाँच-सात मिनट दे दीजिए। वे भी तैयारी से आयी हैं, मैं भी तैयारी से आया हूँ। मैं आपके माध्यम से माननीय वित्त मंत्री जी को भी कहूँगा कि अगर पांच मिनट मुझे और सुन लेंगी, तो Heavens won't fall, Sir.

MR. CHAIRMAN: No, no. Everybody asked for the same, please.

श्री राघव चड्ढा : सर, मुझे लगता नहीं कि यहाँ कोई आपत्ति करेगा। **...(व्यवधान)...**

श्री सभापति : आर्ग्यू मत कीजिए। **...(व्यवधान)...** मेरे सामने नाम हैं। **...(व्यवधान)...** I have the names before me.

श्री राघव चड्ढा : सर, मैं आपके आश्वासन पर ही बोलूँगा। मुझे प्लीज़ थोड़ा समय दीजिएगा। सर, आज से कई साल पहले एक मूवी "पीपली लाइव" आयी थी। उसका एक गाना था - "सखी सैंया तो खूब ही कमात है, महँगाई डायन खाये जात है।" आज इस गाने के लिरिक्स सार्थक होते नजर आ रहे हैं। मैं पंजाब सूबे से आता हूँ, जो एक खेती प्रधान सूबा है। पंजाब का किसान, देश का किसान महँगाई की डबल मार झेल रहा है - एक मार किसान पर ऐज़ ए प्रोड्यूसर और दूसरी मार किसान पर ऐज़ ए कन्ज्यूमर। फूड प्रोडक्शन की कॉस्ट पिछले एक साल में करीब-करीब 21 प्रतिशत बढ़ी है। यानी किसान की फूड प्रोडक्शन की कॉस्ट बढ़ गई, लेकिन उसकी आय, जिसका वादा था कि एमएसपी दोगुना करेंगे, आय बढ़ायेंगे, वह उस रेट पर नहीं बढ़ी, जिसके चलते आज देश का किसान ऐज़ ए प्रोड्यूसर महँगाई के बोझ तले दबता जा रहा है। दूसरा, देश का किसान ऐज़ए कन्ज्यूमर भी - क्योंकि मैं पंजाब से आता हूँ - आज कहीं बाजार में कुछ भी खरीदने जाता है, तो महँगाई की मार झेलता है। मैं आपको बताऊँ कि यह शायद आज़ाद भारत के इतिहास में पहली बार हो रहा है, जब भारत देश की रूरल इन्फ्लेशन भारत देश की अरबन इन्फ्लेशन से ज्यादा है। यानी कि गाँव में रहने के मुकाबले शहरों में रहना सस्ता है और आप जानते हैं कि यह देश वह देश है, जहाँ पर मैक्सिमम आबादी रूरल आबादी है।

सर, इन्फ्लेशन को टैक्सेशन विदाउट लेजिस्लेशन भी कहा गया है। यानी कि महँगाई वह चीज़ है, जो बिना कानून के सरकार हम लोगों पर टैक्स के रूप में लगाती है, ऐसा माना जाता है। सर, जैसे रावण के दस सिर थे, भारत की महँगाई के सात सिर हैं। मैं सातों के सातों पर आधा-आधा मिनट बोलना चाहूँगा, आप जितना टाइम दे दें।

सर, पहला है ऊर्जा पर टैक्स, एनर्जी टैक्सेशन, दूसरा है सर्विस इन्फ्लेशन, जो नज़र नहीं आती, लेकिन महसूस होती है। तीसरा है- जीएसटी का बोझ, चौथा है- लागत बढ़ाने वाली महँगाई, यानी कॉस्ट-पुल इन्फ्लेशन, पाँचवाँ है बढ़ती महँगाई, घटती कमाई, यानी कि हमारी आमदनी उस दर पर नहीं बढ़ रही है, जिस दर पर भारत की महँगाई बढ़ रही है। छठा प्वाइंट है गिरता हुआ रुपया और सातवाँ प्वाइंट है कॉरपोरेट और सरकार की साठ-गाँठ।

सर, एनर्जी टैक्स, जो क्रूड ऑयल पर लगता है, पेट्रोल पर लगता है, डीज़ल पर लगता है, यह भारत में दुनिया के मुकाबले सबसे ज्यादा है जिसके चलते आज कोयले की बात हो या पेट्रोल की बात हो, सारा बोझ कैसकेडिंग इम्पैक्ट के तहत देश के आम आदमी पर डाला जा रहा है। मैं बताना चाहूँगा कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार 26 मई, 2014 को बनी थी, तब अन्तरराष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल 108 डॉलर प्रति बैरल पर बिकता था। वह 20 अप्रैल, 2020 को 108 डॉलर प्रति बैरल से घट कर 1 डॉलर पर आ गया, इतना घट गया, लेकिन उसका जो फायदा था, लाभ था, वह देश के गरीब आदमी को नहीं सौंपा गया और मेरे सवाल के जवाब में, इस सदन में मुझे जवाब दिया गया कि 2016 से लेकर 2022 के बीच में सरकार ने 16 लाख करोड़ रुपये कमाये हैं, एक्साइज़ ड्यूटी बढ़ा-बढ़ा कर। सर, इस सरकार ने पेट्रोल पर 78 बार और डीज़ल पर 76 बार एक्साइज़ ड्यूटी बढ़ायी है। दूसरा प्वाइंट है..

श्री सभापति: राइट।

श्री राघव चड्ढा : सर, दो मिनट।

श्री सभापति: नहीं, नहीं। **...(व्यवधान)...**

श्री राघव चड्ढा : सर, मेरा दूसरा प्वाइंट है **...(व्यवधान)...** सर, मैं छोड़ रहा हूँ। **...(व्यवधान)...**। am leaving some points. ...(*Interruptions*)...

श्री सभापति : मैंने आपको तीन मिनट का समय दिया है। **...(व्यवधान)...**

SHRI RAGHAV CHADHA: I am leaving some points. ...*(Interruptions)*... I am leaving some points. But I will come to the point. ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: I have given you four minutes' time. ...*(Interruptions)*...

SOME HON. MEMBERS: Concluding, Sir. Concluding, Sir. ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: Please.

श्री राघव चड्ढा : सर, जीएसटी का जो बर्डन है,...**(व्यवधान)**...

श्री सभापति : राज्य सभा में वकालत अलाउड नहीं है। ...**(व्यवधान)**...

SHRI RAGHAV CHADHA: Sir, you count this as my maiden speech. There is no problem. Let me speak. Please permit me. ...*(Interruptions)*..

MR. CHAIRMAN: Please. There is no time. ...*(Interruptions)*... I have to call another 14 Members. ...*(Interruptions)*..

SHRI RAGHAV CHADHA: Sir, just give me a few minutes. I beseech you. I beseech you. ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: Please. ...*(Interruptions)*...

SHRI RAGHAV CHADHA: I seek your indulgence. जीएसटी, जिसे आज इस देश में गरीब शोषण टैक्स के नाम से भी जाना जाता है, सरकार यह टैक्स क्यों कम नहीं करेगी? इसलिए कम नहीं करेगी, क्योंकि जैसे-जैसे महँगाई बढ़ती है, वैसे-वैसे सरकार का जीएसटी का कलेक्शन बढ़ता है। अगर कोई चीज़ एक सौ रुपए की बिकती थी और आज वह डेढ़ सौ रुपए की होती है, तो डेढ़ सौ रुपए पर जीएसटी लगता है यानी कि इससे सरकार का खजाना बढ़ता है, इसलिए महँगाई कम करने की मंशा सरकार की कभी हो ही नहीं सकती। यह एक बड़ा महत्वपूर्ण प्वाइंट है, जिसके चलते इन्होंने आटा, दाल चावल आदि पर जीएसटी लगाया। ऐसा करके आम आदमी को और गरीब करने की कोशिश की गई, लेकिन मैं जिस धरती से आता हूँ, पंजाब से, वहाँ पर अमृतसर को गुरुओं की नगरी माना जाता है, पवित्र धरती माना जाता है, वहाँ पर जितने भी सराय हैं, जितने भी अकोमोडेशन सेंटर्स हैं, उन पर भी जीएसटी लगा कर आज औरंगजेब के जजिया टैक्स वापस लाने का काम भाजपा की सरकार ने किया है।

MR. CHAIRMAN: Right. Thank you, Raghavji. Next speaker is, Shri Jose K. Mani. ...*(Interruptions)*...

श्री राघव चड्ढा : सर, मेरे बस एक-दो प्वाइंट्स हैं, मुझे एक मिनट दे दीजिए। I will finish, Sir. ...*(Interruptions)*... I will finish it. ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: No, no, please. ...*(Interruptions)*... Please. ...*(Interruptions)*...

SHRI RAGHAV CHADHA: I will finish it. ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: Please. ...*(Interruptions)*...

SHRI RAGHAV CHADRA: Sir, give me one minute. ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: I have given you five minutes' time. ..*(Interruptions)*...

SHRI RAGHAV CHADHA: I am finishing, Sir. ...*(Interruptions)*..

MR. CHAIRMAN: Conclude it. Conclude in one line. ...*(Interruptions)*... Conclude in one line, please.

श्री राघव चड्ढा : सर, जब भारतीय जनता पार्टी के सदस्य विपक्ष में थे, तो वह कहा करते थे कि जब रुपया गिरता है, तो भारत की साख गिरती है। आज एक डॉलर 80 रुपए के पार हो गया है। पुरानी सरकारों ने रुपए को सीनियर सिटिज़न बनाया था, करंट सरकार ने 80 पार करके उसे मार्गदर्शक मंडल में पहुँचा दिया है।

MR. CHAIRMAN: Right. ...*(Interruptions)*...

श्री राघव चड्ढा : सर, आज जिसके चलते...**(व्यवधान)**...

MR. CHAIRMAN: Please. ...*(Interruptions)*... No; Shri Jose K. Mani. ...*(Interruptions)*...

श्री राघव चड्ढा : पेट्रोल हो, डीजल हो, ...**(व्यवधान)**...

MR. CHAIRMAN: You have a lot of future. You are a youngster. Follow the guidelines. I have already given you five minutes. ...*(Interruptions)*...

SHRI RAGHAV CHADHA: Sir, if the Finance Minister has no problem listening to me, if she can spend three-four minutes, ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: It is not between both of you. ...*(Interruptions)*...

SHRI RAGHAV CHADHA: If she can delay her speech by three-four minutes ... ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: There are seven speakers from BJP and ... ...*(Interruptions)*...

SHRI RAGHAV CHADHA: Sir, heaven won't fall. ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: Please. Jose K. Mani. ...*(Interruptions)*...

SHRI RAGHAV CHADHA: Heavens won't fall. Please permit me. ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: It will not fall. Don't worry. Please. You sit down. ...*(Interruptions)*... Shri Jose K. Mani. ...*(Interruptions)*...

SHRI JOSE K. MANI (Kerala): Sir, the inflation and price rise have already reached India like the smallpox. It is alarming. India is being converted into another Sri Lanka. I think it is in the making of another Sri Lanka. The democratic people of India would not like to imitate them. But the patience has a limit. The starvation is knocking at the doors of the middle class and the lower class. Sir, 'London Bridge is Falling Down' is a famous nursery rhyme. But this rhyme is differently sung by the kids of Kerala. The cash crops are falling down, falling down. But the price of milk and curd is rising up and up. It is a fact that the people are on the street and starvation is going on. Sir, strangely, we find, as he said, the cash crops - if you take into consideration the State of Kerala -- whether it is pepper or rubber or cardamom, the price is coming down.

MR. CHAIRMAN: Right, Mr. Mani.

SHRI JOSE K. MANI: Sir, I have not even come to the point at all. It is hardly two sentences.

MR. CHAIRMAN: I am sorry. If you cannot come to the point, I can't help it. I will go to the next speaker. Try to understand. I have another eight speakers here and the Ruling Party's six speakers, and from the main Opposition, one speaker. I have to go by the strength of the parties. But still we are liberal and giving time to 'Others'. You have to understand this; and you are bargaining. Go and bargain with the people. Next time, they must send you with much more strength so that you can have more time. ...*(Interruptions)*... Shri Vaiko. ...*(Interruptions)*...

SHRI JOSE K. MANI: One point, Sir. When we are talking about inflation of price over the value of rupee, the Treasury Benches are saying, nothing is happening. But we demand that a White Paper be released on the price rise and the effects of economic breakdown.

MR. CHAIRMAN: Right. Shri Vaiko.

SHRI VAIKO(Tamil Nadu): Hon. Mr. Chairman, Sir, ...

MR. CHAIRMAN: You have two minutes' time, Mr. Vaiko. Please.

SHRI VAIKO: It is a big time, Sir.

MR. CHAIRMAN: Yes.

5.00 P.M.

SHRI VAIKO: Sir, price rise in essential commodities and daily needs is a slow poison which is killing the people of this country. The price of foodgrains rose by 7.56 per cent, particularly vegetables rose by 17.37 per cent, spices by 11.04 per cent, edible oil and butter by 9.36 per cent. As you have said, I have only two minutes, I am skipping so many things.

The common citizens are now suffering from a price rise pandemic after the Covid pandemic. The price hike mostly affects only the low wages or fixed salaried middle class families as compared to higher wages salaried class. Auto rickshaw drivers and cab drivers are also robbed of their livelihood. Our fishing community also suffers the most since they use diesel for their craft boats and trawlers. They live hand to mouth and they are exposed to the rough weather of the sea. Sometimes, they get the catch of fish and sometimes they have to return empty handed. On the mid-sea, there is also the threat of attack by the Sri Lankan Navy. Many times, they are attacked and killed. The Government is coming with the excuse that because of rise in the price of crude oil in the international market, they are increasing the price of petrol. But the Union Government is not bringing down the excise duty structure and cess which is more than 50 per cent. Recently, the Government has reduced the rate of duty on petrol and diesel marginally, as a token reduction. No doubt, it has brought down the price of petrol by Rs.5, but the relief is only a token relief to the common people. To add insult to injury, the Union Government has levied GST on food articles

like rice, wheat, milk and milk products. It will have a cascading effect on the economy. Even the hospital-rooms taken on hire in the ICU are being taxed. The Union Government is, unfortunately, not sparing anyone.

MR. CHAIRMAN: Vaiko*ji*, please conclude.

SHRI VAIKO: I will take only one minute. Because of wrong monetary policies, there is a devaluation of rupee against the US dollar and, due to that, all imports are getting costlier, including the oil import bill. My demand is that the Union Government should roll back the price of LPG cylinders to the level of 2014 price. The Union Government should make all-out efforts to monitor and control the prices of essential commodities and daily needs of the common people. I have abided by your command, Sir.

MR. CHAIRMAN: Thank you, Vaiko*ji*. Young Members must know that Vaiko*ji* is one of the most ferocious speakers in the country. I have no hesitation in saying so. But the strength of his Party is less, so I cannot increase his time in the House. I have to go by the time allotted and do justice to others also. Thank you, Vaiko*ji*. He is very senior. This is the way that others also should follow the advice given by the Chair.

SHRI KANAKAMEDALA RAVINDRA KUMAR (Andhra Pradesh): Thank you, Mr. Chairman, Sir, for giving me the opportunity. The main reason behind rise in prices of essential commodities is found unabated increase in the price rise of petrol and diesel. It is not just the common man but even a small businessman like a restaurant owner is suffering. At present, the only solution is to bring the petrol and diesel under GST. My strong protest is for hiking the prices of LPG cylinder also. Recently, the Central Government had included many essential food items within the GST slab. It puts extra burden on common people. The entire population has not yet recovered from the shock of Covid-19 pandemic. Adding to this, the Government has brought essential items like rice, wheat, flour, milk and curd within the ambit of GST slab. This is totally uncalled for. I appeal to remove it. At the outset, I register my strong protest against the State Government of Andhra Pradesh for not reducing the excise duty on petrol and diesel. Most of the States had reduced the excise duty on petrol and diesel and the Central Government had also reduced it on two occasions. But the State Government of Andhra Pradesh had not reduced the excise duty. This had caused serious financial burden on the people of Andhra Pradesh. The effect of non-reduction of excise duty by the State Government is such that it has caused further price rise in the State of Andhra Pradesh. The need of the hour is to contain the

inflation. If the inflation keeps on rising continuously, the prices will increase and there shall be a financial burden on all the sections of the society, particularly the marginalised people of the society. Time and again, the Government is claiming that several supply-side measures have been taken by the Government to address the inflation. The Government should ensure that the supply side is maintained properly. The extent of the land under cultivation has to be increased considerably in order to achieve self-reliance. How we can reduce this inflation? The only way is self-reliance. This is the solution for the overall development of the sector. The Government has to consider the fact that the income of the people has not been increased. No steps have been taken to increase the income of the common man, at least, to pay the increasing taxes. Vulnerable sections of the society are suffering due to high prices of essential commodities. Price rise is a reality. We should not escape from this by giving several justifications. The Government should do something to reduce the burden of the common man. I request the hon. Finance Minister to take steps this direction. Thank you, Sir.

DR. M. THAMBIDURAI: Mr. Chairman, Sir, as you know very well, as you have served as a Parliamentary Affairs Minister also, many a time, we have discussed this issue of price rise in the Parliament. In the same way, we are discussing it today also. The price rise is a common phenomenon now. It can be controlled not only by the Central Government; the State Government also has to play its role to control the prices. That is why, during our regime, during the time of former Chief Ministers of Tamil Nadu, Amma, and Edappadi K. Palaniswami, so many incentives were given to the farmers and free rice was also given to the people to control the prices.

In the Lok Sabha, our Finance Minister raised the point that the poll promises that are given to the people have to be fulfilled. But, on the other side, about the DMK Government, I want to say that the electricity bills have gone up. They have been increasing the bills. Also, as promised during the polls, they have not reduced the petrol prices. ...*(Interruptions)*... Yes, only petrol prices have been reduced, but the diesel prices have not been reduced. ...*(Interruptions)*... I am saying this because when they spoke...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: When you get an opportunity, you can reply.

DR. M. THAMBIDURAI: Sir, I am stating that this is a fact. Even our Finance Minister had raised this issue in the Lok Sabha. Whatever promises were made by the State

Government of Tamil Nadu have not been fulfilled. That is why, price rise is there. ...*(Interruptions)*... Our Party, AIADMK, protested under...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: Please...*(Interruptions)*...

DR. M. THAMBIDURAI: We protested to see that electricity bills must not be increased. As they promised, the price of diesel must be curtailed. Regarding GST, I want to say that the GST is the child of the Congress. They had brought the GST. ...*(Interruptions)*... I am just concluding, Sir. ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: Please, I know what to allow and what not to allow. ...*(Interruptions)*...

DR. M. THAMBIDURAI: The concept of GST was brought during the UPA Government. There, the DMK was also a part of that. But, that Government could not do anything. Prices have increased because of GST. That is a fact. I accept this fact. But, at the same time, the DMK Party is a part of that Council. Here, the Minister has made it very clear that the non-BJP States of Punjab, Chhattisgarh, Rajasthan, Tamil Nadu, West Bengal, Andhra Pradesh, Telangana and Kerala had agreed to impose 5 per cent. ...*(Interruptions)*... This is what the Finance Minister has said. ...*(Interruptions)*... She is here. She is going to answer to you. ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: No arguments, please. ...*(Interruptions)*...

DR. M. THAMBIDURAI: Thank you very much, Sir.

MR. CHAIRMAN: No argument, please. The Minister is here. She is capable of responding. Don't worry. ...*(Interruptions)*... Please, इससे क्या फायदा होगा, यह मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मैं भी यहाँ पर ऑलमोस्ट 20 साल से हूँ। यह तो रिकॉर्ड में नहीं जाएगा, वे इसको नहीं दिखाएँगे। इससे केवल आपका गला खराब होगा, जिससे परेशानी बढ़ जाएगी। महँगाई कम नहीं होगी, मगर परेशानी बढ़ जाएगी। Now, Shri Abdul Wahab. You obliged Mr. Baishya. That is why, I am obliging you now.

SHRI ABDUL WAHAB(Kerala): Sir, for me, I think ten minutes will be okay.

MR. CHAIRMAN: Yes, two minutes.

SHRI ABDUL WAHAB: It was the other way round. This is end of your term. So, I thought you will be giving more time.

MR. CHAIRMAN: This is not the end of my life; I am still...*(Interruptions)*...

SHRI ABDUL WAHAB: Sir, with much effort, we got a chance to talk about price rise. I cannot understand as to why we did not talk about this issue on the very first day of the Session. After twelve days, we have got this opportunity. We were talking about Antarctica and all, but this is the issue on which we have to talk. We should give priority to this issue. We, the Keralites, are much of a problem for the BJP in the Centre and the LDF in Kerala. Both of them are charging us, the common people. They have not reduced the prices. In Tamil Nadu, the DMK Government has reduced the price of diesel and petrol. In Kerala, they are taking a chance to increase everything. ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: Please, don't look at them.

SHRI ABDUL WAHAB: Sir, I am looking at you, but in the meantime, we have to look at other people also to see how they are responding. Sir, we have the LDF Government there. Sir, Kerala people are in between the devil and sea. So, I am requesting Shrimati Nirmala Sitharaman at least to reduce the last increase in GST on essential items, to which Kerala Government has not agreed. I am not wearing horticulture items but price of everything is increased. Please do the needful. Hon. Minister is not looking at me.

THE MINISTER OF FINANCE; AND THE MINISTER OF CORPORATE AFFAIRS (SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN): I am listening to everything.

SHRI ABDUL WAHAB: Please address these issues in your reply. Thank you.

श्री सभापति : श्री घनश्याम तिवाड़ी। घनश्याम जी, समय कम है, आपकी पार्टी का समय है, लेकिन फिर भी आप थोड़ी मदद कीजिए।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (राजस्थान) : माननीय सभापति महोदय, मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आज आपके श्रीमुख से सुनकर मुझे बोलने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं समय का पूरा ध्यान रखूंगा।

महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मैंने तो 8-10 दिन तक विपक्ष का हंगामा सुनकर यह सोचा था कि निश्चित रूप से विपक्ष ऐसी कोई सार्थक बहस करेगा, जिससे आम जनता को

राहत मिले और काम हो सके, लेकिन सबके प्रवचन सुनने के बाद मुझे ऐसा लगा कि सारा का सारा काम पूर्णतयः राजनीतिक है, जनता के पक्ष में करने वाला काम नहीं किया गया। अगर ये लोग ईमानदारी से बात करते, तो आज श्री नरेन्द्र मोदी जी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते कि इतने बड़े कोविड के बाद, रूस और यूक्रेन की लड़ाई के बाद, ये सारे काम होने के बाद - आज अगर देश को चारों तरफ से देखें, तो पहले हमारे आसपास के कंट्रीज़ को देखें कि उनकी क्या स्थिति है, आप अमेरिका को देखें कि उनकी क्या स्थिति है, फिर पश्चिमी यूरोप को देखें कि उनकी क्या स्थिति है! इन सबके बीच में देश की नाव को इस प्रकार से निकाल कर ले जाना एक महानता का काम था, जिसके प्रति आपको कृतज्ञता ज्ञापित करनी चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, कोविड के अंदर दो साल तक सारी एक्टिविटीज़ बंद हो गई थीं, सारी रेल बंद हो गई थीं, सारे हवाई जहाज़ बंद हो गए थे, सारे लोगों को एक प्रांत से दूसरे प्रांत जाना पड़ा, जिससे उत्पादन बंद हो गया। उस समय 80 करोड़ लोगों के घरों पर राशन पहुंचाकर जिस प्रकार का जनकल्याणकारी काम किया गया है, वह एक अद्भुत काम सरकार ने किया था। रूस और यूक्रेन की लड़ाई के बाद जब अमेरिका ने और यूरोप के नाटो देशों ने माननीय मोदी जी पर दबाव बनाया कि आप रूस से सस्ता क्रूड ऑयल मत खरीदिए - आज पाकिस्तान का बच्चा-बच्चा बोलता है कि भारत के प्रधान मंत्री की हिम्मत थी कि उन्होंने अमेरिका को मना किया, यूरोप को मना किया और सस्ता क्रूड खरीद कर भारत को दिया ताकि पेट्रोल और डीज़ल के पैसे नहीं बढ़ सकें, यह काम किया है। सरकार ने इस प्रकार के काम किए हैं। फिर सरकार ने इन बातों पर ध्यान नहीं दिया। कोई यह कल्पना नहीं करता कि गर्मी एकदम से बढ़ी और गाँवों का उत्पादन कम हो गया और जब गाँव से एक्सपोर्ट होने लगा, तो सरकार ने गाँव के एक्सपोर्ट पर प्रतिबंध लगाकर यह कोशिश की कि यह कम हो जाए।

दूसरा, जब आठ बार लगातार सरकार ने पेट्रोल और डीज़ल के दाम को कम किया, तो विपक्ष की सरकारों ने कम नहीं किया। मैं कहना चाहता हूं कि राजस्थान एकमात्र ऐसा राज्य है, जहां हिन्दुस्तान में सबसे अधिक महंगा पेट्रोल और डीज़ल है। परंतु महोदय, दुर्भाग्य यह है कि कांग्रेस पार्टी में राजस्थान से कोई भी जीतकर आया हुआ आदमी नहीं है, सभी उत्तर प्रदेश से या अन्य जगह से हैं, तो वे बोलते नहीं हैं। जब भारत सरकार ने कम किया तो राज्य सरकारों ने कम किया। फिर दूसरा दोहरा चरित्र सामने आया, वह आया कि कल जब माननीय वित्त मंत्री महोदया ने लोक सभा में साफ-साफ कहा और राज्यों के मंत्रियों के वक्तव्य छपे कि जीएसटी काउन्सिल में जो प्रस्ताव पास हुआ, वह सारा प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास हुआ। उसके बाद आम जनता को दिखाने के लिए राज्य सभा में आकर विरोध करते हैं और वहां अंदर बैठकर समर्थन करते हैं। यह दोहरा चरित्र है, जो जनता कि हित का नहीं है, यह राजनीतिक हित का चरित्र है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि यह महंगाई की समस्या है, महंगाई की समस्या का समाधान है और सरकार ने 8 कदम उठाए हैं। सरकार ने यह कदम उठाया कि जो ऑयल सीड्स आ रहे हैं, उन पर ड्यूटी समाप्त कर दी। सरकार ने प्रतिबंध हटाया, जिससे कि स्टील की कीमतें कम हों, वह काम किया। सरकार ने चीनी के एक्सपोर्ट को लिमिटेड करने का काम किया। सरकार ने आठ बड़े-बड़े कदम उठाए हैं, जिनके कारण आज हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान डूब रहा है, श्रीलंका डूब रहा है, बंगलादेश 4.5 अरब डॉलर का कर्ज मांग रहा है। हमारे चारों तरफ के देश आज इस हालत में हैं और हम सबसे सुरक्षित हालत में हैं। यह काम नरेन्द्र मोदी जी ने किया है। दूसरा, मैं यह कहना

चाहता हूं कि अमेरिका का इन्फ्लेशन रेट 9 परसेंट तक गया, ब्रिटेन का 30 परसेंट सबसे अधिक गया, स्पेन में 9 परसेंट गया, इटली में गया, उन सबके बजाय भारत उनसे बच कर रहा, यह काम वर्तमान सरकार ने किया, नरेन्द्र मोदी जी की सरकार ने किया और आने वाले समय में जनकल्याण के कार्य सरकार करेगी और महंगाई पर कंट्रोल करेगी।

सभापति जी, आपका इशारा हो गया और मैं इशारों को समझता हूं, इसलिए मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: ये बहुत अनुभवी हैं। श्रीमती रंजीत रंजन, आपके पास सात मिनट का समय है।

श्रीमती रंजीत रंजन (छत्तीसगढ़) : सभापति जी, मैं आपके सामने पहली बार बोल रही हूं। प्लीज़ मैं आपसे दो-तीन मिनट अधिक देने के लिए रिक्वेस्ट करूंगी। आप बीच में बोल देते हैं, तो मेरी सारी रिदम खत्म हो जाती है। महोदय, कल लोक सभा में जो माननीय सदस्य बोल रहे थे, क्योंकि हमें सभा की आदत पड़ी हुई है, तो हम लोग सबके भाषणों को सुन रहे थे। माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी का रिप्लाई भी सुना। हमें बहुत सारी बातें समझ में आईं। मुझे मुंशी प्रेमचंद जी की एक रचना याद आ गई, जिसका नाम गोदान था - गऊ का दान। सर, एक बहुत गरीब फैमिली थी, वह पूरी जिदंगी एक गाय को पाल कर अपने बच्चों को दूध और दही खिला पाने का सपना देखती रही। उसका पति बीमार पड़ता है और शय्या पर होता है और पांच मिनट बाद उसकी डेथ होने वाली होती है, तो पंडित जी आते हैं और यह कहते हैं कि गोदान कर दीजिए, तो आपका पति स्वर्ग सिधार जाएगा। उसकी पत्नी घर गई, एक रुपये का सिक्का लेकर आई और पंडित जी को दिया और उनसे कहा कि मेरे घर में यही एक रुपया बचा है। मेरा पति पूरी जिदंगी दूध और दही के सपने लेकर, गौ पालने के सपने देख रहा था और आज आप यह कह रहे हैं कि स्वर्ग सिधारने के लिए गो का दान कर दीजिए। मैं यह इसलिए बोल रही हूं कि आज गरीब के पेट पर लात मारी जा रही है और हमारे मोदी साहब कह रहे हैं कि थाली बजाओ, थाली बजाओ। आप सारा ठीकरा यूक्रेन की लड़ाई पर ठोक रहे हैं, आप कोविड को दे रहे है, लेकिन आपने और आपकी नीति ने जो नोटबंदी की और आपने 2016 से जो गलतियों पर गलतियां कीं, उनका कभी भी ज़िक्र नहीं किया। जितने अर्थशास्त्री थे, उन सब ने कहा था, जब हमारे देश की आर्थिक हालत बिल्कुल स्टेबल थी, उस वक्त नोटबंदी मत कीजिए। आपके स्वर्गीय सदस्य, मैं उनका नाम नहीं लूंगी, उन्होंने भी कहा था कि नोटबंदी नहीं करनी चाहिए। उस दिन से आज तक हम अपने देश की आर्थिक स्थिति को संभाल नहीं पा रहे हैं। मैं वर्तमान प्रधान मंत्री जी का 2013 का भाषण याद कर रही थी। उस समय उन्होंने कहा था कि मनमोहन सिंह जी महंगाई का 'म' नहीं बोलते हैं। प्लीज़, मनमोहन सिंह जी आएं और महंगाई के बारे में बताएं कि कब कम होगी। उन्होंने कहा मरो, तो मरो, आपका नसीब। ये प्रधान मंत्री मोदी जी के शब्द थे, तत्कालीन प्रधान मंत्री मनमोहन सिंह जी के लिए, उन्होंने कहा था कि आप गरीबों के लिए कह रहे हैं कि मरो, तो मरो, आपका नसीब। मुझे फिर कोविड का वक्त याद आ रहा है। जब करोड़ों लोग हजारों किलोमीटर तक सड़कों पर चलकर जा रहे थे, * फिर हमारी माननीया मंत्री * ने कहा कि जब भूखा बच्चा चीख-चीख कर भूख से व्याकुल हो रहा होता है, तो सरकार क्यों नही सुनती है? जब

किसान आत्महत्या कर रहा होता है, तो आप कान में रूई डालकर सो जाते हो। । wish * आइए, और हम लोगों के साथ अगर आप चीख-चीख कर उस बच्चे की पुकार और दर्द को समझ रही थीं, तो आइए। आज गैस सिलेंडर 1,054 रुपये हो गया है। आज आप हमारे साथ चीख-चीख कर गरीबों की बात करिए। # ...**(व्यवधान)**...

श्री सभापति : एक मिनट रंजीत जी ...**(व्यवधान)**... किसी का नाम लेकर यहां सवाल नहीं करना चाहिए। ...**(व्यवधान)**... वह रिकॉर्ड में नहीं जाएगा।

श्रीमती रंजीत रंजन : सर, मैं स्वर्गीय सुषमा जी की स्पीच को याद करना चाहती हूं, जिन्होंने कहा था कि यह संवेदनहीन सरकार है। यह बिल्कुल भी गरीबों के बारे में सोचने वाली सरकार नहीं है। यह विश्वासघाती सरकार है। आज मुझे यह कहना पड़ रहा है कि *मुझे डर लगता है जब मैं प्रधान मंत्री की उस स्पीच को सुनती हूं, जब उन्होंने कहा था कि घर में चूल्हा नहीं जलता है, बच्चे भूख से रो-रो कर सोते हैं और मां आंख में आंसू लेकर चुप हो जाती है। जब आंसू की बात पीएम साहब के मुंह से सुनते हैं, तो हमें डर लग जाता है, क्योंकि उन्होंने पहले मिडल क्लास से कहा, महिलाओं के आंसू निकलते हैं मेरे भी निकलते हैं, सब्सिडी छोड़ दो, महिलाओं ने छोड़ दी। कहा गरीबों को सब्सिडी देंगे, महिलाएं पसीज गईं, हम सबने सब्सिडी छोड़ दी। आज उसका हश्र क्या हुआ? आज आपने 1,600 रुपये का एक झुनझुना पकड़ा कर लगभग सात करोड़ लोगों को चूल्हा और गैस का सिलेंडर दिया। आपको मालूम था कि गरीब आपके झांसे में फंसेगा। एक चुनाव, दो चुनाव आपने 'उज्ज्वला योजना' से निकाल दिए। उसके बाद क्या हुआ? क्या वह 1,600 रुपये, वह सब्सिडी, जिस रेवड़ी की बात आज मोदी साहब कर रहे हैं, प्रधान मंत्री साहब कर रहे हैं, क्या वह रेवड़ी नहीं थी? उस रेवड़ी में फर्क इतना था कि वह गरीबों के लिए नहीं थी, वह गैस एजेन्सीज़ के लिए थी। आप 1,600 रुपये गरीबों से ले रहे थे, बाकी का जो पैसा सरकार दे रही थी, वह किसका दे रही थी? टैक्सपेयर्स का दे रही थी। उसके बाद क्या हुआ? आज आंकड़े हैं, पर इतना वक्त नहीं है। लगभग सात करोड़ घर, जिनमें साढ़े चार करोड़ वे लोग हैं, जो उज्ज्वला के तहत आते हैं, एक साल में एक भी गैस सिलेंडर रीफिल नहीं करा रहे हैं। साढ़े तीन करोड़ के लगभग वैसे लोग हैं, जो साल में एक रीफिल करवा रहे हैं। यह झुनझना किसको दिया था? यह किसकी रेवड़ी थी? रेवड़ी तो प्रधान मंत्री साहब आपने भी दी। कल मैं सुन रही थी, लोक सभा में भाजपा के एक सांसद बोल रहे थे।

MR. CHAIRMAN: Don't take name of Lok Sabha Member.

श्रीमती रंजीत रंजन : उस वक्त भी आपके टाइम में 900 रुपये का गैस सिलेंडर था, हम मानते हैं कि 900 रुपये था, लेकिन हम अपनी रेवड़ियां गरीबों में दे रहे थे। बिल्कुल 400 रुपये कम में गैस सिलेंडर दे रहे थे, हम गरीबों की मदद कर रहे थे। हम एनपीए की और करोड़पतियों की मदद

---

* Expunged as ordered by the Chair.

Not recorded.

नहीं कर रहे थे। हम उनके साढ़े तीन-तीन लाख करोड़ रुपये माफ नहीं कर रहे थे, हम गरीबों को दे रहे थे।

आप खाद्य सुरक्षा की बात कर रहे हैं। एक तरफ मोदी साहब कहते हैं कि रेवड़ी बांटना बहुत खतरनाक है। प्रधान मंत्री साहब, मैं सभापति महोदय के माध्यम से बोलूंगी कि उज्ज्वला की रेवड़ी हो, चाहे आपकी कोई भी गरीबों के लिए रेवड़ी हो, उस रेवड़ी में न तिल था, न चीनी थी और न गुड़ था। यह तिल, चीनी और गुड़ सब कुछ जो लेकर गए, वे कॉरपोरेट थे। मैं आपको एक और रेवड़ी की याद दिलाना चाहती हूं - जिओ। आप एक तरफ कह रहे हैं कि रेवड़ी नहीं खिलानी चाहिए। आपने क्या किया? पूरे देश को जिओ की रेवड़ी खिलाई। पहले बोल रहे हैं कि मुफ्त में दे रहे हैं, मुफ्त में दे रहे हैं, मुफ्त में दे रहे हैं। जब उसकी आदत डल गई, उसके बाद अब लोग कितने में जिओ का प्रीपेड और पोस्टपेड भरवाते हैं। यह कौन सी रेवड़ी थी। यह रेवड़ी भी कॉरपोरेट के लिए थी, गरीबों के लिए नहीं थी।

दूसरी तरफ, मैं आपको जरूर कहना चाहूंगी कि मेरी बात एक छोटी सी फैक्टरी चलाने वाले व्यक्ति से हो रही थी। कल मैं निर्मला जी का भाषण सुन रही थी, उन्होंने बोला कि लगभग 1.45 लाख करोड़, मेरे आंकड़े गलत हो सकते हैं, इस बार भी हमने जीएसटी से पाया। मैं मंत्री जी से पूछना चाहूंगी कि आप जीएसटी से तो पा रहे हैं, जो लोग काम कर रहे हैं, फैक्ट्रीज़ चला रहे हैं, महीने के अंदर ही उनको बैंक का ब्याज भी देना पड़ता है, जीएसटी भी गवर्नमेंट को देना पड़ता है और अगर 15 दिन के अंदर वे नहीं देंगे, तो आप पेनल्टी लगाते हैं, लेकिन उनका जीएसटी का इनपुट आपको कितने दिन में देना था? एक-एक साल लगाकर आप उनका इनपुट नहीं देते हैं। खरबों रुपये उनके इनपुट से बनाकर क्या सरकार देश को उसी इन्पुट से चला रही है?

श्री सभापति : अब आप कन्क्लूड कीजिए।

श्रीमती रंजीत रंजन : तीसरी बात, मैं 16-17 साल के एक बच्चे से मिली। आप पांच परसेंट जीएसटी लगा रहे हैं, आप 12 से 18 परसेंट जीएसटी लगा रहे हैं। दोनों ही जीएसटी में आम आदमी मरता है। किसी ने बोला कि 5 परसेंट जीएसटी से किसको फर्क पड़ेगा? सर, फर्क पड़ता है। जो व्यक्ति 500 रुपये की वृद्धा पेंशन के लिए आठ घंटे लाइन में खड़ा होता है, पूरे महीने उससे काम चलाता है, अगर उस पर 5 परसेंट जीएसटी लगता है, तो फर्क पड़ता है। आप कहते हैं कि जो गरीब है, वह खुले का खाता है, इसलिए उसको फर्क नहीं पड़ेगा। मैं आपसे पूछती हूं कि क्या आप यह चाहते हैं कि वह गरीब जिंदगी भर, ठेले पर मक्खी लिपटा हुआ खाना ही खाता रहे? क्या उसको हक नहीं है कि वह पैक्ड खाना खाए? क्या उसको यह हक नहीं है कि वह स्वस्थ खाना खाए? **..(व्यवधान)..**

श्री सभापति : श्रीमती रंजीत रंजन, प्लीज़ कन्क्लूड कीजिए। **..(व्यवधान)..**

श्रीमती रंजीत रंजन : सर प्लीज़, दो-मिनट और बोलने दीजिए। आप यह बताइए कि टेट्रा पैक में जो 10-12 रुपये की लस्सी, छाछ, दूध, दही आदि हम सभी खाते हैं, बच्चे जब स्कूल से आते हैं,

तो किसी भी एमसीडी या एनडीएमसी के बूथ पर जाकर छाछ लेते हैं, आप उस पर जो 12-18 परसेंट टैक्स लगा रहे हैं, क्या उसको अमीर खाता है या किसी करोड़पति का बच्चा वह टेट्रा पैक वाली लस्सी पीता है, जिसके लिए आप कह रहे हैं कि 12-18 परसेंट करना है? मुझसे एक बच्चा कह रहा था कि मैडम, आप लोग सदन में बोलते क्यों नहीं हैं? ..**(व्यवधान)**..

श्री सभापति : श्रीमती रंजीत रंजन, आपने ज्यादा समय लिया है, धन्यवाद।

श्रीमती रंजीत रंजन : सर, दो मिनट दे दीजिए। ..**(व्यवधान)**..

श्री सभापति : मैंने आपको दो मिनट एक्स्ट्रा टाइम दिया है, अगर आप पॉलिटिकल सवाल पूछने लगी हैं, तो मैं क्या करूँ? ..**(व्यवधान)**.. Please. Now, Dr. Fauzia Khan. ...*(Interruptions)*...

श्रीमती रंजीत रंजन : सर, मैं कंक्लूड कर रही हूं। ..**(व्यवधान)**..

श्री सभापति : कंक्लूड कीजिए।

श्रीमती रंजीत रंजन : उसने क्या बोला कि आप बताते क्यों नहीं हैं? स्कूटी से जाएँ, तो तेल महंगा, दस रुपये के एक टेट्रा पैक का जूस पिएँ, तो वह महंगा, स्कूल में जाएँ, तो पेंसिल, रबड़, इरेजर, कटर महंगा है - आदमी जाए तो कहाँ जाए? एक तरफ तो आप कोविड महामारी में 23 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा में लेकर आ गए, 98 परसेंट लोगों की सारी आमदनी घट गई। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करती हूं, लोग बार-बार कह रहे थे कि रुपया गिर रहा है, देश की आबरू जा रही है आदि-आदि, तो मनमोहन सिंह जी से आपने पूछा था और मनमोहन सिंह जी ने बोला तो उस वक्त भी कुछ नहीं था, लेकिन वह 59 से 69 हुआ था और चार महीनों के अंदर वे दोबारा उसे 59 पर लेकर आ गए थे। क्या आप लेकर आएंगे? मैं आपसे आग्रह करती हूं कि प्लीज़ ..**(व्यवधान)**..

MR. CHAIRMAN: Please. Now, Dr. Fauzia Khan. ...*(Interruptions)*... It is not going on record.

श्रीमती रंजीत रंजन : *

MR. CHAIRMAN: Once I call the other name, it will not go on record. आप बैठ जाइए। Dr. Fauzia Khan, you have two minutes.

DR. FAUZIA KHAN (Maharashtra): Thank you very much, Mr. Chairman, Sir. सर, आर्थिक नियोजन में और इस संतुलन में ही सरकार की सारी कुशलता छुपी हुई होती है कि आम

* Not recorded.

आदमी पर टैक्स का अधिक बोझ भी न पड़े, न ही महंगाई की अधिक मार पड़े और सरकार का विकास का काम भी सरलता से चलता रहे।

†سر، آرتھک نیوجن میں اور اس سنتولن میں ہی سرکار کی ساری کُشلتا چھپی ہوئی ہوتی ہے کہ عام آدمی پر ٹیکس کا زیادہ بوجھ بھی نہ پڑے، نہ ہی مہنگائی کی زیادہ مار پڑے اور سرکار کا وِکاس کا کام بھی آسانی سے چلتا رہے۔

Running the Finance Department is all about balancing finances. With a capable woman Finance Minister on the driving seat, I feel inclined to think that India will emerge victorious in this battle of balancing. सर, वह सुबह कभी तो आएगी। कहा जाता है,

'माना कि अभी तेरे मेरे अरमानों की कीमत कुछ भी नहीं,
मिट्टी का भी है कुछ मोल, मगर इंसानों की कीमत कुछ भी नहीं।
इंसानों की इज्ज़त जब झूठे सिक्कों में न तौली जाएगी,
वो सुबह कभी तो आएगी।'

सर, मैं यह भी कहना चाहूंगी कि यह सुबह हम ही से आएगी। मुश्किल यह है कि अब नियोजन कुछ चूक रहा है, खाद्य वस्तुओं पर भी जीएसटी लगाया जा रहा है।

†سر، وہ صبح کبھی تو آئے گی۔ کہا جاتا ہے کہ،

مانا کہ ابھی تیرے میرے ارمانوں کی قیمت کچھ بھی نہیں
مٹی کا بھی ہے کچھ مول، مگر انسانوں کی قیمت کچھ بھی نہیں۔
انسانوں کی عزت جب جھوٹے سِکوں میں نہ تولی جائے گی،
وہ صبح کبھی تو آئے گی۔

سر، میں یہ بھی کہنا چاہونگی کہ یہ صبح ہم ہی سے آئے گی۔ مشکل یہ ہے کہ اب نیوجن کچھ چک رہا ہے، کھانے پینے کی چیزوں پر بھی جی ایس ٹی لگایا جارہا ہے۔

These GST compulsions on basic commodities are obviously the result of the need for more money to run the Government. The same applies to the fuel cess. सर, हर घर, हर घर करते-करते हम कब हर घर तंगी लेकर आ गए, यह हम समझ भी नहीं पाए। यहाँ तक कि हमने मासूम बच्चों के, दूध पीते बच्चों के दूध पर भी टैक्स लगा दिया है।

†سر، ہر گھر، ہر گھر کرتے کرتے ہم کب ہر گھر تنگی لیکر آگئے، یہ ہم سمجھ بھی نہیں پائے۔ یہاں تک کہ ہم نے معصوم بچوں کے، دودھ پیتے بچوں کے دودھ پر بھی ٹیکس لگادیا ہے۔

The Government does not forget to pat its back when it comes to collecting more GST, handling inflation, GDP debt ratio, etc. But, Sir, when such matters come up, why does the Government conveniently shift this to the GST Council? That is my

† Transliteration in Urdu script.

question here. सर, सवाल यह है कि क्या यह सरकार उस भूखे बच्चे के सामने जाकर, जो भूख से पाँव रगड़-रगड़ कर रो रहा है, क्या हम उसके सामने जाकर यह कह सकते हैं कि हमारा जीडीपी डैट रेश्यो इतना-इतना है? क्या उस माँ के आगे, जो अपने बच्चे के लिए उस 5 परसेंट एक्स्ट्रा पैसे की वजह से जो दूध लाती है, उसका पेट भरने के लिए वह उसमें पानी मिला रही है, क्या उससे यह कह सकेंगे कि यह कोविड की वजह से हो रहा है? सर, उस पेशेंट को, जो इलाज कराने के लिए, हॉस्पिटल रूम में जाने के लिए अपना घर बेच रहा है...। क्या हम उसको यह कह सकते हैं कि ग्लोबल कांटैक्स्ट में तो हम बेहतर हैं? सर, मैं देहात की महिलाओं के बारे में बात करना चाहती हूं। सर, मुझे एक ही मिनट दे दीजिए। देहात की महिलाएं आज नशे में चूर उनके पुरुषों की वजह से त्रस्त हैं, हैरान हैं।

मैं यह पूछना चाहती हूं कि दूध पर जी.एस.टी. लगाने के बजाय जो टोबैको पर 28 परसेंट जी.एस.टी. है, वह हम लगा चुके हैं, जो हाइएस्ट टैक्स स्लैब है। सिगरेट पर, टोबैको प्रोडक्ट्स पर जो रिटन प्राइस है, उसका 52.7 परसेंट

†سر، سوال یہ ہے کہ کیا یہ سرکار اس بھوکھے بچے کے سامنے جاکر، جو بھوکھ سے پاؤں رگڑ رگڑ کر رو رہا ہے، کیا ہم اس کے سامنے جاکر یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا جی ڈی پی ڈیٹ ریشو اتنا ہے؟ کیا اس ماں کے آگے، جو اپنے بچے کے لیے اس پانچ فیصد زیادہ پیسے کی وجہ سے دودھ لاکر اپنے بیٹے کا پیٹ بھر رہی ہے اور پیٹ بھرنے کے لیے اس میں پانی ملا رہی ہے، تو کیا ہم اس ماں سے یہ کہہ سکیں گے کہ یہ کووڈ کی وجہ سے ہورہا ہے؟ سر، کیا اس پیشینٹ کو، جو علاج کرانے کے لیے، ہاسپٹل روم میں جانے کے لیے اپنا گھر بیچ رہا ہے۔

کیا ہم اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ گلوبل کانٹیکٹس میں تو ہم بہتر ہیں؟ سر، میں دیہات کی مہیلاؤں کے بارے میں بات کرنا چاہتی ہوں۔ سر، مجھے ایک ہی منٹ دے دیجیئے۔ دیہات کی مہیلائیں آج نشے میں چور ان کے پروشوں کی وجہ سے ترست ہیں، حیران ہیں۔

میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ دودھ پر جی ایس ٹی لگانے کے بجائے ہم جو ٹوبیکو پر اٹھائیس فیصد جی ایس ٹی ہے، وہ ہم لگا چکے ہیں، جو ہائیبٹ ٹیکس سلیب ہے۔ سگریٹ پر، ٹوبیکو پروڈکٹس پر جو ریٹین پرائز ہے، اس کا 52.7 فیصد۔۔

for cigarettes, 22 per cent for *beedis*, 63.8 per cent for.....*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: Please conclude. ...*(Interruptions)*... You have already taken four minutes.

DR. FAUZIA KHAN : I just want to say that why do we not try to come up to the recommendation of the W.H.O. by raising it to 75 per cent in some way? At the end, Sir, I would only like to refer to what Rajani *Tai* was saying that we got a drop of time here today. Thank you very much for it. लेकिन एक छोटी सी कविता सुनाकर 20 सेकंड में मैं अपनी बात का अंत करूंगी। जलते दीपक ने कहा, जलता दीपक जनता है, जलते दीपक ने कहा:

'ऐ लहराती हवा, दो पल रुक तो जरा, मेरा फसाना भी तो सुन।
मेरी सुलगी हुई हस्ती, तेरी बेपरवाह मस्ती,

† Transliteration in Urdu script.

नई कहानी तो न बुन, मेरा फसाना भी तो सुन।
मेरी जिद का जोर कहूं, या हौसले का बल,
दो पल जो रुक गये, मेरा फसाना सुनने।'

मैं आभारी हूं कि इस देश के दुख का फसाना तो आपने आज सुन लिया, भले ही मुझे दो मिनट के अंदर बोलना पड़ा।

†لیکن ایک چھوٹی سی کویتا سناکر 20 سیکنڈ میں میں اپنی بات ختم کرونگی۔ جلتے دیپک نے کہا، جلتا دیپک جنتا ہے:

جلتے دیپک نے کہا، اے لہراتی ہوا،
دو پل رک تو ذرا، کیرا فسانہ بھی تو سن۔
میری سلگی ہوئی ہستی، تیری بے پرواہ مستی،
نئی کہانے تو نہ بُن، میرا فسانہ بھی تو سن۔
میری ضد کا زور کہوں، یا حوصلے کا بل،
دو پل جو رک گئے، میرا فسانہ سننے۔

میں آبھاری ہوں کہ اس دیش کے دکھ کا فسانہ تو آپ نے سن لیا، بھلے ہی مجھے دو منٹ کے اندر بولنا پڑا۔

श्री सभापति : दो मिनट नहीं, चार मिनट से ज्यादा हो गया। Now, Shri Binoy Viswam, two minutes.

SHRI BINOY VISWAM(Kerala): Thank you, Sir, for the benevolent two minutes.

श्री सभापति : मैं क्या करूँ?

SHRI BINOY VISWAM: Sir, if powerful speeches could have the capacity to control prices, it could have happened yesterday. The speech that our Madam Finance Minister made in Lok Sabha yesterday was very powerful even though she is not well due to Covid reasons. It was a very good and powerful speech. If promises in large numbers could bring in robust economy, our country could have reached *acche din* much, much earlier but the fact is not like that. Everybody knows what the B.J.P. Government says and what is happening in the country are diametrically opposites. Their words go in one direction but the country's life goes to the opposite direction.

Sir, yesterday, in the speech in Lok Sabha, Madam F.M. talked about robust economy. She told one more thing. She told, 'why to compare India with Sri Lanka or Bangladesh? Compare it with the U.S.A.' Yes, we can compare India with the U.S.A. In the U.S.A., 1 per cent of the total population controls 37 per cent of the

† Transliteration in Urdu script.

wealth. In India, it is 77 per cent. You compare it. In the same way, compare the strength of the currency in the U.S.A. and here. I can predict here that within a couple of weeks sometimes our rupee would become hundred per dollar. This is what is happening. She talked about the banking system, the NPA and how they reduced it. I should call it a magic. What the F.M. did in the banking sector is a magic. The NPA is there but she did haircuts. Haircuts are nothing but giving concessions one after another to the looters and in that way they claim that they have reduced the NPA. The whole exercise of the Government in the economy is like that. And who are the sufferers, Sir? I have not much time, but still I want to read some items only. Kindly tell us vanaspati price, soya oil price, sunflower oil price, palm oil, packed salt, potato, tomato, wheat, atta, groundnut oil. The prices, the percentage here is on the increase. *Achche Din*! Sir, in this way I have only one request to the Finance Minister. While replying to the debate, kindly tell us, what will happen to MGNREGA. What will happen to it? You have reduced the funds. Kindly regain that fund and give to the poor people. What will happen to the health sector? What will you do for education, the problem of such persons? Sir, I would request the Finance Minister to read the manifesto of the BJP.

MR. CHAIRMAN: Right, Mr. Viswam. I have already given you four minutes. ...*(Interruptions)*....

SHRI BINOY VISWAM: I would request her to read the BMS resolution also. Then it will help her. Thank you.

MR. CHAIRMAN: I have given you four-and-a-half minutes. Now, Shri G.K. Vasan.

SHRI G.K. VASAN (Tamil Nadu): No doubt, Sir, price rise is a very important issue in the country and that is why, the Government has allowed all the Members to give their views on this. ...*(Interruptions)*... Sir, we have to understand that why there is price rise, how price rise and what are the ways by which the Government is tackling the price rise to end the problem of the common man. Number one, 2020 COVID. Even countries which are superpowers, were locked with economic problem. Countries which have 20-25 or 15 crores population, were in deep trouble. India with 140 crore people--you cannot imagine--we were able to feed 80 crore people in our country. That is number one. Number two, we had a package of Rs.25 lakh crores. And again, Rs.1.7 lakh crores so that we could give money to the needy people. That helped the economy to grow at that time. The second problem was the Ukraine-Russia War. They are the main suppliers of food and fuel. Superpower countries are still suffering.

We are the one of the countries which are negotiating with them on fuel with discount price. Many countries have gone bankrupt. Many countries are asking money from the world fund. Many countries have gone to recession. The next country is Pakistan. The regime itself has changed. Sri Lanka, because of their very bad economic management, has gone into internal crisis. Still, we were able to help them. I would like to thank the Finance Minister and Prime Minister on behalf of the Tamil people in Sri Lanka, that they have been helped so much. To conclude, I would like to say that price rise, being an important issue, concerns everybody in the country. Today, we have a stable economy but, still, we are seeing the GST and other revenue collection at a record high. Since the economy is slowly developing and improving, I am sure the hon. Finance Minister will take necessary steps to address the increase in the price level of the essential commodities. Thank you, Sir.

MR. CHAIRMAN: Now, Shri Jayant Chaudhary. You have two minutes.

श्री जयंत चौधरी (उत्तर प्रदेश) : सर, दो मिनट में तो मैगी बनती है और उस पर भी 12 परसेंट जीएसटी देना पड़ता है।

श्री सभापति : मैं क्या करूँ, यह जीएसटी काउंसिल का डिसीज़न है।

श्री जयंत चौधरी : सर, मुझसे पहले माननीय सदस्यों ने भी बात रखी। मैं पहले माननीया सुषमा स्वराज जी को श्रद्धांजलि दूँगा। इसमें कोई शक नहीं है, मुझे याद है, लोक सभा में मैंने उनके भाषण को सुना। जिस तरीके से जमीन से जुड़ी बात, एक गृहिणी का दर्द, घर-गृहस्थी की बात, मध्यम वर्ग और गरीब के दर्द और पीड़ा को वे बयान करती थीं, बखूबी तरीके से, उनसे प्रेरणा लेते हुए आज वह दायित्व हमारा है। हम कोशिश करेंगे, लेकिन सरकार भी ऐसी हो, जो सुने। मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूँ, क्योंकि हमने चर्चा की है और खाद्यान्न की महँगाई की दर पर सभी सदस्यों ने बात रखी, लेकिन जो मूल बात यहाँ सदन में हुई है, मैं उससे कुछ अलग राय रखता हूँ। जब हम महँगाई की बात करते हैं, तो हम तुरंत आलू, प्याज और टमाटर पर आ जाते हैं। क्या हमने सीमेंट, सरिया, ईंट की बात की, ट्रैक्टर के भाव की बात की? पम्प सेट्स के भाव कैसे बढ़ गये, उनकी बात की? क्या हम किसान की लागत की चर्चा कर पा रहे हैं? मैं आंकड़े दूंगा - अप्रैल से जून, 2020, ये जो तीन महीने हैं, अगर इनमें सीपीआई फूड इन्फ्लेशन आठ परसेंट रहा तो काफी होता है, मैं मान रहा हूं। उसी समय में डब्ल्यूपीआई फार्म इनपुट इन्फ्लेशन 27.4 प्रतिशत था। यहां मैं खुद का एक्सपीरियंस बताना चाहता हूं, कुछ अनुभव बताना चाहता हूं, अगर आंकड़ा गलत हो, तो यहां बहुत से ऐसे सदस्य हैं, जो खेती करते हैं, वे जानते हैं, वे बता दें। 2014 में अगर एक एकड़ के गेहूं के खेत की आप एक ट्रैक्टर से जुताई करते, तो औसतन आपके तीन हजार रुपये खर्च हो रहे थे, आज आठ साल के बाद 5,400 रुपये खर्च होते हैं। यदि एक एकड़ की धान की खेती आप करते, तो 300 रुपये का बीज आ जाता था, आज 600 रुपये लग रहे हैं। आपके खाद और दवाई

पर 2014 में यदि तीन हजार रुपये खर्च हो रहे थे, एक एकड़ पर धान की खेती करने वाले किसान के लिए आज 6 हजार रुपये तक वह आंकड़ा पहुंच गया है।

महोदय, हम सिर्फ महंगाई की बात करें, ठीक है, आपने स्कीम बनाई, 2018 में 500 करोड़ रुपये दिये, सवाल बनता है कि उस संसाधन का क्या प्रयोग हुआ? क्या हमने खाद्य प्रसंस्करण की इंडस्ट्री, फूड प्रोसेसिंग को बढ़ावा दिया है? क्या यह सचाई नहीं है कि जब बात टोमेटो से शुरू होती है, टमाटर की प्रोसेसिंग पर आप 12 परसेंट जीएसटी वसूलना चाहते हैं? क्या यह सचाई नहीं है कि पोटेटो को प्रोसेस करने के लिए अगर आप चिप्स बनायेंगे, नमकीन बनायेंगे, तो उस पर भी आप 12 परसेंट जीएसटी वसूलना चाहते हैं? यह भी एक कारण है कि जो फूड इन्फ्लेशन है, वह बेकाबू हो रहा है।

मैं वित्त मंत्री जी को सुझाव देना चाहता हूं कि सीपीआई में जो फूड का वेटेज़ है, अगर आप उसे घटा देंगे, तो ये जो बेवजह चर्चाएं होती हैं, आप पर भी उनका दबाव कम होगा। आप तुलना कीजिए, जर्मनी में सीपीआई का फूड का वेटेज क्या है, यह साढ़े आठ परसेंट है। ब्राज़ील में साढ़े पच्चीस परसेंट, चाइना में 19.9 परसेंट, पाकिस्तान में 35 परसेंट है और हमारे यहां 46 परसेंट है। इसलिए दूध का भाव यदि एक रुपया बढ़ जाएगा, तो त्राहि-त्राहि मच जाएगी, आप पर भी दबाव बन जाएगा और फिर आप व्यावहारिक फैसले नहीं ले पाती हैं। हमने देखा है, दुनिया ने देखा है, कॉमर्स मिनिस्ट्री डेलिगेशन तैयार कर रही थी, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री पीएम को ब्रीफ कर रही थी, प्रधान मंत्री जी यूरोप में कह रहे थे कि हम दुनिया का पेट भरेंगे, गेहूं का निर्यात करेंगे और कुछ ही दिन में आपने निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया। ऐसे फैसले न हों, ऐसी मेरी मांग है।

महोदय, मेरी वित्त मंत्री जी के साथ सहानुभूति है, क्योंकि जब से वे आई हैं, मजबूर होकर क्राइसेज़ मैनेजमेंट मोड में उन्होंने काम किया है, लेकिन हमें सिनेरियो प्लानिंग करनी चाहिए, भविष्य की प्लानिंग हमें बनानी होगी। मैं पूछना चाहता हूं कि आज मानसून डेफिशिएंसी है, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में जितनी औसतन बारिश होती थी, वह नहीं हुई है। उत्तर प्रदेश में 23 परसेंट धान की बुवाई कम हुई है। क्या वहां के कृषि मंत्री के विभाग ने कोई मीटिंग ली है? क्या आपने उनके साथ कोई बैठक की है? क्या आप उनके साथ बैठक करेंगी? इसका जवाब मैं आपके उत्तर में जानना चाहूंगा।

अंत में, जो आम आदमी कहता है कि उसके पास सारी चीजों का समाधान है। मैं बताना चाहता हूं कि एक आम आदमी ने मुझे कहा कि आप सदन में जा रहे हैं, चर्चा करेंगे, वहां यह समाधान दे दीजिएगा। मैंने पूछा क्या समाधान है? उसने कहा बहुत सरल है, इनकी सरकार पांच साल रहेगी, ऐसी व्यवस्था बना दो कि हर दो-तीन महीने में कहीं चुनाव करा दो और आप देखो कि सरकार डीजल, पेट्रोल, बिजली आदि का कोई भी रेट नहीं बढ़ने देगी, धन्यवाद।

श्री सभापति : इन्होंने कोई राजनीति नहीं की है, केवल सुझाव दिये हैं, उन्हें आप स्वीकार करें या न करें, वह अलग बात है। सचमुच में चर्चा ऐसी होनी चाहिए। श्री के. आर. सुरेश रेड्डी। Suresh Reddy*ji*, you have two minutes to speak. Sorry to say it.

SHRI K.R. SURESH REDDY (Telangana): Mr. Chairman, Sir, I do understand your predicaments but, at the same time, we are a seven-Member Party and my name

was on the listed Business today. But, of course, there was some communication gap between us and the Table which resulted in the name not being there. Nevertheless, Sir, I leave it to you and, of course, you have all the inherent powers for your indulgence. With deep anguish, today I must say that when the country is going through the period of what they call it the *Amrit Kal,* it is not prosperity but it is poverty and the loud cries of the common man which are resonating all across the nation. All very honourable, experienced Members across the parties, while speaking, Sir, I can sum it up and say the whole summary was cradle to crematorium. The kind of agony in the country and the poor people are facing has very explicitly been described in this House. So, all I can add to that is, after the debate probably अगर आम आदमी के पास कुछ बचा, तो उसके वसीयतनामा में कुछ जीएसटी का प्रोविजन अन्तिम यात्रा के लिए रखना चाहिए, so he will have a nice farewell before that. ...*(Interruptions)*.. My question, Sir, is between September 2021 and April 2022, the consumer food price inflation in India has risen from 0.68 to 8.38 per cent year on year. Currently, it stands at 7.1 per cent. The Wholesale Price Index was at a record high, which is the highest in 30 years, in May 2022, at 15.9. I would not go for a tedious repetition how the prices have gone up, but the excuse given needs to be looked into again. When we spoke about the sunflower oil, they said the Ukraine War is the reason. I can say with full confidence that it is not the Ukraine War. Ukraine also had a drought in 2020 and 2021. Russia had an export embargo for their essential commodities. But the war started in February of 2022. You cannot blame the Ukraine war for all the price rise which is happening in our country. Secondly, Sir, when we see the petroleum prices, I would not like to go into the full split of that, but one issue which I would like to bring to the notice of the House is that Central taxes and State taxes which make part of the entire pricing of a litre of petroleum product, in that there are various taxes from the Central Government, the Government of India. One such tax which we noticed is the Agriculture Cess. The Agriculture Cess, which is at 2.5 rupees per litre, this is being collected for agriculture infrastructure and development. During the course of the debate, many hon. Members have pointed out that there has been a high inflation in Telangana and some other States. I would like to know from the hon. Finance Minister in her reply as to what is the amount you spent on agriculture infrastructure. In the last seven years, I have not seen a single major irrigation project coming up in this country. I haven't seen any major incentives being given to the farmers. But in spite of this fact, you have been collecting it. For example, in my Telangana, where you say the inflation is high, Telangana, from the most backward regions in the country before it became a State, has become one of the top five contributors to the Indian economy in a span of seven years. How did we do this? It could be achieved

through the optimum utilization of river waters which meant a lot of expenditure had been incurred. Seeing the prosperity of Telangana, which is against the spirit of the federal structure on which the country thrives, they are trying to choke Telangana. You are trying to put curbs on our borrowings. You are trying to put curbs on various limitations. Now this way the development of Telangana is one area which would be affected, Sir. I would request the Finance Minister that the spirit of federalism doesn't choke States which are progressing and which are contributing to the country.

MR. CHAIRMAN: Thank you, Sureshji.

SHRI K.R. SURESH REDDY: Finally, Sir, one last point. Everything was spoken one about the Russian war and the other was on the pandemic. But we have to see a lot of mismanagement happening even before the pandemic, it happened during demonetization. The hon. Finance Minister spoke so highly of Raghuram Rajan, and spoke about what he said, in the Lok Sabha, but I would like to quote one last point before I close. Raghuram Rajan has also said the other day in a conference in Raipur that Sri Lanka was an example of what happens when a country's politicians try to deflect a job crisis by targeting minorities. Your failures, your mismanagement should not be taken with pandemic as a reason. So, with these words-- of course, I had a lot, but with due respect to the Chair-- I thank you, Sir.

MR. CHAIRMAN: Mr. Suresh Reddy is the former Speaker. He has experience of time management.

DR. K. LAXMAN (Uttar Pradesh): Mr. Chairman, Sir, at the outset, I would like to thank you for giving me a chance to speak on the subject of price rise for the first time in this august House. Sir, I hail from Telangana, but I have been given an opportunity to get elected from Uttar Pradesh for Rajya Sabha. I am really grateful to my Leader, Modiji and our President, Naddaji for giving me a chance. As a person from Telangana, it is my bounden duty to speak on behalf of the Telangana people and to see that the interests of Telangana and the welfare of Telangana is spoken here and I would like to become the voice of the Telangana people in this august House because I am the first Rajya Sabha Member from Telangana by a ruling party and my party has given me the chance. At the same time, I would like to take the responsibility to say how being a Rajya Sabha Member from Uttar Pradesh, how my Government, under the leadership of Modiji and Yogiji, the double engine *sarkar*, is working day and night for the development and also for the empowerment of the downtrodden, the weaker

sections and the poor of the society. Mr. Chairman, Sir, in spite of this pandemic situation and the entire world facing economic crisis, our visionary leader Narendra Modiji was able to contain inflation and was able to control the price rise. I have been hearing co-Parliamentarians from Telangana speaking about price rise. I really fail to understand and I feel they have no moral right to speak on price rise because I would like to share some facts about how these Telangana people are suffering due to increase in prices. I would like to take three examples, Sir, with due permission. As soon as fuel charges were confirmed, the Union Government reduced twice, not once, and all the BJP-ruled States also reduced the prices right from Rs. 15 to Rs. 5, lessening the burden of the common man to the tune of Rs. 20-25. I have seen in Uttar Pradesh for the last one year, it is almost Rs. 20-25 on petrol and diesel. This is the concern of the Government towards the common and poor sections, whereas in Telangana, our Chief Minister * proudly says, 'I am not going to increase a single paisa which the State collects in the name of VAT'. I am sorry, Sir, the State Government collects on petrol 35 per cent as VAT and 27 per cent on diesel as VAT. Altogether, from 2014-2022, this Government has collected not less than Rs. 70,000 crores as VAT. Unfortunately, the Centre which collects, in the name of excise duty, 41 per cent share goes to the State again. This is Telangana Government's concern towards the poor and the common man! When it comes to increase of land value, twice in a span of five months, the Government has increased the land value. Not only the land value has increased up to 50-60 per cent, on which they have made money out of that, but they have also increased the stamp duty from six per cent to seven-and-a-half per cent and the market value of the land has also increased from 50-60 per cent. Apart from this, the common man relies on public transport and 50 per cent has been increased on the public transport system to the tune of Rs. 5,596 crores. It is a burden on the common man. ...*(Interruptions)*... For your information, the Government itself has due to the RTC not less than to the tune of Rs. 17,120 crores, out of which Rs. 12,598 crores are due. This Government claims to be a surplus Budget State, but unfortunately, now it is in debt of Rs. 3.5 lakh crores. Our students, the poorer sections and the common man rely on bus passes. Now the bus pass fee has increased from Rs. 160 to Rs. 450 per month. ...*(Interruptions)*... My friends spoke a lot about irrigation and concern towards farmers. Unfortunately, one project by name, Kaleshwaram, was redesigned. It was a Rs. 30,000 crore project, but enhanced to Rs. 1.20 lakh crores. Already they spent Rs. 80,000 crores, but of no use. Sir, due to recent floods and rains, all pumps in the pump house were submerged! ...*(Interruptions)*...

---

* Not recorded.

MR. CHAIRMAN: Mr. Laxman, you have to conclude. ...*(Interruptions)*... You have to conclude. ...*(Interruptions)*... Please sit down. ...*(Interruptions)*...

DR. K. LAXMAN: It is learnt that hundreds of crores of rupees have to be spent for their repair! ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: Listen, his party has given him time. ...*(Interruptions)*...

DR. K. LAXMAN: It will take more than one year to get them repaired! This is the vision of our Chief Minister where public money is being wasted. Finally, I would just like to compare the UP model with Telangana. मैं उत्तर प्रदेश का भ्रमण करता हूँ, मैं चुनाव के समय भी वहाँ गया था। मोदी जी के द्वारा लगभग 3,50,000 करोड़ खर्च करके 80 करोड़ की आबादी को हर महीने पाँच किलो नि:शुल्क राशन दिया जा रहा है। हमारी तेलंगाना सरकार ने तीन महीने से वह पाँच किलो राशन भी बंद कर दिया है, गरीब को मारा है। ...**(व्यवधान)**... कोई गरीब भूखा पेट नहीं सोए, इसके लिए हमारे प्रधान मंत्री, मोदी जी के अलावा, हमारे मुख्य मंत्री योगी जी के द्वारा चावल के अलावा, नमक के साथ गेहूँ, दाल, चीनी, तेल हर महीने दो बार दिया जाता है। ...**(व्यवधान)**... देश के किसी भी प्रदेश में इस तरह राशन नहीं दिया जा रहा है। ...**(व्यवधान)**... हमारे उत्तर प्रदेश में जो डबल इंजन सरकार है और हमारे जो भी बीजेपी शासित राज्य हैं, वे हमारे गरीब, वंचित, शोषित, पीड़ित, दलित, किसान के लिए काम करने वाले हैं। मोदी जी गरीबों के मसीहा हैं। तेलंगाना के लोग आज तबाह हो गए हैं, वे आज बदलाव चाह रहे हैं। ...**(व्यवधान)**... हम तेलंगाना की आबादी को यह विश्वास दिलाते हैं कि तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी सरकार में आ सके, इसके लिए हम काम करेंगे।

MR. CHAIRMAN: Secretariat to take note. Any reference to Chief Minister by name will not go on record. That has been the practice. Of course, other things can go. Name of the Chief Minister of Telangana should not go on record. Now, Shri Ajit Kumar Bhuyan. You have two minutes. Almost all the parties have exhausted their time.

SHRI AJIT KUMAR BHUYAN (Assam): Thank you hon. Chairman, Sir. Since I get a very short time, I will raise only a few points. But, I think, touching of such points is enough as the Government already knows everything and, tragically enough, hides everything.

Sir, from flood to price hike, the people of my State, Assam are suffering like hell and the Government goes with the same rhetoric, we cannot control price hike for these reasons. If you can give neither job nor food or relief from calamities like floods, why is there Government at all is my question.

Sir, I cannot understand why pathetic financial condition of the country and its people's financial penury is directly proportionate to the meteoric rise of a selected few. The most recent data released by the Ministry of Statistics and Programme Implementation, Government of India, shows that the rate of inflation in India, in the month of July, 2002, has been 7 per cent, while that of food inflation has been 7.75 per cent. If we look commodity-wise, we will find that the rate of inflation has been as high as 17 per cent in case of vegetables, 9 per cent for oils, 8.6 per cent for fish and meats, 10.39 per cent for fuel and light and 9.5 per cent on clothing and footwear.

Sir, it should also be noted that the rate of inflation in the country has remained over 6 per cent for quite some time now. For instance, if we consider the period since January, 2020, the average rate of inflation in India has been 6.17 per cent for the last thirty months!

Sir, why the data of various reputed international organizations on India's development index differ from our Government's data? This is my question. Now, are we manipulating even statistics of our development! To whom are we lying actually?

6.00 P.M.

What is important here is to realise that in demand constrained condition particularly, the condition arising out of the pandemic, inflation is caused only by increasing costs. A series of hikes in fuel prices, including petro products and LPGs, have only aggravated the situation.

MR. CHAIRMAN: Right, Ajit Kumar*ji*.

SHRI AJIT KUMAR BHUYAN: Sir, one minute. The present inflation is thus triggered by faulty administrative decisions. But to control inflation, the Government needs to have sufficient handles. The question is: Does the Government have sufficient handles to contain inflation? We are failing, Sir. I just want to remind this House that if we do not do anything, it will be an endless backward journey. Thank you, Sir.

MR. CHAIRMAN: Hon. Members, it is Short Duration Discussion. The Short Duration Discussion is normally of two-and-a-half hours. Because of the importance of the subject, on the request of the Members, I extended it by another one-and-a-half hour, making it four hours. Now, four hours are over. There are still some speakers left and the Minister has to give response to all these issues raised. So, the House is extended to sit beyond six o'clock till we complete the Business today for the other

speakers and also for the response by the hon. Minister. Now, Shri Sushil Kumar Modi.

श्री सुशील कुमार मोदी (बिहार) : सभापति महोदय, आज जीएसटी को लेकर सदन में काफी चर्चा हुई है। यद्यपि सरकार ने बार-बार कहा है...

MR. CHAIRMAN: You have ten minutes' time. Keep that in mind.

SHRI SUSHIL KUMAR MODI: Sir, the Government has reiterated that it was a unanimous decision in the Fitment Committee, in the Group of Ministers and even in the GST Council.

[THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA) *in the Chair.*]

But somehow, my Members from Opposition are saying, 'No; we opposed this increase of GST.' मैं केवल एक ही सवाल का जवाब जानना चाहता हूँ कि अगर आपने विरोध किया, तो वोटिंग क्यों नहीं कराई? जीएसटी काउंसिल में वोटिंग का प्रावधान है। अगर आपने विरोध किया और आपकी बात को स्वीकार नहीं किया गया, तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि क्या आपने वोटिंग के लिए फोर्स किया, क्या आपने वोटिंग करवाई और अगर नहीं कराई तो क्यों नहीं कराई? उपसभाध्यक्ष महोदय, सच्चाई तो यह है कि यह निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा। एक राज्य के वित्त मंत्री ने यहाँ तक कहा कि इस पर कोई चर्चा की जरूरत नहीं है, इसको सर्वसम्मति से पारित कर दिया जाए।

उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं यह भी जानना चाहता हूँ कि अगर आपका विरोध है, तो आपने नोटिफाई क्यों किया? On 18th of July, each and every State including Congress-ruled or TMC or CPM notified this increase of GST. आपने पश्चिमी बंगाल में क्यों नोटिफाई किया? आप रोक देते कि हम नोटिफाई नहीं करेंगे। आपने केरल में क्यों किया? आपने तमिलनाडु में क्यों किया? आपने टैक्स इन्क्रीज़ को नोटिफाई किया, it means you are in favour of increasing of GST rate tax और अब आप कह रहे हैं कि हमने तो साथ नहीं दिया था। महोदय, यह बार-बार कहा जा रहा है। मैंने केरल के मुख्य मंत्री का बयान देखा कि हम इसको लागू नहीं करेंगे। मेरा कहना है कि अगर हिम्मत है तो जो अपोज़िशन-रूल्ड स्टेट्स हैं, वे घोषणा करें कि इस इन्क्रीज़ को अपने राज्य में लागू नहीं करेंगे। अगर हिम्मत है, तो वे एलान करें। लेकिन, उन सबों ने इसको लागू कर दिया और अब यहाँ पर धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं तो आग्रह करूँगा कि अगर आपको गरीबों की इतनी ही चिन्ता है, तो आप एलान कीजिए कि आप रीइम्बर्स करेंगे। There is a provision of reimbursement. They will not levy any tax on the consumer, but they will reimburse the tax to the shopkeepers. आप अनाउंस कर दीजिए कि रीइम्बर्स करेंगे। अभी भी समय है, आप जीएसटी काउंसिल की अगली बैठक में विदड्रॉ करने का प्रस्ताव ला सकते हैं। इसके पहले भी जीएसटी काउंसिल की बैठक में 300 से ज्यादा चीज़ों पर जो टैक्स इन्क्रीज़ हुआ,

उसको वापस लिया गया। आप एलान कीजिए कि जीएसटी काउंसिल की अगली बैठक में हम इस निर्णय को वापस लेंगे।

उपसभाध्यक्ष महोदय, यह जीएसटी काउंसिल का फैसला है। यह केन्द्र सरकार का फैसला नहीं है। केन्द्र सरकार वहाँ मौजूद थी, केन्द्र सरकार वहाँ उपस्थित थी, लेकिन सर्वसम्मति से यह फैसला लिया गया। चाहे वह कांग्रेस हो या टीएमसी हो, सभी ने सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया है। उपसभाध्यक्ष महोदय, आश्चर्य की बात है कि एक पार्टी के लोग कह रहे हैं कि 'जीएसटी को स्क्रैप कर देना चाहिए। अगर हमारी सरकार बनी तो नया जीएसटी लाएंगे', वे कहते हैं कि सिंगल रेट होना चाहिए। आप अगली मीटिंग में प्रस्ताव लाइए। क्या आज तक आप कोई प्रस्ताव लाए कि सिंगल रेट होगा? क्या चप्पल पर जो टैक्स लगेगा, वही टैक्स मर्सिडीज़ कार पर भी लगेगा! अगर हिम्मत है तो जीएसटी काउन्सिल की अगली बैठक में bring a Resolution that there will not be four slabs of taxes, but there will be only one slab of taxes. महोदय, आपने वहां सर्वसम्मति से निर्णय कर दिया और यहां पर आप उसका विरोध कर रहे हैं। इनको विरोध करने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है।

महोदय, जहां तक इन्फ्लेशन की बात है। यह इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन है। यह आयातित महंगाई है। यह देश की अर्थव्यवस्था के मिसमैनेजमेंट के कारण पैदा हुई महंगाई नहीं है। यह इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन है। यह जो इन्फ्लेशन है, 'India's import dependency is a Congress legacy'. मैं कॉंग्रेस के नेताओं से जानना चाहता हूं कि अगर आज़ादी के 75 साल के बाद भी 85 परसेंट क्रूड ऑयल इम्पोर्ट करना पड़ रहा है, तो क्या आप इसके लिए ज़िम्मेदार नहीं हैं? जो खाद्य तेल है, पाम ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, सोयाबीन ऑयल, अगर हमें आज 60 परसेंट एडिबल ऑयल इम्पोर्ट करना पड़ता है, तो आपने क्या प्रयास किया कि वह इम्पोर्ट न करना पड़े? महोदय, हम 58 परसेंट नेचुरल गैस इम्पोर्ट करते हैं। 75 साल में आपने क्या प्रयास किए कि उसे इम्पोर्ट नहीं करना पड़े? महोदय, हम 60 परसेंट फर्टिलाइज़र इम्पोर्ट करते हैं। आज जो सारी महंगाई है, यह 3F के कारण है, 'Fuel, Food and Fertilizer'. ये तीनों चीज़ें हैं, जिन्हें हम विश्व के बाज़ार से आयात करते हैं। महोदय, 3R - Russia, Rate and Recession - ये तीन बड़े कारण हैं, जिनके कारण यह स्थिति यहां पैदा हो रही है।

महोदय, मेरे पूर्व के लोगों ने विस्तार से ज़िक्र किया है कि अमेरिका में इन्फ्लेशन कितना है। वह 2 परसेंट था, that is increased to 9.1 per cent. कनाडा में 8.1 परसेंट है, यूके में 9.4 परसेंट इन्फ्लेशन है, and that is going to be increased to 11 per cent in the coming days. आज पूरी दुनिया में विरोध हो रहा है, पूरी दुनिया के अंदर आंदोलन हो रहा है। मैं सदन को बताना चाहूंगा कि इंग्लैंड के अंदर वेजेज़ को बढ़ाने के लिए रेलवे की स्ट्राइक हो गई, ज़िम्बाब्वे में नर्सेज़ ने स्ट्राइक कर दी, बेल्जियम के अंदर वर्कर्स की स्ट्राइक हुई - साउथ कोरिया, स्पेन, पेरू, अफगानिस्तान, यमन, म्यांमार, हैती, ब्रुसेल्स, लेबनान, इराक, केन्या, ट्यूनीशिया, बुर्किना फासो, आदि दुनिया के 50 से ज्यादा देशों में महंगाई के विरोध में जनता सड़कों पर आ गई, लेकिन यह नरेन्द्र मोदी जी का कमाल है कि इन्होंने महंगाई को नियंत्रित करके रखा और आपके प्रयास के बावजूद कोई सड़कों पर नहीं आया। पोलिटिकल पार्टीज़ के प्रदर्शन के अलावा कहीं जनता सड़कों पर नहीं आयी, क्योंकि जनता को मालूम है कि यह महंगाई यूक्रेन के कारण है, जनता को मालूम है कि अंतरराष्ट्रीय बाज़ार में अगर फर्टिलाइज़र का दाम नहीं बढ़ा होता, तो

भारत में फर्टिलाइज़र का दाम नहीं बढ़ा होता। महोदय, जनता को यह मालूम है कि फ्यूल से लेकर बाकी चीज़ों का ...**(समय की घंटी)**... महोदय, आपने 10 मिनट का समय दिया था।

उपसभाध्यक्ष (श्री भुबनेश्वर कालिता) : अभी पार्टी ने समय कम कर दिया। 7-7 मिनट का समय कर दिया है।

श्री सुशील कुमार मोदी : आपने मुझे नहीं बोला कि कम कर दिया है, आपने कहा कि 10 मिनट का समय है, इसलिए मैं 10 मिनट को ध्यान में रखकर बोल रहा था। महोदय, चेयरमैन साहब ने 10 मिनट का समय दिया था।

महोदय, मैं केवल यही कहना चाहूंगा कि यह जो महंगाई है, वह चाहे फर्टिलाइज़र की महंगाई हो - फर्टिलाइज़र का दाम अंतरराष्ट्रीय बाज़ार में बढ़ा, लेकिन हमने किसानों के लिए दाम बढ़ने नहीं दिया, हमने उनको सब्सिडी दी। हमने 62 हज़ार करोड़ रुपये की सब्सिडी दी है, नई सब्सिडी दी है और अब सरकार ने एलान किया है कि वर्ष 2025 के बाद हम यूरिया का इम्पोर्ट नहीं करेंगे। यह भारत सरकार की हिम्मत है कि वर्ष 2025 के बाद हम यूरिया का इम्पोर्ट नहीं करेंगे। अगर हम यूरिया का इम्पोर्ट नहीं करेंगे, तो उससे 40 हज़ार करोड़ की बचत होगी, हम कितनी सब्सिडी दे रहे हैं? मैं सदन को बताना चाहूंगा कि यह जो यूरिया है, उसका प्राइस 2,450 रुपये है और हम 2,184 रुपये सब्सिडी दे रहे हैं, यानी 2,450 रुपये की यूरिया केवल 266 रुपये में हम किसानों को दे रहे हैं। डीएपी का दाम 4,073 रुपये है और हम 1,350 रुपये में दे रहे हैं। एनपीके का दाम 3,291 रुपये है और हम 1,470 रुपये में दे रहे हैं। एमओपी का दाम 2,654 रुपये है, लेकिन हम 1,700 रुपये में दे रहे हैं। महोदय, अगर नरेन्द्र मोदी जी नहीं होते, तो आज भारत में महंगाई की दर जो 7 प्रतिशत है, मैं दावा करता हूं यह 20 परसेंट पर पहुंच गई होती। महोदय, समय नहीं है। मेरे पूर्व के लोगों ने आंकड़ा दिया है कि यूपीए के समय में क्या हुआ, इन्फ्लेशन का रेट क्या था, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के समय भारत के अंदर इन्फ्लेशन का रेट क्या था, टेम्पर टेन्ट्रम के समय इन्फ्लेशन का रेट क्या था? हम आज 7.01 पर है और मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं अब यूक्रेन से सनफ्लॉवर का एक्सपोर्ट प्रारंभ हो गया है, यूक्रेन से गेहूं का एक्सपोर्ट प्रारंभ हो गया है। माननीय घनश्याम तिवाड़ी जी ने ठीक कहा है कि नरेन्द्र मोदी जी थे, जिन्होंने रूस-यूक्रेन युद्ध के दौरान और अमेरिका की बिना परवाह किए, सैंक्शन की बिना परवाह किए रूस से केवल कच्चा तेल ही नहीं, बल्कि रूस से फर्टिलाइज़र, कच्चा तेल और अन्य चीज़ों को सस्ते दाम पर मंगवा कर गरीबों को देने का काम किया है।

उपसभाध्यक्ष (श्री भुबनेश्वर कालिता) : प्लीज़, आप कन्क्लूड कीजिए। आपका दस मिनट का समय पूरा हो चुका है।

श्री सुशील कुमार मोदी : सर, मैं कन्क्लूड कर रहा हूं, इसलिए मैं भारत के प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहूंगा, जिन्होंने प्रोएक्टिव होकर महंगाई को नियंत्रित करने का प्रयास किया है। प्रोएक्टिव पॉलिसीज़ बढ़ाई हैं और आगे आने वाले दिनों में भी हम महंगाई को 7

परसेंट से आगे नहीं जाने देंगे। उपसभाध्यक्ष महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। आपने समय दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

DR. FAUZIA KHAN: Sir, I have a point of order. ...*(Interruptions)*...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): I have already called the next speaker. ...*(Interruptions)*...

डा. राधा मोहन दास अग्रवाल (उत्तर प्रदेश) : माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बातें चार बिंदुओं पर आपके सामने रखता हूं।...**(व्यवधान)**...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): Under what rule is it?

DR. FAUZIA KHAN: Sir, it is under Rule 261. This is defamatory to Maharashtra when hon. Member was saying that nobody opposed anything in the GST Council. Maharashtra Government has written an open letter saying that this GST must not be applied to food products. ...*(Interruptions)*...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): He is not talking about the open letter. ...*(Interruptions)*... He is talking about the Council. ...*(Interruptions)*...
DR. FAUZIA KHAN: How can he say it? ...*(Interruptions)*... He can't say that nobody opposed it. ...*(Interruptions)*...

उपसभाध्यक्ष (श्री भुबनेश्वर कालिता) : काउंसिल की बात कर रहे हैं, लैटर की बात नहीं कर रहे हैं।...**(व्यवधान)**... लैटर में या हाउस में ज़िक्र करने की बात नहीं कर रहे हैं।...**(व्यवधान)**...

DR. FAUZIA KHAN: The Maharashtra Government has written a letter. ...*(Interruptions)*...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): Your point of order is ruled out. ...*(Interruptions)*... It doesn't come under any rule. ...*(Interruptions)*...

डा. राधा मोहन दास अग्रवाल : माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, महंगाई की इस महत्वपूर्ण बहस पर मैं चार बिंदुओं पर अपनी बातें रखूंगा। क्या यह महंगाई पहली बार भारत में आई है? क्या भारत के भाजपा शासित राज्यों और गैर-भाजपा राज्यों के बीच में महंगाई एक-सी है, क्या भारत का विकास इससे प्रभावित हुआ है और महंगाई पर ये तथाकथित नेता ज्यादा समझदार हैं या इस देश की जनता ज्यादा समझदार है? महोदय, 75 साल के शासन में पहले 27 साल कांग्रेस का

शासन था और महंगाई की दर 13 प्रतिशत से लेकर 28 प्रतिशत तक थी। फिर बीच में जनता पार्टी का शासन आया और जनता पार्टी ने खींचकर महंगाई की दर 2.52 परसेंट तक ला दी। फिर कांग्रेस का शासन आया और तकरीबन 15 साल कांग्रेस की सरकार रही और महंगाई फिर बढ़कर 10 परसेंट से लेकर 11.35 परसेंट हो गई। उसके बाद फिर अटल जी की सरकार आई और अटल जी की सरकार में महंगाई 1999 में 4.67 परसेंट, 2000 में 4.01 परसेंट, 2001 में 3.75 परसेंट, 2002 में 4.3 परसेंट और 2004 में 3.77 परसेंट रही। यानी फिर भाजपा की सरकार आने पर महंगाई घट गई। उसके बाद एक अर्थशास्त्री प्रधान मंत्री बनकर हम लोगों के बीच में आए। 2009 में 10.88 प्रतिशत महंगाई थी, 2010 में 11.99 परसेंट महंगाई थी, 2011 में 8.91 प्रतिशत महंगाई थी, 2012 में 9.48 प्रतिशत महंगाई थी, 2013 में 10.02 परसेंट महंगाई थी। यह एक अर्थशास्त्री प्रधान मंत्री के दौरान इस देश की महंगाई थी। फिर आए चाय बेचने वाले हमारे प्रधान मंत्री, जिन पर आज पूरा देश गर्व करता है। कबीर दास ने लिखा है:

"पोथी पढ़ि पढ़ि जग मुआ, पंडित भया न कोय,
ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होय"।

गरीबों के बीच में जीने वाले उस मोदी ने महंगाई को 2014 में 6.77, 2015 में 4.91, 2016 में 4.95, 2017 में 3.33, 2018 में 3.94, 2019 में 3.75 और 2021 में 5 परसेंट कर दिया। यह कार्यकाल था माननीय मोदी जी का। यह पिछले आठ सालों का एक ऐतिहासिक कार्यकाल है। मैं अपने छात्र जीवन में सुनता था, 'जब-जब कांग्रेस आई है, कमर तोड़ महंगाई है।' अब समझ में आता है और ये आंकड़े बताते हैं कि सच्चाई क्या है।

उपसभाध्यक्ष महोदय, दूसरी बात, आज के दिन जो वर्तमान की महंगाई है - उत्तर प्रदेश में भाजपा का शासन है, वहां महंगाई 6.7 और देश का एवरेज 7.1 प्रतिशत है, उत्तराखंड में भाजपा का शासन है, वहां महंगाई की दर 6.04 परसेंट है, मध्य प्रदेश में भाजपा का शासन है, वहां थोड़ी सी ज्यादा है, 7.16 परसेंट है, बिहार में भाजपा की सम्मिलित सरकार है, महंगाई 5.97 प्रतिशत है। गैर भाजपा शासित राज्यों में - तेलंगाना में 10.05 प्रतिशत है, पुडुचेरी में 10.09 प्रतिशत, राजस्थान में 7.79 प्रतिशत, ओडिशा में 7.71 प्रतिशत, आंध्र प्रदेश में 8.63 प्रतिशत, लक्षद्वीप में 9.6 प्रतिशत, महाराष्ट्र में हमारी सरकार के पहले के आंकड़े के अनुसार 8.52 प्रतिशत है। यानी देश में 7.1 प्रतिशत महंगाई के बावजूद, इस देश में जितने भाजपा शासित राज्य हैं, सभी में महंगाई बहुत कम है और जितने भी गैर-भाजपा शासित राज्य हैं, उन सभी में महंगाई बहुत ज्यादा है।

उपसभाध्यक्ष महोदय, तीसरी बात मैं आंकड़ों से ही कहूंगा। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई है। दुनिया में विकास की दर 4.8 प्रतिशत है। अरब देश में 1.6 प्रतिशत है, पूर्वी एशिया और जापान में 5.5 प्रतिशत, लैटिन अमेरिका और कैरेबिया में 5.8 प्रतिशत, यूके में 7 प्रतिशत, यूएसए में 5.5 प्रतिशत, रूस में माइनस 2.8 परसेंट, इटली में 7.3 परसेंट है और भारत की विकास की दर 22 मार्च, 2022 की वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के हिसाब से दुनिया में सबसे अधिक रिकॉर्ड 7.9 प्रतिशत है। यह वर्ल्ड बैंक की ऑफिशियल रिपोर्ट है।

अब मैं अंतिम बात कहना चाहूंगा। महंगाई इनको दिखती है, जनता को नहीं। ...**(व्यवधान)**... मैंने वर्ल्ड बैंक के बारे में बताया। आप सुनिए, थोड़ा पढ़िए और सोर्स खोज लीजिए। ...**(व्यवधान)**... मैंने आपको बताया वर्ल्ड बैंक के संबंध में, फिर भी आप न पढ़ना चाहें, तो कोई कुछ नहीं कर सकता है। ...**(व्यवधान)**...

उपसभाध्यक्ष (श्री भुबनेश्वर कालिता) : आप चेयर को एड्रेस कीजिए।

डा. राधा मोहन दास अग्रवाल : महोदय, मोदी जी सरकार में आए थे, 2015 में प्रति व्यक्ति आय 86 हज़ार रुपये थी, 2016 में वह बढ़कर 94 हज़ार हो गई, 2017 में 1 लाख 4 हज़ार हो गई, 2018 में 1 लाख 14 हज़ार हो गई, 2019 में 1 लाख 26 हज़ार हो गई, 2020 में 1 लाख 35 हज़ार हो गई और आज हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि भारत की प्रति व्यक्ति आय 1 लाख 50 हज़ार रुपये है। इस कार्यकाल में हमारी आय पिछले एक साल के मुकाबले 18 परसेंट बढ़ी है और मोदी जी के कार्यकाल में 80 परसेंट बढ़ी है। महंगाई 7 परसेंट है, मैं मान लेता हूं कि महंगाई में फूड का इन्फ्लेशन 14 परसेंट है और पिछले एक साल की आय 18.5 परसेंट है। यही कारण है कि हमारे देश के नागरिक इस बात को जानते हैं कि हमारे पास एक प्रधान मंत्री है, जो अनवरत इस बात के लिए काम करता है कि कैसे इस देश के गरीब नागरिक को उसकी गरीबी का एहसास न होने दिया जाए। आज दुनिया मोदी इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ रही है कि वह कौन सा तरीका है कि कोरोना काल में इतनी समस्याएं आईं, लेकिन इस देश का एक भी गरीब सड़क पर निकलकर नहीं आया। खर्चे सिर्फ अनाज के नहीं होते, खर्चे मकान के होते हैं, जो मोदी जी ने दिये, खर्चे बिजली के होते हैं, जो मोदी जी ने दिये, खर्चे पढ़ाई के होते हैं, जो मोदी जी ने दिये, खर्चे इलाज के होते हैं, जो मोदी जी ने दिये। सर, खर्चे अनाज के होते हैं, ..**(व्यवधान)**...जिसको मोदी जी ने इतना दिया है कि लोग अपने घरों में नहीं रख पा रहे हैं। मैं इस पूरी बहस को एक शुद्ध राजनीतिक बहस कहते हुए कंडेम करता हूं। ..**(व्यवधान)**..

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): Next speaker is Shrimati Geeta alias Chandraprabha. ...*(Interruptions)*... Dr. John Brittas, please take your seat. ...*(Interruptions)*... Geeta ji, please speak.

श्रीमती गीता उर्फ चंद्रप्रभा (उत्तर प्रदेश) : उपसभाध्यक्ष जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आज मुझे महंगाई पर हो रही चर्चा में भाग लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ..**(व्यवधान)**..मैं दो सप्ताह से देख रही हूं कि विपक्ष के लोग लगातार सदन में हंगामा कर रहे हैं, जबकि हमारी सरकार महंगाई पर चर्चा करने के लिए लगातार तैयार थी, फिर भी दो सप्ताह तक सदन को नहीं चलने दिया गया। महंगाई का रोना रोते हुए इनको स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि इस सदन को चलाने में कितना खर्च होता है, परंतु इन्होंने उसके बाद भी सदन नहीं चलने दिया। मैं आपके माध्यम से सदन ..**(व्यवधान)**..मैं मजबूर होकर ..**(व्यवधान)**.. सदन के सामने कुछ आंकड़े रखना चाहती हूँ। अभी हमारे भाई ने आंकड़े रखे हैं, मैं ज्यादा रिपीट नहीं करूंगी, लेकिन यह बात सच है कि ये आंकड़े भारतीय जनता पार्टी के नहीं, ये आंकड़े भारत सरकार के नहीं, बल्कि ये आंकड़े

विश्व बैंक के हैं, जिन्हें मैं आपके समक्ष रखना चाहती हूं। मान्यवर, कम से कम इसलिए भी विपक्ष के बंधुओं को इन आंकड़ों पर विश्वास करना ही पड़ेगा।

महोदय, हमारे भारत के गौरव आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, जब 1998 में प्रधान मंत्री बने थे, उस समय उन्हें महंगाई का आंकड़ा 13.2 परसेंट के रूप में मिला था, परंतु उतनी विषम परिस्थितियों में भी आदरणीय अटल जी ने उन चुनौतियों को स्वीकारा और 1998 के बाद वाजपेयी जी ने अपनी अच्छी कार्य शैली और अच्छे तरीके से इसको प्रति वर्ष कम किया। महोदय, मैं इसको दोहराना नहीं चाहूंगी। 1998 में, जब उन्हें 13.2 परसेंट के रूप में महंगाई की दर मिली थी, तब उसके बाद, 2004 में उन्होंने महंगाई को 3.7 परसेंट की दर पर छोड़ा था। महोदय, इन आंकड़ों से यह स्पष्ट होता है कि अटल जी की सरकार बनने से पहले देश महंगाई की मार से जूझ रहा था, देश के लोग महंगाई से मर रहे थे। उसके बाद भी प्रति वर्ष - महोदय, मैंने जिस तरीके से अभी आंकड़े बताए कि 2004 के बाद आदरणीय मनमोहन सिंह जी जब प्रधान मंत्री बने, तो इन्होंने इसको 3.7 परसेंट से बढ़ाकर देश के लाल, आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी के हाथ में 11 फीसदी दर की महंगाई के स्तर पर छोड़ा था। इससे यह स्पष्ट होता है कि इन दस वर्षों में महंगाई न सिर्फ बढ़ी, बल्कि इसकी रफ्तार भी बहुत तेज़ थी।

उपसभाध्यक्ष महोदय, आप खुद समझिए कि 2004 में 3.7 परसेंट से 2013 में जब 11 परसेंट की दर पर छोड़ा था, तो वह उनकी नीतियों को स्पष्ट दर्शाता है। मैं इस सदन के माध्यम से यह बताना चाहती हूं कि गरीबी में जीवन यापन करने वाले देश के ऐसे लाल के पास जब नीतियों में सुधार करने का अवसर आया, तो आदरणीय प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने 2014 से लेकर अब तक, विषम परिस्थितियों में भी, 2020 में कोरोना जैसी महामारी के आने के पश्चात् भी कार्य किया। देश में लॉकडाउन लगा, कई महीनों तक आर्थिक गतिविधियाँ भी ठप रहीं और उसका लाखों लोगों की आजीविका पर भी असर पड़ा। लोगों के व्यापार ठप हो गये, लोगों की नौकरियां चली गईं तथा लोगों की बचत रोज़मर्रा की चीजें जुटाने में खर्च हुई, इसके पश्चात भी 2020 में हमारी सरकार ने महंगाई की दर 6.6 प्रतिशत से बढ़ने नहीं दी। इससे स्पष्ट है कि हमारी सरकार, हमारे प्रधान मंत्री जी कितने संवेदनशील हैं। आप सभी लोग जानते हैं, विपक्ष के साथी भी जानते हैं, अभी मैं देख रही थी, आदरणीय शक्तिसिंह जी जिस तरीके से आरोप लगा रहे थे, बहन रजनी जी आरोप लगा रही थीं, मैं उनको बताना चाहती हूं कि आप स्वयं जानते हैं कि इस बार अनेकों अन्तरराष्ट्रीय विषयों, जैसे यूक्रेन युद्ध, अन्तरराष्ट्रीय बाजार मंदी और अनेकों अन्य विषय रहे, जिनका प्रभाव भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ा। इसके पश्चात भी इस वर्ष महंगाई की दर 7 फीसदी से ज्यादा नहीं रही है, इसलिए स्पष्ट समझ से मैं अपने प्रधान मंत्री जी का पुनः यहां से आभार व्यक्त करती हूं कि देश के नागरिकों के लिए वे कितने संवेदनशील हैं, जिन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था को बरकरार रखते हुए समूचे विश्व को, मंदी में जूझ रहे विश्व को एक रास्ता दिखाया है। अपनी कमजोर आर्थिक नीति के कारण श्रीलंका की स्थिति को भी हमने देखा है। पिछले सात वर्षों में सरकार द्वारा बनाई गई मजबूत आर्थिक नीतियों के कारण आज देश को इस विपरीत समय में भी कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ रहा है। माननीय प्रधान मंत्री जी के कुशल नेतृत्व के कारण मुझे बताते हुए गर्व हो रहा है कि जब सारा विश्व मंदी से परेशान है, तब भारतीय अर्थव्यवस्था का दुनिया में सबसे तेज़ गति से बढ़ने का अनुमान लगाया गया है। यह आंकड़ा कोई भारतीय जनता पार्टी का नहीं है। आज विकसित देश भी हैरान हैं कि भारत किस

प्रकार से इस वैश्विक चुनौती से अपनी अर्थव्यवस्था को बचाकर तेज़ गति से आगे बढ़ रहा है। 2022-23 में हमारी अर्थव्यवस्था का 9 फीसदी की दर से आगे बढ़ने का अनुमान लगाया गया है। **...(समय की घंटी)**... सर, मुझे 10 मिनट का समय दिया गया था...

उपसभाध्यक्ष (श्री भुबनेश्वर कालिता) : अभी समय कम कर दिया गया है। आपका समय सात मिनट है। अब आप समाप्त कीजिए।

श्रीमती गीता उर्फ चंद्रप्रभा : महोदय, ये आंकड़े भारतीय जनता पार्टी के नहीं हैं, ये अन्तरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के आंकड़े हैं। इस बात को कांग्रेस क्यों समझने को तैयार नहीं होती है, क्योंकि उनके नेताओं द्वारा लगातार एक परिवार शास्त्र पढ़ा जाता है, इसलिए वे अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र अब सब भूल गये हैं। अपनी गलतियों को छिपाने के लिए उनका लगातार सिर्फ एक उद्देश्य रहता है कि किसी न किसी प्रकार से सदन को चलने नहीं देना है। कभी महंगाई तो कभी जी.एस.टी., कभी अग्निवीर, कभी यह, तो कभी वह, ये लगातार पूरे देश को गुमराह करने का काम करते रहते हैं। महोदय, जी.एस.टी. देश का सबसे बड़ा टैक्स सुधार है, जिसका सीधा-सीधा लाभ आम लोगों को पहुंचता है। अगर जी.एस.टी. न होता तो मुझे लगता है कि इतनी महामारी में भी 80 करोड़ जरूरतमंद लोगों को मुफ्त में राशन नहीं पहुंचता, इसलिए मैं प्रधान मंत्री जी का आभार व्यक्त करती हूं। चूंकि समय कम है।

अंत में मैं इतना ही कहूंगी, मैं विपक्षियों से अनुरोध करती हूं कि आपके द्वारा समय-समय पर लगाये जा रहे बेबुनियाद विषयों को छोड़कर एक संवेदनशील विपक्ष की भूमिका निभाते हुए देश की प्रगति में आप सहयोग करें। बहुत-बहुत धन्यवाद।

प्रो. राम गोपाल यादव (उत्तर प्रदेश) **:** श्रीमन्, मुझे उम्मीद थी कि इतने झगड़े-झंझट के बाद जब महँगाई पर चर्चा हुई, तो उसका रिजल्ट कुछ अच्छा निकलेगा, लेकिन सत्ताधारी दल की तरफ से जिन विद्वान साथियों ने तर्कसंगत और अपने आँकड़ों के साथ भाषण दिए, उससे हमें यह लगता है कि इसका कोई अच्छा रिजल्ट नहीं निकलने वाला है, क्योंकि आंकड़ों से आधे पेट, भूखे बैठे हुए व्यक्ति का पेट नहीं भर सकता। इस देश की जनता ने हमेशा देखा कि यहाँ बजट के दौरान, आज नहीं, पहले से भी आँकड़ों के मकड़जाल में ही जनता को फँसाया गया और धरातल पर वास्तविकता बिल्कुल डिफरेंट रही। मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, मैं कुछ ज्यादा कहना भी नहीं चाहूँगा। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि अगर आप वास्तविकता को जानना चाहते हैं, तो कभी सुबह 5 बजे जग कर सड़क पर जाइए, पृथ्वीराज रोड, मोती लाल रोड, वगैरह। वहां सड़क के किनारे जो झाड़ू लगाने वाला है, उससे पूछिए कि महँगाई का दर्द क्या होता है। यहाँ बैठे हुए ज्यादातर लोग इसे नहीं समझ सकते हैं। जब आप उन गरीब लोगों से जाकर पूछेंगे, तब मालूम पड़ेगा कि महँगाई क्या चीज होती है। उन माताओं से पूछिए, जो अपने बच्चों को दूध नहीं दे पा रही हैं। मैं कल एक कार्टून देख रहा था, जिसमें एक बच्ची कह रही है कि निर्मला दीदी, आपने जीएसटी लगा कर मेरी पेंसिल और शार्पनर का भी दाम बढ़ा दिया तथा मेरी मैगी का भी दाम बढ़ा दिया! इसलिए जिन पर बीतती है, वे ही जानते हैं कि महँगाई की स्थिति क्या है। यह सही है कि महँगाई तमाम कारणों से बढ़ती है। इसलिए मैं अपने मित्रों से यह कहना चाहूँगा कि कम से कम

यह तो स्वीकार करना चाहिए कि महँगाई बढ़ रही है। आप उसको जस्टिफाई मत कीजिए कि दुनिया में ऐसा है, इसलिए हिन्दुस्तान में भी ऐसा है। जस्टिफाई करने का कोई औचित्य नहीं है। जब महँगाई बेतहाशा बढ़ रही है, रुक नहीं रही है, तो यह मान कर चलिए कि अर्थव्यवस्था में कहीं न कहीं गलती है। आप उसकी व्यवस्था को सुधार सकते हैं। आप बड़े लोगों पर टैक्स बढ़ा सकते हैं, गरीबों से हटा सकते हैं। इसलिए मैं माननीया वित्त मंत्री जी से यह कहना चाहूँगा कि जब आप जवाब दें, तो आपने जो जीएसटी बढ़ाया है, आप कम से कम उसको विद्ड्रॉ करने की घोषणा यहाँ जरूर करें। लोगों को कुछ तो मिले! आप बड़े लोगों के लिए बढ़ा दीजिए। आप तमाम लोगों को राहत दे रहे हैं, कॉरपोरेट टैक्सेज़ में कमी की जा रही है, जबकि गरीब लोगों पर टैक्स बढ़ रहा है। उनका टैक्स बढ़ाइए और गरीबों का टैक्स कम कीजिए, वरना इस चर्चा का कोई लाभ नहीं है। हम जानते हैं कि आप क्या जवाब देंगी। आपको जो जवाब देना था, वह आपके सदस्यों ने दे दिया और मोदी जी ने पूरा जवाब दे दिया। उन्होंने कुछ छोड़ा ही नहीं, मंत्री जी क्या बोलेंगी! ...**(व्यवधान)**... सुशील मोदी जी। यहाँ तो वही मोदी जी हैं।

मैं आप लोगों को एक और राय देना चाहता हूँ। आप हर काम में प्रधान मंत्री, मोदी जी का नाम मत लिया कीजिए। कल कहीं कोई काम बिगड़ा, तो क्या फिर आप उन्हीं को दोषी ठहराएँगे? अपने नेता को बचाए रखने के लिए कुछ तो गुंजाइश छोड़िए। पता चला कि खराब स्थिति हुई, तो निर्मला जी जिम्मेदार, अच्छी स्थिति है, तो मोदी जी जिम्मेदार। इसलिए आप अपने नेता को सुरक्षित रखने का भी काम किया कीजिए। आप हर बार, हर मामले में नेता का नाम मत घसीटा कीजिए। मुझे कुछ नहीं कहना है, लोग बहुत कुछ बोल चुके हैं। मुझे एक ही प्रार्थना करनी है कि माननीया मंत्री जी जब जवाब दें, तो जो बढ़ा हुआ जीएसटी है, जो गरीब लोगों पर बढ़ा है, आम चीजों पर बढ़ा है, उसको विद्ड्रॉ कर लीजिए आप कुछ बड़े लोगों पर बढ़ा दीजिएगा, धन्यवाद।

उपसभाध्यक्ष (श्री भुबनेश्वर कालिता) : श्री रामजी। आपके पास दो मिनट का समय है।

श्री रामजी (उत्तर प्रदेश) **:** उपसभाध्यक्ष महोदय, चूँकि मेरे पास दो मिनट का समय है, तो मैं अपनी बात को संक्षेप में ही रखना पसंद करूँगा। इस सदन में मैं सुषमा जी की एक बात को क्वोट कर रहा हूँ। अभी कई सारे सांसदगणों ने, कई सारे लोगों ने बात को रखा और सभी लोगों ने यहाँ पर इंटरनेशनल आँकड़े प्रस्तुत कर दिए। देश की जो गरीब जनता है, आदिवासी है, चाहे दलित है, जो गाँव में रहता है, डेली मजदूरी करता है, वह इंटरनेशनल आँकड़ों को नहीं जानता। उसे यह मालूम होता है कि आटे का भाव कितना है, दाल का भाव कितना है, आज तेल कितना महँगा हो गया, पेट्रोल कितना महँगा हो गया। जो जरूरत के सामान हैं, उन्हें देखकर वे लोग बोलते हैं। अभी माननीय सदस्य ने यहां बात रखी कि आज आम आदमी इस दौर में महंगाई के जाल में और सरकार के आंकड़ों के मकड़जाल में फंसा हुआ है। यह हमने नहीं कहा है, ये सत्ता पक्ष के लोग जब विपक्ष में बैठे हुए थे, तब इन लोगों ने इसी बात को कहा था।

महोदय, आज मैं आपके सामने यह एक बिल दिखा रहा हूं, यह केन्द्रीय उपभोक्ता भंडार का बिल है। 841 रुपये का सामान खरीदा गया और इस पर 84 रुपये का टैक्स लगा है। इसमें दाल, साबुन आदि जरूरत का सामान है, वहां टीवी और फ्रिज इत्यादि नहीं मिलते हैं, केन्द्रीय

उपभोक्ता भंडार पर वही सामान मिलता है, जो डेली यूज़ का सामान होता है। यानी कि एक गरीब आदमी अगर 841 रुपये का सामान खरीदेगा, तो वह 84 रुपये का टैक्स देने का काम करेगा।

महोदय, मैं छोटी सी बात कहना चाहता हूं कि गरीबों की थाली से रोटी छीनकर अमीरों को मलाई खिलाना बंद कर दीजिए, इससे देश का भला नहीं हो सकता। अगर आप देश को कुछ दे सकते हैं, तो आप एजुकेशन फ्री कर दीजिए, फ्री एजुकेशन फॉर ऑल। फिर आपको फ्री में कुछ भी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कल लोक सभा में एक सांसद ने बोला कि फ्री फंड का देते हैं, यह सरकार की उपलब्धि नहीं होती है। फ्री फंड का देना, फ्रीबीज़ देना कोई सरकार की उपलब्धि नहीं है। आपकी उपलब्धि तब होती है, जब आप अवाम को इतना ताकतवर बना दो कि वह महंगी से महंगी चीजें खरीद सके। आप एजुकेशन दीजिए, उनके लिए रोजगारपरक अवसर उत्पन्न कर दीजिए, वे ऑटोमेटिकली उन्हें खरीदना शुरू कर देंगे। इसलिए मेरा निवेदन है कि इन सब बातों पर ध्यान दिया जाए।...सर, अभी मुझे बोलते हुए दो मिनट ही हुए हैं।

उपसभाध्यक्ष (श्री भुबनेश्वर कालिता): आपका टाइम दो मिनट ही है।

श्री रामजी : ठीक है, सर मैं कन्क्लूड कर रहा हूं। आपके माध्यम से सरकार से मेरा निवेदन है कि आटा, दाल, चावल आदि जो रोजमर्रा की जरूरत की चीजें होती हैं, गरीब आदमी, आम आदमी जिस तरह से मजदूरी करके अपना घर चलाता है, उसे ध्यान में रखते हुए इसे वापस लिया जाए और दाल, आटा, गेहूं इत्यादि सामानों पर जो जीएसटी लगाया गया है, इसे खत्म कर दिया जाए, धन्यवाद।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): Now, the hon. Minister.

THE MINISTER OF FINANCE; AND THE MINISTER OF CORPORATE AFFAIRS (SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN): Sir, I thank all the Members who have gone into great detail in speaking about the issue. In fact, I would like to start by saying that I am indeed happy to be able to stand up here and give the reply to this debate and actually I would have but for Covid which hit me; I would have been here on the first day when the debate should have started. From my Party and from the Government, I would like to assure every Member in this House that in debates, particularly on such topics, we have always been keen to participate and respond because we strongly believe in parliamentary democracy. I have personally never been against giving replies. Sometimes, I do it a bit more than what is expected of me because I go to the extent of trying to answer every point raised which sometimes can mean a longer session of sitting and hearing more of the Minister's reply. Let me assure this House that debates are something which we respect and want to participate. I am glad that today we had this debate and I am here to respond to what the Members have spoken about.

Many of the Members seemed to have heard what I have spoken in the Lok Sabha yesterday. So, on many of the points, although they have been raised here, I would not elaborate too much. Of course, in honour of the Member who has raised it, I will respond somewhat but they have heard me on many of those issues in great detail having spoken in the Lok Sabha. So, I will try to keep it crisp on some of these points.

Sir, I started there and I really like to start here as well by saying that the Indian economy compared to the situation prevailing in many of our peer groups and compared to the situation in many of the developed economies, is definitely much better. But that does not mean that we are running away. Some of the Members have said that because of imported inflation, imported supply-chain related problems, global commodity prices, etc., we are being impacted. These are the realities and we are here to answer and discuss on them. Nobody is saying or nobody is in a denial about price rise. I mean even Prof. Ram Gopal Yadav spoke on this, he is not here now. *...(Interruptions)...* Thank you for correcting me. He said: "No; धरातल पर जाकर देखिए, नम्बर्स नहीं।" हम नम्बर्स भी देखेंगे और धरातल पर क्या हो रहा है, वह भी देखेंगे। हम भाग नहीं रहे हैं। यह भी सच्चाई है कि नम्बर्स के मुताबिक भी हमारे इन्फ्लेशन रेट का एक बैन्ड रहता है। 4 is the median point, -2 or +2 is what is normally accommodated and we are at 7 with some effort or it can be slightly more than 7 but we have made sure that the Reserve Bank of India and the Government, put together, are taking enough steps to make sure that it is kept in the band of 7 or ideally below 6. So, nobody is denying. Therefore, when we say, "Look at the world where some countries are experiencing inflation which they have not seen in 40 years, 35 years, 27 years", it does not mean that there is no inflation in this country. So, you know, it becomes very, very haranguing. That's not to say about you. If the debate constantly is only attributing things which we have not even said, so let's please, both on data and on धरातल. Thank you very much Prof. Ram Gopal Yadav. Constant interaction with the people, who are affected, is giving us inputs and based on which we are having a targeted approach from the pandemic until today when the recovery is going on. Through the targeted approach, we are reaching sections which so desperately need that help. Of course, yes, we can do a lot more. Nobody is denying that but that does not mean we are saying, "No, we won't do anything at all." Also, this very impressive narrative can go on, "Oh, you have collected so much from the fuel excise duty and the cesses and you are sitting with it and the poor person is not being given any help." I am sorry. I will list out and I will definitely list out what for the poor person even today, we are doing and we love to do more. That is not to say, "Oh you gave 50 people, you do not want to give the 51st." No, we will give but to think and

attribute to us that we are not doing anything for the poor, I am sorry. And the approach that, "You know, you have never done anything for the poor, you are always for Adanis and Ambanis", I am sorry I am compelled to take the names here, is absolutely politicizing a debate which is so necessary for the country because all of us together, some of us in our States, some of us as Members of Parliament in our respective constituencies, are working to make sure that the poor's voice is heard. We are trying to reach out. Some of the schemes which do not go down to the ground, we are making sure that is given to them. Each one of us is contributing in this recovery process. This recovery process is not purely on the economic recovery, also because of the pandemic. I am glad the Health Minister is also here; think about the efforts taken for vaccination which is so critical for the economy as well. Every Member has been keen to know about it and we have been constantly giving data to prove that everybody is in it so that the economic recovery can happen. So, I appeal to the august House that we speak both on facts and on the धरातल. It is not as if we are only throwing data at the people. In fact, most of the times we are accused of giving data which is not right. So, I am definitely emphasising that comparing with many of our peer group nations, emerging economies or even looking at some of the advanced economies, India's position, let's be somewhat comforted by the fact that our macro-economic fundamentals are strong. It is all very well for us to be told: "No, you should do some more here, some more there" but if you are denying that the macro-economic fundamentals are strong, I am sorry, you are not going to be taken seriously. Not by me. I will take you seriously. You are a Member of Parliament, I will honour you. But let us talk on what is actual and not what is generated, I do not know, by who. So with that, I just want to highlight one of the points which is important because we have a temptation to compare and that is not wrong. Please do compare with our neighbours, with economies which we thought are better than us. Probably, they were, and you wanted to tell us that they are better and why are we not. All that is fine, but please don't forget that today, the very same economies which were quoted to us saying that they are doing much better, India is not, because their policies are lot more friendly for industry. I am sorry. I am not revelling in countries which are suffering today. I honestly do want everyone of our neighbours, some of whose name I will take here to be better off, to be able to perform well. But today's situation, the reality is that some of these countries which have been quoted to us earlier, for one index or the other index, they are better than us, you are not, look at the reality please, hon. Members. Bangladesh, about which we are periodically quoted and we have great friendly relations with Bangladesh, and I am happy for it. And there was a time when we were quoted repeatedly saying,

"Bangladesh is doing well, you are not." But even on a reply to a Parliament question on 1st August, yesterday, I have given the data of what is the comparison which has got to be there. I just want to read it out. The per capita GDP at PPP in 2013 of Bangladesh, was 3,143 international dollars as I say it, but it is US Dollar. But in the same 2013, India's per capita GDP at PPP was 5,057; 3,143 *versus* 5,057. And in 2021, when we are repeatedly reminded saying, "You know Bangladesh is doing..." Even if they do well, very well. But I want to give you the number. In 2021, Bangladesh's per capita GDP at PPP is 6,613, whereas, ours is 7,334. So please do quote, but quote with facts. And again, I am underlining this point. I am not quoting miseries here, but because repeatedly we are being told, "Oh! You are next Sri Lanka. You are not anywhere near Bangladesh." But please understand the whole story everywhere. Bangladesh, today, is seeking from IMF 4.5 billion because they have balance of payment problems. And when I say when our macro economic fundamentals are strong, please, let us recognise that our macro economic fundamentals are strong. Sri Lanka, of course, is asking for 3.5 billions to the IMF. Pakistan in total, is asking in different stages for 7 billions from the IMF. There are times when we have also been told, "Oh, in India the petrol price per litre is this. Look at our neighbour Pakistan, look at our neighbour, Sri Lanka. That is the rate there. They are far lower than you." Let us consider it in a holistic way rather than piecemeal saying, "You are this, we are that, they are they." No! Today's economic distress throughout the world being what it is, let us look at it holistically rather than just throwing one *astra* here, so that, "Yes, good, I have done my job". No. Please, this is a very serious business and all of us are honestly, Members of this House, who will have to look at very seriously what kind of things can be done so further we are able to improve the lot of our people. Now I go to specific points raised by hon. Members because I would like to answer them. I am not going to get into greater details of other things which govern the macro economic situation. The first speaker, Elamaram Kareem*ji*, had raised a few things, which, I think, were not based on facts.

I would want to correct them. He spoke about bank cheques. I would like to say there is no GST on withdrawal of cash from bank. There is no GST. Please! And, today on very many things, I will say there is no 'this' and there is no 'that' on the GST, Sir, because the more I listen to issues related to GST, I have a concern that probably, the right information is not reaching and, as a result, there is quite a lot of misconception. I would today attempt to clear some of these misconceptions. First of all, there is no GST on the withdrawal, specifically on the cheque books. GST has been imposed on the bank cheque books when banks buy it from the printers of the cheque books, because banks will have to buy it in bulk. And, from them, when they

obtain it, because banks don't print their cheque books, they buy it from the printers and the printers, after all for the paper, after all for the machine, after all for many other things that they have and the services that they are paying GST, for those inputs with which they manufacture the cheque books and supply to the banks; so for them, there is a GST tax because they already are paying input tax for many of these items. So, the stream till the consumer, because it is a consumption based tax, will have to keep settling tax dues at every level. That is what is before you, hon. Member Kareem. So, I want you to kindly take into cognizance that as regards consumers or the bank clients who take the money, withdraw the money, there is no charge on him. It is a bank which purchases from the printer for whom there is a GST. Otherwise, the printer will end up at a disadvantage giving it at cost at which he gives it to the banks while the input credits will get accumulated. And, I elaborate on the fact that when you go and withdraw cash, five free transactions from your own banks ATM and five from an ATM of a different bank, you can draw without any charge. They are free transactions. So, ten in total. And, in three banks, transactions are limited to three and not five because in six metro cities there are difficulties and instead of five, they give three. However, for small, no frills, basic saving bank deposit accounts, which are what the common, small or medium class families use, they are still permitted five free transactions even in metro cities. So, five plus five, ten transactions - in a month is totally free when you withdraw from your ATM. So, let us please not be laid by misinformation. And, then banks may provide more if they chose to because RBI has not asked them to contain it at that if they want to give more. So, that is about bank and withdrawal. Again an issue which I may periodically now and a bit later also elaborate about the pre-packaged item. I hesitate to say something here. GST Council has Members, Ministers from every State. They are not alone when they are inside the GST Council. They sit with their officers as well. So, it is not as if it is possible for anyone to say something about some other State outside and get away with it because they are with their officers. It is not the Minister himself, the officers also know it. As regards the latest 47th Meeting, which was held in Chandigarh, it is a matter of record that all States agreed to the proposal. I put it on record. And, if there have been private conversations with some Ministers, I recognize the private conversation. Madam, Rajani *Tai,* I would like to particularly tell you. Private conversation can be anything. The minutes, the oral records all stand testimony that there was not one person who spoke against. This is my word, you may not trust me, but I have the responsibility as the Chairperson of the GST Council to put the facts on record in this august House. Not one spoke against. And, I repeat, not one spoke against. So, there was not even a single disagreement for the decisions which were

taken. I am glad that Sushil Modiji spoke about it elaborately to the extent that some of the Members said, "Oh! The Minister's reply is being given by him." He is a very old hand in the GST. He has been there before the GST Council was formed, in the Empowerment Committee, Empowered Group of Ministers, which prior to GST drew the entire framework. I don't derive any pleasure by saying something which is not true. You can always pull me up later. My credibility will be gone to the bins. Why would I want to do it? If Ministers who had agreed, and who later don't want to stand up and say, "Look, I agree", I cannot hold them responsible; Bhaiya, you were there, why don't you want to say, I will not ask them. In the Council what happened is what is on record and about that if there are speculations, it is my duty to answer it. That is what I am doing. I repeat that 47th Council Meeting in Chandigarh, where after a three layer of process of Fitment Committee, and I go to the details to tell you who were the members in the Fitment Committee, and post that a Group of Ministers. I will tell you who were the members of the Group of Ministers. It is not just my BJP patriots, I mean compatriots. Ministers from all different States were in this Group, some others were in this Group and post that, it comes to the GST Council. Why has this correction become necessary? Then and now, the poor's consumption of any of these are not being taxed even now. Even now they are exempted. When in 2018, the branded people, some of them who were not registered as brand but unregistered were also given the exemption. There was a thorough rampant misuse because those who were given exemption, not so registered branded people, they are all getting the exemption but those who were registered and high value brands, they were given a choice saying that if you disclaim your registration of the patent or your copyright or your brand, you also become one of those brands but not registered, blatant misuse happened. This from 2019 has been worrying the GST Council, in every meeting this was discussed and there were amounts also looked at as to what this misuse is leading to. In its wisdom, therefore, the Council said, we will have to work out some way in which the poor continue to get theirs without GST but the brand and unbranded which is happening will have to be dealt with. Therefore, what we have done now is this continues for the poor. They are not being touched. The exemption continues on sale of loose rice, puffed rice, *dahi, chaval, lassi*, or whatever; it continues. What's now the exemption has been withdrawn is on the pre-packed. Even now, when a trader who is dealing with small customers has to sell in loose, he has to buy his products from somewhere. So, when he buys in bulk, gets it packed up there and then brings it to his shop, he is not being taxed even now. He can get his more than 25 kg, 30 kg, come here to his shop and sell to the poor without GST. So, the Council, and I take extreme--I think it is my duty-- pride to say that the

Council has applied its mind at various levels, at the Fitment Committee level, Group of Ministers level and then at the GST Council level.

7.00 P.M.

The continuation of the exemption for the sake of the poor continues and the misuse which was happening from the branded ones, particularly those which are registered brands, had to be corrected. That is what has happened. Shri Elamaram Kareem was also worried that we are dealing with diamonds so kindly. He said, 'you are taxing them very less. Food products are being taxed at five.' Kareemji, at the time when GST was brought in, elaborate discussions took place about diamonds because in this country 96 per cent of all imported diamonds which were coming was cut, polished and some jewellery with value addition work gets exported. Ninety-six per cent of all rough diamonds which are brought into this country are exported. So, obviously, you don't export your taxes. Any export item does not bear the domestic tax, and, therefore, earlier where it was three per cent, then there were quite a lot of demands from those and it is a labour-intensive industry. Therefore, a lot of input tax credits were getting accumulated and because they were selling it with no tax, or some percentage of tax, it wasn't benefitting. Therefore, in order that the Input Tax Credit (ITC) claims can be sorted out, studies were done on it and, post that, the Council took their decision to keep the tax where it is. So, that is not a favour done to diamonds. It is more the industry and the workers who are all there and because 96 per cent gets exported, that rate has been fixed. Hon. Member, Kareemji said, if I may be able to recall his words, "Since Independence, there has never been tax imports on cereals and food products." Please correct me if I am wrong. I am sorry, no; I need to put the facts before you. Prior to GST, I have the data here with me, State-wise, for the VAT rates on pulses, dal, wheat, rice, flour, atta, maida, suji, rava, besan, paneer, curd, lassi, buttermilk. Every State, in some or the other item has imposed a VAT. So, since Independence, nobody taxed on cereals. No, Sir. Since you are from Kerala, I will quote that example first and I will read out the others later. In Kerala, pulses before GST was taxed at one per cent. In Kerala, atta, maida were at five per cent, Suji/rava at 5 per cent, besan at 5 per cent. So, it is fine. We may probably not have the necessary information in our hand, but every State had one or the other tax on all these items which today have become the GST-related curse! No, Sir. In fact, there are some States, Jharkhand for instance, which taxed five per cent on dal, 5.5 per cent on wheat, 5.5 on rice, 5.5 per cent on maida, 5.5. per cent on suji/rava, 5.5. per cent on besan, 5.5 per cent on paneer. Maharashtra

had it on curd (whether or not sweetened) at six per cent. Paneer was taxed at 6 per cent as well in Maharashtra. So, it is very well for us to very quickly say, 'No, no. This has never happened.' West Bengal taxed paneer at 5 per cent pre-GST.

SHRI DEREK O'BRIEN: Sir, I am on a point of order.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): There is no point. ...*(Interruptions)*... Mr. Derek, it is discussion. ...*(Interruptions)*... No, please, there is no point. ...*(Interruptions)*... You listen to her first. Let her make a statement. ...*(Interruptions)*...

SHRI DEREK O'BRIEN: Bur, Sir, ...*(Interruptions)*...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): No. Not in between. You are not supposed to disturb the Minister while she is replying. ...*(Interruptions)*...

SHRI DEREK O'BRIEN: I am not disturbing, Sir. ...*(Interruptions)*... Why should I disturb? ...*(Interruptions)*... I have only asked for a point of order. ...*(Interruptions)*... I am not disturbing. ...*(Interruptions)*...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): Don't disturb. ...*(Interruptions)*... I am not allowing. ...*(Interruptions)*... Please be seated. ...*(Interruptions)*...

SHRI DEREK O'BRIEN: Sir, I am not disturbing. ...*(Interruptions)*... I will sit down. ...*(Interruptions)*... *

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): Once the reply of the Minister is over, you can ask. ...*(Interruptions)*...

SHRI DEREK O'BRIEN: Sir, I have asked for a point of order, because she mentioned West Bengal and paneer. I have asked for a point of order. * we walkout on this. * No, Sir. ...*(Interruptions)*...

(At this stage, some hon. Members left the Chamber.)

---

* Expunged as ordered by the Chair.

THE LEADER OF THE HOUSE (SHRI PIYUSH GOYAL): Sir, it is extremely unfortunate and this has exposed the Trinamool Congress and myesteemed colleague, the leader of the Trinamool Congress, Mr. Derek O'brien, today in this House. They never wanted the debate in the first place. We have been repeatedly saying that they are running away from the debate. We were missing the hon. Finance Minister due to COVID. She has just recovered from COVID. After that, she sat for five hours and listened to every hon. Member, made copious notes and addressing each Member's concerns very elaborately. Despite such an exhaustive and very, very articulate response to everybody's issues, if the hon. Member wants to find an excuse to walkout, I think, it is very, very sad. It only shows that they are getting exposed for their failure to take effective measures.

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: So, Sir, I would not elaborate on each State. But, the fact of the matter is that some States or, in fact, all the States, on some item or the other, pre-GST, had VAT on every one of these items which we, today, feel outraged how did the GST Council do. The GST Council has not done anything. No new tax has been levied. But, those who had exemption and misusing them have now been told, 'No more exemption for you if you are branded.' So, pre-packed for the poor, which is brought in loose, is still under exemption. With that, I will not elaborate further.

There were concerns about hospital beds! I would like to highlight it again. This is as a result of misunderstanding. I would like to clear this misunderstanding. The GST Council recommended GST on hospital room rent. It is not on bed. It is not on ICU. ICU is not being charged at all. It does not impact emergency services. It does not impact ICU. But, if you are taking a room in a hospital, which is more than Rs. 5,000 per day, it is only for that class of people, 5 per cent GST on hospital room rent alone is being levied. But, if you are taking a room which costs Rs. 5,000 or less, there is no tax. So, again, there is misunderstanding which I would like to clear or wanted to say, 'No. Sorry. That is also not right.'

Again, Sir, with a lot of cynicism, the Council is accused of having levied charges on crematoria! I am charging if one is burreid; no. Please, please put in a minute more to read what actually the Council has said. I am extremely proud, Sir, the way in which Council functions. The Ministers apply a lot of their mind. The Fitment Committee does its business. At every layer, the Legal Committee looks into the legality of everything and post that, the issues come to the Council. And, even there, they think whether it is the right time; should we do it later; what is the loss if

we do it tomorrow; what is the loss if we had not done it at all. Everything is discussed. To suddenly make a picture of the GST Council, as though it is sitting mindlessly and just goes about wanting to earn more; no, please. They are also people coming from the ground. After all, they belong to all our parties. They know what the ground is. They come back to say what they want. And, there is no maniacal wanting to earn more revenue. It is more reasonably addressing issues but addressing nevertheless. So, as regards crematorium, hon. Member Kareem, there is no GST on crematorium, funeral, burial or mortuary services. इसके ऊपर कोई टैक्स नहीं है, क्योंकि वह सब एग्जेम्प्ट है। अगर कोई एक नया क्रेमाटोरियम बनाना चाहता है, उसके लिए इलेक्ट्रिकल इनसिनरेटर ला रहा है या कुछ और बना रहा है, तो इन सब चीज़ों को इनस्टॉल करने के लिए और इन चीज़ों को लाने के लिए, वह टैक्स पे करके ले आता है। He buys these huge incinerators, and also builds it with materials for which he pays tax. And, when he comes here to build it, he has already paid the tax. How will he retrieve it unless he has got it? So, the construction of crematorium is what is being taxed and it is not as though the services that you go to bury and there you are being taxed. No. Let us please understand how the economics of taxation works. Yes, it is important to be conscious that we don't hurt a poor consumer. But it does not mean that we break the taxation chain and disrupt the whole GST framework. Even now, we say, 'No, no; GST is a failure.' Not at all. I actually want to highlight this and I shall do it. Today, I heard a lot of this *grahinis*, *grihastha*. Oh! GST Council is also conscious of *grahinis*, GST Council is also conscious of households. I will read out the list as to what the taxation on *grahinis* was before the GST was introduced. Mr. Derek O'Brien is not here. He listed out six things and said, 'Minister is not here' but has come. I wanted to come and reply. I am ready to reply; he is not here. But I will read it out. So, hon. Member Kareem, I want you to be sure that the crematorium matter be settled.

I just want to be sure that the point on the GST decision-making process is understood. I want to tell hon. Members as to who were there in the Fitment Committee. The Fitment Committee consists of top Commissioner level officers from Rajasthan, West Bengal -- sorry, I have misplaced the papers, but I will get the details. So, that is at the Fitment Committee level. After that comes the Group of Ministers. Who are the Ministers in this? They are West Bengal, Rajasthan, Kerala, Uttar Pradesh, Goa and Bihar. They have considered the decision given by the Fitment Committee. The Group of Ministers is looking at rationalisation of rates, looking at the correction of inverted duty structure in the taxation where you pay higher tax when you are buying the raw material but pay a lower tax when you are selling the product. Group of Ministers is there which is headed by the Chief Minister

of Karnataka. Then it was agreed by Council. And, in that too, who are the Ministers again? They are from Punjab, Chhattisgarh, Rajasthan, Tamil Nadu, West Bengal, Andhra Pradesh, Telangana and Kerala and other states. All members of GoM and Council agreed, Sir, and agreed without any difference. So, I want this debate laid as a matter of fact. Sir, there were concerns about poshan, nutrition and also about reduction in malnutrition and issues like that. Between 2015-16 and 2019-21, 'child-stunting' has been reduced from 38.4 to 35.5 in percentages; 'child-wasting' from 21 to 19.3 per cent; 'underweight children' from 35.8 to 32.1; 'malnutrition in women', that is, between 18 and 49 years, from 22.9 to 18.7.

Sir, I am happy to say -- the Health Minister is here, the former Health Minister is here -- that institutional births in rural areas, which is very important for the maternal health, have increased. It was 75.1 in 2015-16; 75.1 percentage. It is today at 86.7 percentage. Also regarding the cost of medicines, the people not being able to purchase medicines, I want to say that I am very glad -- I very closely follow the Health Minister, Dr. Mandalviya's *Jan Aushadhi Kendras*; we every now and then talk about it -- that the price of *Jan Aushadhi* medicines is cheaper, at least, by 50 per cent, and, in some cases, by 80 per cent to 90 per cent of the marked market price of branded medicine, the same branded medicine and what is available as a generic medicine here in *Jan Aushadhi Kendras* -- 90 per cent, 80 per cent and such differences. So, I want that to be appreciated that '*Jan Aushadhi Kendra*', as a mission, has succeeded in reaching medicines at affordable prices to the poor and the needy, and that is a big success. I credit the two, one former and current Health Ministers who are here. In the last eight years, starting from the annual turnover of Rs. 8 crores in a year, 2014-15, the highest monthly sales turnover of Rs. 100 crores has been achieved in this; and therefore, this is something which I want you to take into cognizance. I want Kerala to have a lot more *Jan Aushadhi Kendras* so that your people in Kerala can benefit by affordable medicines. More than 3.28 crore persons have been treated free of cost because there was this concern. 'The cash has to be paid; they can't afford it.' *Ayushman Bharat* has given this facility of being treated free-of-cost. I am giving you the data as on 7th April, 2022. About 3.28 crore persons have benefited from it, and 18 crore Ayushman cards have been issued. So, the care of the poor is being fully kept in mind.

Hon. Member, Shri Shaktisinh Gohil, is here, and very many other Members spoke about how *Ujjwala* is really not making a difference. 'You spread it but then we all gave up but then today, there is a problem.' I just want to highlight that as of May 21st when we announced the excise duty cut, we agreed and we announced that Rs. 200 per gas cylinder, up to 12 cylinders, will be given to over 9 crore beneficiaries of

Pradhan Mantri Ujjwala Yojana. We have not forgotten them. But the cost of the gas, LPG, is not in our hands. If we are importing it and if the prices are going up, obviously, we will have to make sure that the poor get it at a concessional rate. We are giving Rs. 200 per cylinder, and not for one-two, 12 cylinders are being given that subsidy. In 2014, there were only 16.8 crore LPG connections. Today, in 2022, there are 30.5 crore people benefiting from it. Tomato, onion and potato scheme has been an easy target of a lot of people saying, "Nothing has made a difference in it; you announced it; Prime Minister Modi said it." But I would like to highlight what it is about. Actually, over a span of less than five years under UPA-II, from May, 2009 to November, 2013, the average price of various food commodities was in triple digit, not in double digit. Some of them went on that much. I am not exaggerating. The increase in the prices of potato, onion and tomato over this period, from 2009 to 2013, was shockingly at 164 per cent for potato, 323 per cent for onion and 160 per cent for tomato. That was the kind of increase that happened during UPA-II. Today with TOP Scheme, we are able to get more of these perishable goods to the market and give them capacities to store. As a result of which, the prices have been held reasonably. In fact, in November 2013, the price of onion had touched Rs.100 per kg. in certain centres. Sir, you are from Assam. You know that in places like Aizwal, it was already Rs.100 per kg. or more at that time and tomato was costing Rs.80 per kg. I am glad that Rajani *Tai* remembered my exchange about onions in Lok Sabha. Whether I eat or not, *Tai*, we worked to make sure that it is affordably available for everybody. So, it doesn't matter whether I am an onion-eater or not. All of us rejoiced at a Minister being bullied saying, 'Oh! She doesn't eat onion, so she doesn't care for the poor who need to eat it.' Not just me, Prime Minister also has a concern and that is why the TOP Scheme succeeded. I would like to quote the reduction in the price between the last month and this month whereas what it was between 2009 and 2013. On May 1, 2009, potato was Rs.9 per kg., whereas on November 22, 2013, it was Rs.26 per kg., whereas what we have on July 29 is Rs.26 per kg. only. We have contained the prices. Onion was Rs.52.98 per kg. in 2013, whereas it is Rs.25.45 per kg. on 29th July today. Tomato was Rs.46 per kg. in November 2013, today it is at Rs.34 per kg. So, one of the things which I would like to take into cognizance is that there were detailed questions about groundnut oil, mustard oil and *vanaspati*. I have the data; I don't want to read it here, but proving that we are holding the prices carefully. One of the hon. Members did ask what is happening to the area under cultivation. I think it was one Member from Telangana. He said that the area under cultivation of rice is going down and the area under cultivation of wheat is going down. He further said that we halted the export. There is a Group of Ministers headed by the hon. Home

Minister which periodically reviews it. The Commerce and Industry Minister, Consumer Affairs Minister and the Leader of the House here are members of that Group. We periodically review the availability of cereals, pulses, *dalhan, tilhan* and also the crop sowing area acreage under cultivation and take calls accordingly. So, it is not left high and dry. The Government is looking at it because these are essential and we need to do something about it for the vulnerable sections of the society. I would like to quote Pandit Deendayal Upadhyaya from whom we derive a lot of inspiration. He said, "It is our thinking and principle that these uneducated and poor people are our Gods. We have to worship them. It is our social and human *dharma*." That is what he said and the *antyodaya,* which we practise, is derived from that. Now, let me list out some of the specific actions. ...*(Interruptions)*...

SHRI BINOY VISWAM: You just said that the poor are the gods for you. ...*(Interruptions)*... What are you doing for the farmers? ...*(Interruptions)*...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): Binoy Viswamji, not now. ...*(Interruptions)*...

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: I will give you the data of what we are doing for the farmers. About PM Ujjwala, I have already mentioned. In 2014, it was 16.8 crores. Today, it is 30.5 crores. Since we heard the hon. Member, Shri Binoy Viswam, talking about farmers, in 2014, there was no Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi Yojana, but in 2022, we have already deposited, in the accounts of 12.5 crore-plus number of farmers, an amount of Rs.6,000 each. Sir, 12.5 crore-plus farmers have received Rs.6,000 each in their accounts per year. So, we are looking at the farmers and taking care of them.

Regarding Jal Jeevan Mission, in 2019, there were only 3.2 crore households getting piped water. Now, 9.6 crore households get piped water. So, we are taking care of the poor actually and not just throwing some money and saying, "आह, पुअर के लिए पैसा दे दिया!" नहीं, सचमुच उनके घर में पानी नल के द्वारा जा रहा है।

For the street vendors, there is the PM SVANidhi Yojana. In 2014, there was no scheme. Till 2022, twenty-nine lakh plus get affordable loans, under the PM SVANidhi Yojana, so that they can do their own work. They don't have to give security. Without any security, they get these loans. About Ayushman Bharat, I have already stated. Under the Ayushman Bharat Jan Aarogya Yojana, 3.28 crore people get free treatment. So, let us accept these facts. Mr. Sanjay Singh is not here. He was talking about पुअर के लिए, गरीब-गरीब। We are attending to *gareeb* in reality.

What they need in their house is reaching them. Shri Tiruchi Siva also mentioned some of these things like गरीब के लिए क्या है।

There is one point on which hon. Member, Shrimati Ranjeet Ranjan, also spoke stating that we have given Ujjwala cylinders, but what is the use as the prices are going up. I have already told you that we have given Rs.200 for up to 12 cylinders in a year for each cylinder, but there is an important data that I would like to highlight here. LPG coverage is defined as ratio of the active consumers to the total households which are getting covered. That has increased from 61.9 per cent in 2016 to 102.2 per cent in November of 2021. That is not possible unless people are having their refills made periodically. So, it is not true that people are not coming for refills. Yes, the prices have gone up. It is not in our hands, but still we are giving Rs.200 per cylinder for people. That may not be sufficient. You can ask me to give them the cylinder totally free. They may deserve it, but I will also have to consider how many people I can afford to give and so on. ...*(Interruptions)*...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): You have covered already. ...*(Interruptions)*...

DR. V. SIVADASAN: The subsidy amount has been reduced. ...*(Interruptions)*... Now, only Rs.242 crore is the subsidy amount. ...*(Interruptions)*...

श्रीमती रंजीत रंजन : उपसभाध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहती हूँ कि सूचना के अधिकार के तहत नीमच के चन्द्रशेखर गौड़ ने जो आँकड़े जुटाए हैं, उनके अनुसार 2021-22 में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, 2.8 करोड़ ग्राहकों ने एक भी रीफिल नहीं कराया, 62.1 लाख ग्राहकों ने सिर्फ एक बार रीफिल कराया; हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन, 49.44 लाख लोगों ने साल में एक भी गैस सिलिंडर रीफिल नहीं कराया, 33.58 लाख ने सिर्फ एक बार कराया। ...**(व्यवधान)**... आप बोलिए। भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन, 2021-22, 30.10 लाख ग्राहकों ने एक बार रीफिल कराया, 24.16 लाख ग्राहकों ने एक भी नहीं कराया। ...**(व्यवधान)**... सर, क्या बात है? ...**(व्यवधान)**...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): Okay, you have made your point. ...*(Interruptions)*...

श्रीमती रंजीत रंजन : 3.59 करोड़ ने साल भर में मात्र एक सिलिंडर भरवाया और 1.20 करोड़ ने सिर्फ एक भरवाया।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): You had the opportunity to ask questions.

श्रीमती रंजीत रंजन : इसके अनुसार 'उज्ज्वला योजना' के लाभार्थियों की संख्या में शामिल पिछले एक साल में 4.49 करोड़ ग्राहकों ने एक बार भी सिलिंडर नहीं भरवाया और 2.4 करोड़ ने सिर्फ एक बार भरवाया ...**(व्यवधान)**...

उपसभाध्यक्ष (श्री भुबनेश्वर कालिता) : आप बैठ जाइये। ऑनरेबल मिनिस्टर।

श्रीमती निर्मला सीतारमण : रंजीत रंजन जी, मैं जरूर आंसर दूंगी। ऑनरेबल मेम्बर, वाइस चेयरमैन साहब, रंजीत रंजन जी को मैं आंसर देना चाहती हूं। सरकार बजट के द्वारा प्रोविज़न करके घोषणा करती है और ये सब रेट्स पब्लिक में अवेलेबल हैं ऑनरेबल मेम्बर्स ऑफ पार्लियामेंट अपने क्षेत्रों में जाकर गरीबों के लिए यह सब्सिडी दिलवायें, यह उनका अपना कर्तव्य है, जो सरकार के द्वारा ...**(व्यवधान)**... I am sorry. ...*(Interruptions)*... I am sorry. ...*(Interruptions)*... I am sorry, you cannot ask me to give an answer you want. I will give an answer having heard you.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): Ranjeet Ranjan ji, please. ...*(Interruptions)*... It cannot be unending or continuous. ...*(Interruptions)*... प्लीज़, आप बैठ जाएं। ...**(व्यवधान)**.. प्लीज़, आप बैठ जाएं। ...**(व्यवधान)**.. Please sit down. ...*(Interruptions)*... Nothing shall go on record, if the Member speaks without my permission. ...*(Interruptions)*... I have not given you permission.

श्रीमती रंजीत रंजन: *

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: I am not yielding now, Sir. ...*(Interruptions)*...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): Nothing will go on record. ...*(Interruptions)*...

श्रीमती रंजीत रंजन: *

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: I am not yielding now, Sir. ...*(Interruptions)*... I am not yielding now, Sir. ...*(Interruptions)*... I sat down. ...*(Interruptions)*... रंजीत रंजन जी, आप जरा सुन लीजिए प्लीज़, मैं हाथ जोड़कर बोल रही हूं। ...**(व्यवधान)**... आप सुन लीजिए। ...**(व्यवधान)**...

---

* Not recorded

उपसभाध्यक्ष (श्री भुबनेश्वर कालिता) : आप सुन लीजिए, आप बैठिये। ...**(व्यवधान)**...

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: I am not claiming it. ...*(Interruptions)*...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): It cannot be a verbal duel. Please have patience. ...*(Interruptions)*... आपने जो प्रश्न पूछना था, वह पूछ लिया, मिनिस्टर ने यील्ड किया, आप मिनिस्टर पर दबाव डाल रही हैं, आप बैठिये। ...**(व्यवधान)**... आप बैठिये। Hon. Minister, please speak.

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: Sir, I am addressing you. I sat down. I heard every Member; sometimes in this place and sometimes from my room, and, even now, I sat down, yielding, to hear the hon. Member. I heard the hon. Member, after which, I am willing to give an answer. It may not be the answer she would like to have but I am giving the answer. If it is not the answer that she wants, it does not mean that one will say, this is not the way to give answer. That is the answer I can give whether you like it or not. With your permission, Sir, I sat down, I heard. But, what is this? ...*(Interruptions)*... Constantly, the Minister will have to be listening. I am listening. But when I stood to give an answer, there are interruptions and running commentary. There is dictation, 'not that way'. I am sorry, Sir. I am willing to hear. I am willing to sit and hear interruptions. I yielded and after that, certainly, I will give a reply. And, Sir, I think, you would give me, it's the duty that I am performing, a chance.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): Definitely. Please speak.

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: Sir, there has also been a lot of questions about the point that the Centre is collecting a lot of cess. ...*(Interruptions)*...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): No interruptions, please.

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: Before that, let me refer to what hon. Member, Derek O'Brien said. He is not here now. He raised something very interesting and spoke about the worries of the families when they think of the morning and the kind of things that they have to do. They have to buy toothpaste at this rate, and, when they go out, they have to get a cylinder and come. गृहिणी, गृहस्थ को ध्यान में रखते हुए, I would like to draw his attention to pre-GST rates.

श्रीमती रजनी अशोकराव पाटिल : आज गृहिणी त्रस्त है।

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: Of course, Madam, and, I fully know this. I am purposely using this word. ...*(Interruptions)*... I am also a *'grehni'*. I used the word *'grehni'* and I am using the word *'grehni'* because I have been told repeatedly ' गृहिणी का ध्यान रखो, मैं गृहिणी हूं। ...**(व्यवधान)**... So, I hope, you will not have an objection. ...*(Interruptions)*...

उपसभाध्यक्ष (श्री भुबनेश्वर कालिता) : आपने जो बोला है, आप उसका जवाब सुनने का सामर्थ्य रखिये। ...**(व्यवधान)**...

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: That is my style of speaking, Madam. I may not speak like Rajani ji sweetly and also keep on saying the things which I have already answered. My nature is different. ...*(Interruptions)*... I am sorry. All of us are made of different stuff. ...*(Interruptions)*... You may have to put up with it. We all are made of different stuff. Sir, Shri Derek has raised this issue about how families have a worry. I just want to say that GST has not increased the burden on families. I am saying this because the rates on some of the items before GST were far higher, and let me list out some of them. Tooth powder, 17 per cent pre-GST and now it is 12 per cent; hair oil, 29.3 per cent pre-GST and now it is 18 per cent under GST; toothpaste, 29.3 per cent pre-GST and now it is 18 per cent under GST; soap, 29.3 per cent pre-GST and now it is 18 per cent under GST; footwear, which is more than a thousand rupees, 21 per cent pre-GST and now it is 18 per cent under GST; paints, because I heard hon. Member, Jayant Chaudhary say we probably talk about tomatoes, potatoes, onions only, but items like *saria*, paints and varnishes, which are necessary for the ordinary citizen to make his house, 31.3 per cent pre-GST and now it is 18 per cent under GST; sugar, जो आम घर में उपयोग में आता है, 6 per cent pre-GST and now it is 5 per cent under GST; sweets, मिठाई, जो दुकान से लेते हैं , 7 per cent pre-GST and now it is 5 per cent under GST; washing machine, which has now become a common household thing, everybody wants some model or the other, 31.3 per cent pre-GST and now it is 18 per cent under GST; vacuum cleaners, 31.3 per cent pre-GST and now it is 18 per cent under GST; televisions up to the sizes of 32 inches, 31.3 per cent pre-GST and now it is 18 per cent under GST; LPG stove 21 per cent pre-GST and now it is 18 per cent under GST; LED lamps, which Piyush ji as Minister propagated that people should have LED lamps in their houses, 15 per cent under pre-GST and now it is 12 per cent under GST; kerosene pressure lantern, which we use in emergency in poor households which till today have not received electricity, 8 per cent pre-GST and now it is 5 per cent under GST. So, Derek

O'Brien, families which want to buy things today are buying them at far lesser rate under the GST. He is not here. I do not want to spend much time on it. But he also very simplistically, I am not criticizing, said that the US inflation is 9 per cent and India's inflation is 7 per cent. So, actually speaking, Indian currency should be appreciating in value. Sir, the currency of a country does not get determined just by this one inflation there versus inflation here. There are so many other factors which go into the fixation of the value of a currency. He obviously talked about a few other things which I am not getting into. But he said, "You quoted Raghuram Rajan in Lok Sabha, but he has also said something more"; many other Members also said. I have taken everything that Raghuram Rajan, former Governor, as an economist, said. Suppose he has given a political opinion. No, I have not referred to it. Let me be clear on that.

I will now make one quick word on cess, Sir. A lot of concern has been expressed by a lot of Members. What the Centre collects as cess and what it spends? I have said as a part of Question Hour as to how we spend money collected as cess. For instance, since 2013-14, 2014-15, 2015-16 till 2022-23 BE, Rs. 3.77 lakh crores of cess for health and education has been collected. What actually has been utilized against is Rs. 3.94 lakh crores. 'Utilized', meaning States have received it. They have started using it. They have spent it. And that amount is Rs. 3.94 lakh crores. So, nearly Rs. 17 thousand crores has been given as extra. Rs. 3.77 lakh crores has been collected and Rs. 3.94 lakh crores have been given. The States receive the cess as and when Centre collects. It doesn't collect and sit with it. It goes to the States promptly, and sometimes, much more than what has been collected goes to the States. This is something which I would like to say on what work do we do with the collected cess. It is not my data. The RBI's data show it very clearly. The total developmental expenditure incurred by the Modi Government in total between 2014 and 2022 was Rs.90.9 lakh crore. It is far higher than what is being spoken about. In contrast, only Rs.49.2 lakh crore were spent on developmental expenditure between 2004 and 2014. In ten years, it was Rs.49.2 lakh crore, whereas between 2014 and 2022, Rs.90.9 lakh crore is what we have spent on development. So the cess collected goes to the States. Developmental expenditure happens. That is the total we have spent.

Next is the expenditure incurred, again by the Modi Government, on food, fuel and fertilizer subsidies. Hon. Member Sushil Kumar Modi *ji* spoke about how global fertilizer prices have costed us huge amounts in importing it. But we have not passed

that burden on to the farmer and this is where the money has been spent. What is the amount? Sir, Rs.24.85 lakh crore have been spent on food, fuel and fertilizer subsidies and Rs.26.3 lakh crore have been spent on capital creation, whereas ten years of the UPA Government saw only Rs.13.9 lakh crore spent on subsidies of this nature. This was about cess collected and cess utilized.

Has GST reduced the flow of resources to the States? I will very quickly give the data which run between 2015-16, the period before the introduction of GST, and today. Total flow of funds to the States has increased substantially. It is an average of 14.8 per cent, close to 15 per cent, during the first five years of GST, despite the pandemic. The pandemic has not reduced it. We have given what was expected to be given and given slightly more as well whereas the average growth before the introduction of GST was only 9 per cent. So, it was nine per cent before GST, and after that, the States have received 14.8 per cent average resource growth in the States. So, cesses are going, devolution is happening, and GST revenues are reaching. States are receiving it. The misconception that cess is not being utilized by us for the States' benefit is not right.

Sir, I come to the last point of loan waivers and write-offs. Shri Sanjay Singh has raised it. There is some confusion. Write-offs are not waivers. Waivers are different from write-offs. This has been explained several times. But again it is politically convenient I suppose to say that you have written off which means it is waived. Banks' balance sheet gets cleaned up. But banks' duty remains there. I can say that in the Parliament I have answered questions about how much of Kingfisher owner Mallya's assets have been brought back to the bank. How much of Nirav Modi's assets are being confiscated by the ED and given to the banks. So banks' dues are getting repaid. Write-off means that the banks' balance sheets are getting cleared, but the banks pursue them and all the securities which are lying with them are being legally auctioned and the moneys are being given back to the banks. So this...*(Interruptions)*...

SHRI BINOY VISWAM: Sir, please. ...*(Interruptions)*...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): No. ...*(Interruptions)*... Let her reply. ...*(Interruptions)*... Let her reply. ...*(Interruptions)*... No. ...*(Interruptions)*... This is not the way. ...*(Interruptions)*... I allowed you once. ...*(Interruptions)*... Not all the time. ...*(Interruptions)*... It is not a running commentary. ...*(Interruptions)*... Madam, you continue. ...*(Interruptions)*...

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: Sir, last two-three points are there. I will finish with that. It is quite late. I halted when I said Fitment Committee which is the first layer and after that the GoM. The Fitment Committee paper was incomplete. In the Fitment Committee, the States which were represented were Maharashtra, Gujarat, Rajasthan, Haryana, Uttar Pradesh, Bihar, West Bengal, Tamil Nadu and Karnataka. So, all of them were in the Fitment Committee. From there, it was GoM in which I read out the States that were represented. After that, the GoM which is headed by the Chief Minister of Karnataka and after that is the GST Council. Nowhere was a difference of opinion.

Sir, now, I come to the last few points. Hon. Member, Mr. Vaiko, is here. He had a concern that ICUs are also being charged. There is no charge on ICUs. Also, it was said that GST has imposed taxation and because of that there is a lot of problem. No, even those items which were under the 28 per cent rate at the stage of introduction of GST -- there were more than 229 items -- gradually, after the introduction of GST, through various Council meetings, those 229 items have now come down to just 28 items which are in the 28 per cent rate. It means that items have been brought down from higher tax rates to lower tax rates. Therefore, I sequentially link to Mr. Raghav Chadha, the new Member. Obviously, they will not have any interest in bringing the GST corrections because it suits them. Hon. Members do correct me if I am caught in the wrong. When the inflation is high, the same commodity is bought at a higher rate and the GST earned out of it will be far higher and, therefore, the GST Council will not be in favour of reducing the rate. That was his case. I am sorry! That is one economics which I am learning today! If the rate is higher, people will stop buying it. If inflation is higher, consumption will come down. Naturally, my tax revenue will go down. Raghav Chadhaji, please, I want you to understand this. He is a new and young representative. Partially throwing economics at people does not help and it is also -- let me submit -- demeaning a body like GST Council that they will not want to reduce it to. Their own Delhi Finance Minister and now their own Punjab Finance Minister are also there. Is he suggesting that the Ministers will be happy if inflation goes up? That's wrong. I don't want cynicism to govern us. We are all capable of doing better. I think largely I have addressed most of the issues. Sir, I thank you very much for having given me this opportunity.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): Thank you, Minister. Now, Message from Lok Sabha. Secretary-General.